₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

अप्रैल 2023

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.-BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PT.-35

बिहार के भावी सम्राट चौधरी !

GSTIN : 10KEPD0123PIZP

उत्तर भारत का COOKIE MAKER, सीवान में पहली बार

आपके लिए लेकर आया है

Cookie का बेहतर श्रृंखला

PRATIK ENTERPRISES

राजपुर (रघुनाथपुर) में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा रस्क, बिस्कुट, बर्गर, मीठा ब्रेड, वंद, क्रीम रोल, पेटीज और बर्ड डे केक, पार्टी केक ग्राहकों के मनपसंद तैयार किया जाता है।

शुद्धता एवं स्वाद की 100% गारंटी

किसी भी अवसर पर
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

प्रतीक फुड कंपनी

प्रतीक इंटरप्राइजेज, प्रतीक पतंजलि

राजपुर, रघुनाथपुर, सीवान (बिहार)

-: सौजन्य से :-

ब्रजेश कुमार दुबे

Mob.-9065583882, 9801380138

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

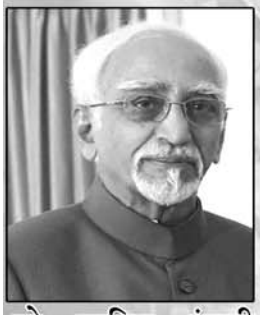

मो० हामिद अंसारी
01 अप्रैल 1937

अजय देवगन
02 अप्रैल 1969

प्रभु देवा
03 अप्रैल 1973

जया प्रदा
03 अप्रैल 1962

जितेन्द्र
07 अप्रैल 1942

रामगोपाल वर्मा
07 अप्रैल 1962

अल्लु अर्जुन
08 अप्रैल 1983

जया बच्चन
09 अप्रैल 1948

जयराम रमेश
09 अप्रैल 1954

मणिशंकर अय्यर
10 अप्रैल 1941

टैरेंस लेविस
10 अप्रैल 1975

स्व० सतीश कौशिक
13 अप्रैल 1956

मुकेश अंबानी
14 अप्रैल 1957

मंदिरा बेदी
15 अप्रैल 1972

लारा दत्ता
16 अप्रैल 1978

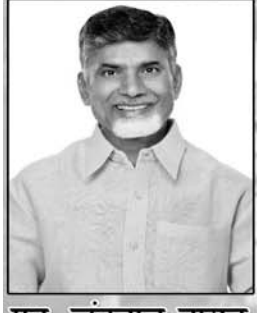

एन. चंद्रबाबू नायडू
20 अप्रैल 1950

चेतन भगत
22 अप्रैल 1974

मनोज बाजपेयी
23 अप्रैल 1969

सचिन तेन्दुलकर
24 अप्रैल 1973

आशिष नेहरा
29 अप्रैल 1979

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi-834001 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:-
editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

आओ खेलें माफी – माफी

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

माफी मांगना भी एक त्याग है और इससे माफी मांगने से अहंकार का नाश होता है लेकिन बिना कसूर के माफी मांगना मूर्खता एवं कमजोर की पहचान भी होती है। 23 अप्रैल 2023 को माफी नहीं मांगने की सजा देश के एक सांसद एवं गाँधी परिवार के यूवराज राहुल गाँधी को सांसद की सदस्यता गवां कर चुकानी पड़ी जबकि राहुल गाँधी पहले किसी मामले में मांग भी चुके हैं। राजनीति में जुबान फिसल जाने से बयान देने पर उस गलती की भारपायी माफी मांगकर की जा सकती है और देश में दर्जनों ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बयान के वक्त जुबान फिसल जाने की दुहाई देकर कठोर दंड से खुद को बचाया है माफी मांगकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरबिन्द केजरीवाल तो गलती पर गलती करके माफी मांगने वाला हथियार का हवाला देकर अपनी पद और प्रतिष्ठा को बचाया है लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक एक साल पहले प्रधानमंत्री के दौड़ में शामिल होने के पहले ही राहुल गाँधी आउट हो चुके हैं क्योंकि 2024 के चुनाव के नतीजे में राहुल गाँधी को देश की जनता क्या रिजल्ट देती लेकिन सत्तापक्ष में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आडाणी के मुद्दे से बेचैनी साफ-साफ दिखती है। विपक्ष में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के चयन में ही कूटनीति है और मोदी पर की गयी राहुल गाँधी द्वारा की गयी राजनीति टिप्पणी आओ खेलें माफी-माफी पर सिमट गयी और अब सदन सुचारू रूप से चलने लगा। माफी मंगवाने और माफी नहीं मांगने की अंदरूनी सच्चाई तो दोनों पक्ष जाने लेकिन राजनीति तो हो गई

'न खाऊंगा और न खाने दूंगा'' की दुहाई देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चतुराई को समझ पाना बहुत मुश्किल है और यही बात समझने की कोशिश में राहुल गाँधी ने अपनी सांसदी गवां दी और अब तो बंगला भी खाली करके जाना पड़ेगा। **'न खाऊंगा और न खाने दूंगा''** की बात को जिद् लेकर बैठे सांसद राहुल गाँधी को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि 20 हजार करोड़ रूपये गौतम अडाणी के कंपनी को क्यों दिया? जब आपने कहा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा और बार-बार जांच की मांग सदन के साथ जनता के बीच भी मांगने लगे और नतीजा यह हुआ की जांच बैठे बगैर राहुल गाँधी को माफी मांगने पर मजबूर किया जाने लगा। क्या 23 मार्च 2023 के पहले राहुल गाँधी माफी मांग लेते तो क्या उन्हें कोर्ट सजा नहीं सुनाती? क्या कोर्ट भी राहुल गाँधी का मांफीनामे का इंतजार कर रही थी? क्या सदन पहले से यह जानती थी की कोर्ट 23 मार्च को राहुल गाँधी को दोषी करार देते हुए 02 साल की सजा सुनायेगी और 24 मार्च को उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी? खैर आओ खेलें माफी-माफी के राजनीतिक खेल में फिलवक्त तो राहुल गाँधी बुरी तरह से फंस चुके हैं। ऐसे में इस कूटनीति की चाल किसने और कब चली यह तो आने वाला वक्त में सार्वजनिक होगा ही लेकिन जिस प्रकार की सजा कोर्ट ने राहुल गाँधी को सुनाई वैसे बयान तो आये दिन देश का कोई न कोई राजनेता सत्ता के लालच में देता रहता है और माफी मांगकर बच जाता है। इसका मतलब क्या इस प्रकार की बयानबाजी का एंटीसपेट्री बेल माफी है? **आओ खेलें माफी-माफी** के राजनीति में भाजपा का पलड़ा भारी है क्योंकि केन्द्र में सरकार रहने की वजह से सरकारी मशिनरी का जांच का आंच भी मोदी की कलाकारी का लोहा मनवाने को मजबूर कर देती है। कांग्रेस के राहुल गाँधी तो आप के अरबिन्द केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की दीदी ममता बनर्जी की कूटनीति का तोड़ भाजपा निकाल चुकी है। राहुल गाँधी और अरबिन्द केजरीवाल कई बार माफी मांग-मांगकर अपना कद पहले से ही कमजोर बना चुके हैं जिसकी वजह से भाजपा यह कहती है कि जब कई मामले में माफी मांगी जा सकती है तो एक और मामले में माफी से लज्जा क्यों? गलत बयानबाजी करके क्षमा मांगने की कला भी राजेनताओं के पास है और यही प्रमुख कारण है कि **आओ खेलें माफी-माफी** का दौर बड़ी चतुराई के साथ चलता है। कोई भगवान पर गंदी टिप्पणी करता है तो कोई धर्म पर, कोई जाति पर अभद्रता करने वाला बयान देता है तो कई केन्द्र एवं राज्य सरकार की जांच एजेंसी पर बेतुका बयान देता है और जब उस बयान में फंसता देखकर अविलम्ब माफी मांग ली जाती है। यह अलग बात है कि मानवता के मूल्यों को आधार बनाकर माफी कई दंड से बचा लेता है लेकिन उस समुदाय पर जो उस वक्त मानसिक प्रताड़ना होती है उसका कोई हिसाब नहीं होता। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे समय में राजनीतिक बयानों का घिनौना दौर चलेगा जिसको सोसल मीडिया पर बड़ी आसानी से सुना जा सकता है। क्या बिहार में 2014 के लोकसभा चुनाव, 2015 के विध नसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा एवं 2020 का विधानसभा चुनाव कोई भी दल और किसी भी दल का लोकप्रिय नेता अभद्र बयान देकर फिर से **आओ खेले माफी-माफी** का कूटनीति करके सरकार बना लेते हैं और जब वही बयान सोसल मीडिया पर देखते हैं तो कुर्सी का यही मांग है कहकर उस वक्त के बयान को राजनीतिक बयान कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले या यूं कहें की मोदी सरकार को मजबूती से टक्कर देने वाले आपस में ही भिड़ंत करते हैं और एक भी सशक्त उम्मीदवार मोदी का मुकाबला करने में सफल नहीं हो पाता और 2019 की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी के प्रचंड शक्ति के सामने सब बौना ही नजर आ रहे हैं जबकि लोकतंत्र खतरे में है की बात लगातार विपक्ष सदन में एवं सड़क पर कर रहा है वहीं भाजपा का एक ही मांग है माफी सिर्फ माफी लेकिन इस बार राहुल गाँधी ने भी जिद् ठान लिया कि सदस्यता जाये तो जाये लेकिन माफी इसबार नहीं मागूंगा। चुनाव में दागी लोगों को महत्व दिया जा रहा है और ऐसे लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि कौन सा बयान संसदीय है और कौन असंसदीय जिसका व्यापक असर सरकार एवं समाज पर पड़ता है और बाद में **आओ खेले माफी-माफी** का खेल शुरू हो जाता है। मीडिया के डिबेट के कार्यक्रम में भी एंकर भी नेताओं से आओ खेले माफी-माफी का बयानबाजी का मुद्दा उठाते हैं और कभी कभार यह भी माफी मांगने पर मजबूर कर देते हैं लेकिन सवाल यह उठता है कि विध्वंसक बयानबाजी करने वाले को दंड देने के बजाय सिर्फ माफी मांगने से दोषमुक्त कैसे हो सकता है? जिस प्रकार राहुल गाँधी को सदस्यता गवानी पड़ी उसी प्रकार अरबिन्द केजरीवाल एवं ममता बनर्जी की सदस्यता जायेगी या फिर आओ खेलें माफी-माफी का दौर चलता रहेगा?

मार्च 2023

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

हमारा पता है :-

द्वारा:- ब्रजेश मिश्र

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल

kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

एनकाउंटर

संपादक जी,

केवल सच पत्रिका का संपादकीय पढ़कर मन को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि संपादकीय आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे पर आधारित होती है। मार्च 2023 अंक का संपादकीय ''**एनकाउंटर यूपी एवं बिहार**'' में जिस प्रकार का राजनीतिक एनकाउंटर आपने किया है वह काबिले तारिफ है। बिहार में अपराधी को दौड़ाने की बात कहने वाली बिहार पुलिस की सच्चाई क्या है यह भी आपने लेख में रखा तो यूपी पुलिस का एनकाउंटर का सच भी आवाम के बीच रखा है। निष्पक्ष लगा संपादकीय।

✦ **शेखर जायसवाल, देशबंधु मार्ग, नई दिल्ली**

खत्म हो रहा है

ब्रजेश जी,

केवल सच, पत्रिका का मैं नियमित पाठक हूं और इसकी बिना लाग लपेट की खबरें मुझे बहुत अच्छी लगती है। पत्रिका के संयुक्त संपादक अमित कुमार की खबर ''**खत्म हो रहा है नीतीश का इकबाल**'' में राजनीतिक बिन्दुओं पर बहुत ही स्तरीय एवं सिलसिलेवार ढ़ंग से पाठकों के समक्ष रखा है। बिहार की भूमि पर राजनीति पर जिस प्रकार का संक्रमण का संकट दिख रहा है तथा सिर्फ सत्ता प्राप्ति का ही उद्देश्य राजनीति रह जाये तो उस राज्य की स्थिति का अवलोकन हो सकता है। सटीक खबर है।

✦ **कुमुद कुमार रजक, घंटा घर, भागलपुर**

खुलासा

मिश्रा जी,

मार्च 2023 अंक में केवल सच, पत्रिका ने **'शौर्य हत्याकांड का हुआ खुलासा'** खबर में पत्रकार ओमप्रकाश ने बेवाकी के साथ पुलिस के सार्थक प्रयास को मजबूती के साथ लिखा है। एक छोटे बच्चे की निर्मम हत्या से राँची की जनता काफी आक्रोश में थी और पुलिस की साख पर दाग लग रहा था लेकिन पुलिस भी शौर्य हत्याकांड को प्राथमिकता में रखते हुए मामले का उद्भेदन करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा। जिस प्रकार पुलिस ने तत्परता दिखायी कोर्ट से भी इन दुष्टों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी घटना पर विराम लग सके।

✦ **सरीन मरांडी, कांटाटोली चौक, राँची**

बढ़ते कदम

मिश्रा जी,

केवल सच पत्रिका के मार्च 2023 अंक में सागर कुमार एवं के.के. सिंह की प्रकाशित खबर ''**जन-जन की तरफ बढ़ते कदम**'' में बहुत कुछ इशारों में लिखा है। 1912 में बंगाल से कटकर अस्तित्व में आया बिहार पुलिस की बदलती स्थिति बिहार दिवस 2023 के अवसर पर देखने को मिला है। कई पुलिस पदाधिकारियों की टिप्पणी वास्तव में बिहार पुलिस की बदलती मानसिकता का परिचय देती दिखती है। पुलिस बल की संख्या में इजाफा एवं नई-नई तकनीक से अपराध पर नियंत्रण का प्रयास के कारण ही पुलिस की साख भी बढ़ी है। बढ़िया खबर लगा।

✦ **अभिषेक सिंह, बेउर, पटना**

भारत का डंका

संपादक जी,

ललन सिंह की खबर बिना लाग लपेट की होती है। मार्च 2023 अंक में इनकी खबर ''**भविष्य में भारत के मजबूती का डंका**'' में रक्षा बजट भी सरकार ने कर दिया है ताकि देश की सुरक्षा में धन का आभाव नहीं दिखे। सैनिकों का विश्वास अब सरकार पर बढ़ा है तथा सभी सुरक्षा एजेंसियां भी अपना कार्य को बेहतरीन से बेहतरीन देने में जुटे हैं, वही पड़ोसी देश पाकिस्तान सहित अन्य कई देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी समीक्षा की है। ललन सिंह की खबर वास्तव में देशहित में होती है और सकारात्मक विचारों को प्राथमिकता से लिखते हैं।

✦ **कौटिल्य प्रसाद, बहू बाजार, कोलकाता**

बंटाघार

संपादक जी,

शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला ने मार्च 2023 अंक में बिहार प्रदेश में नीजि विद्यालयों सहित सरकारी स्कूलों की बदहाली पर सटीक खबर ''**शिक्षा का बाजारीकरण**'' सटीक व उपयोगी खबर पाठकों के समक्ष रखी है कि किस प्रकार सरकार शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर शिक्षा का बाजार बना रही है। इस खबर में शिक्षा मंत्री के रामचरित्र मानस पर दिये गये बयान को भी प्रमुखता से लिखा है। दूसरी खबर कोचिंग संस्थान में हो रहे बाजारीकरण पर भी प्रहार किया है, जिससे छात्र कोचिंग संस्थानों की सच्चाई जान सकेंगे। जानकारीप्रद खबर।

✦ **मनोज शर्मा, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर**

अन्दर के पन्नों में

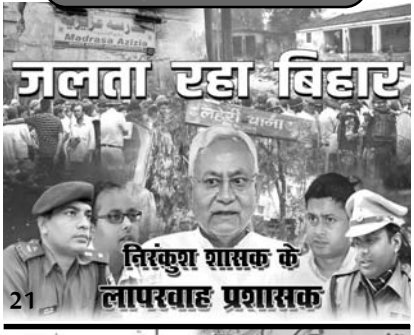

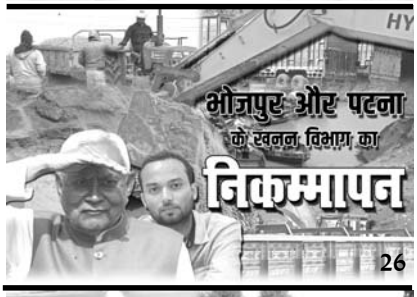

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 17, | अंक:- 203, | माह:- अप्रैल 2023, | मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

स्व० गोपाल मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

ललन कुमार प्रसाद 9334107607

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उपसंपादक

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 8603069137

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 9430243587, 9334813587

आलोक कुमार सिंह 8409746883

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

कृष्ण कुमार सिंह 6209194719, 7909077239

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

प्रदीप कुमार सिन्हा 9472589853, 6204674225

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426.

.

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:-	गौरव कुमार	9472400626
(ग्रा०)	:-		
बाढ़	:-		
भोजपुर	:-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
	:-		
गया (श०)	:-	सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:-		
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-		
	:-		
नवादा	:-	अमित कुमार	9934706928
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-		
बेगूसराय	:-	निलेश कुमार	9113384406
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-		
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:-	.	
	:-		
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-	सुरेश प्रसाद गुप्ता	9939817141
	:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, e ditor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636-9631490205

झारखण्ड सहायक संपादक

ब्रजेश मिश्रा 7654122344-7979769647

अभिजीत दीप 7004274675-9430192929

संयुक्त संपादक

.....

.....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343-8863893672

.....

.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	7903856569
साहेबगंज	:- अनंत मोहन यादव	9546624444
खूँटी	:-	
जमशेदपुर	:- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता	9304824724
हजारीबाग	:-	
जामताड़ा	:-	
दुमका	:-	
देवघर	:-	
धनबाद	:-	
बोकारो	:-	
रामगढ़	:-	
चाईबासा	:-	
कोडरमा	:-	
गिरीडीह	:-	
चतरा	:- धीरज कुमार	9939149331
लातेहार	:-	
गोड्डा	:-	
गुमला	:-	
पलामू	:-	
गढ़वा	:-	
पाकुड़	:-	
सरायकेला	:-	
सिमडेगा	:-	
लोहरदगा	:-	

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

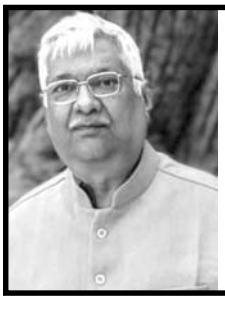

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क

भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C

08877663300

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सागर कुमार	9155378519, 8863014673
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
मणिभूषण तिवारी	9693498852
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

सिर पर भगवा पगड़ी, गले में भगवा गमछा, ललाट पर तीलक लगाकर बेवाकी से दहाड़ते बिहार के योगी 'सम्राट चौधरी' मात्र पांच वर्षों में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बना दिये गये। मंथन भरा विषय है कि बिहार भाजपा में वर्षों से सेवा दे रहे दिग्गज नेताओं को छोड़कर आखिर सम्राट चौधरी को ही प्रदेश का कमान संभालने का नेतृत्व क्यों मिला? तो जवाब होगा कि एक तो सम्राट उन जाति से आते हैं जिनका बिहार में स्थान दूसरे नंबर पर है। बीते चुनावों पर नजर दौड़ायें तो देखेंगे कि कुशवाहा वोटरों का झुकाव भाजपा के प्रति बढ़ा है और चूकि सम्राट चौधरी उन नेताओं में शुमार रखने वाले शकुनी चौधरी के बेटे हैं जिनका प्रभाव अपनी जाति पर हमेशा से रहा है। वह आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी जाति के वोट भाजपा में ला सकते हैं। दूसरा कारण सरकार को घेरने में उनके आक्रामक रवैये से केंद्रीय कमिटि खुश है। माना यह भी जा रहा है कि आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी बीजेपी से मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं और सूत्रों की माने तो केंद्रीय कमिटि भी उन पर दांव लगाने को भी तैयार है। एक बात और है कि अब बिहार की जनता सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की मांग कर रही है। जिस प्रकार बिहार में रामनवमी पर जो दंगे हुए उससे हिंदुओं में खासा डर बैठ गया है। दबी जुबां से जनता अब यह कह रही है कि जब से मुख्यमंत्री नयी सरकार बनाकर आये हैं सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। हत्या, बलात्कार सहित अन्य जघन्य अपराधों पर सरकार की पुलिस व्यवस्था लगाम लगाने में असमर्थ है। इसे देखकर बिहार में योगी-2 की मांग होने लगी है। गौरतलब हो कि प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने के बाद राजधानी के कई जगहों पर 'बिहार के योगी सम्राट चौधरी' वाले पोस्टर देखे गये। इसके बाद से राजनीति के गलियारे में आवाज उठने लगी है कि क्या बिहार के भावी सम्राट होंगे चौधरी? इन तमाम विषयों पर प्रस्तुत है पत्रिका के संयुक्त संपादक अमित कुमार की विशेष रिपोर्ट :-

सम्राट अशोक कुशवाहा जाति से आते थे, इस बात को स्थापित करने की कोशिशों के साथ-साथ ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी था। पटना के बापू सभागार में हुए उस शक्ति प्रदर्शन के नतीजे 11 महीने बाद सामने है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरूण सिंह की ओर से जारी पत्र में लिखा है-ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और बिहार सरकार में तीन बार मंत्री रह चुके हैं। इनके और इनके पिता पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी की बिहार में काफी राजनीतिक पैठ मानी जाती है। सम्राट चौधरी उस समय विवादों में आए थे, जब लालू यादव की कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री बन गए थे। फिर लंबे बवाल के बाद उन्हें मंत्री पद से हटना पड़ा था। एनडीए की सरकार टूटने के बाद बीजेपी लगातार सम्राट चौधरी को प्रमोट कर रही है। सबसे पहले इन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़े और प्रदेश में हमारी सरकार बने, इसकी रणनीति पर काम करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन्हें मंच संचालन की जिम्मेदारी दी गई। अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सम्राट चौधरी पिछले कई दिनों से हर मुद्दे पर सीधे नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। उन्होंने शपथ ली है कि जब तक वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल नहीं कर देंगे। तब तक वो पगड़ी बांधे रखेंगे। सितंबर में संजय जायसवाल का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन लगातार 2 विधानसभा उपचुनाव और अमित शाह के दौरे के कारण ये नियुक्ति टल रही थी।

बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को नया अध्यक्ष बनाया। माना जा रहा है कि चौधरी को अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने जहां युवा को नेतृत्व का दायित्व सौंपा है, वहीं लव कुश समीकरण में सेंध लगाकर जदयू के वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। इसमें कोई शक नही कि कुशवाहा समाज में सम्राट चौधरी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि 2005 में नीतीश को सत्ता तक पहुंचाने में लव कुश (कोइरी-कुर्मी) काफी मददगार रही थी। इस लिहाज से 5 साल में ही सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके पीछे उनका कुशवाहा समाज से आना, बड़ा कारण है। उनके पिता शकुनी चौधरी कुशवाहा समाज के बड़े नेता रहे हैं। कुशवाहा-कुर्मी समाज को साधने के लिए सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए तुरूप का पत्ता साबित होंगे। बिहार में कुशवाहा-कुर्मी समाज की आबादी 11 फीसदी है। ऐसे में सम्राट को भाजपा पूरे बिहार में घुमाएगी। 54 साल के सम्राट के एग्रेशन को देखते हुए भी भाजपा ने ये जिम्मेदारी दी है। सनद् रहे कि गत् उपचुनाव में कुशवाहा ने बीजेपी का दामन कुछ ज्यादा ही पकड़ा था। इस वजह से जेडीयू अपने कुशवाहा उम्मीदवार को कुढ़नी विधान सभा से नहीं जीत दिला पाई थी। बीजेपी के रणनीतिकार तब से कुशवाहा को लेकर बड़ा राजनीतिक खेल करना चाह रहे थे। आज सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान थमा कर बीजेपी ने जेडीयू को शह देने की पहली बाजी चल दी है। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही बीजेपी ने पिछड़ों की राजनीति का दामन पकड़ लिया है। वैसे भी पिछड़ी जाति में यादव

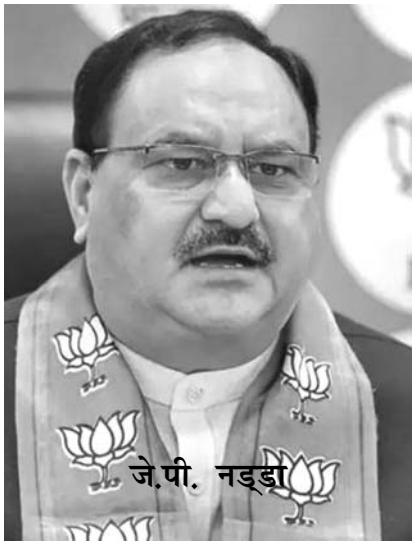

के बाद सबसे ज्यादा वोट अगर किसी जाति की है तो वह है कुशवाहा की। लगभग 7 से 9 प्रतिशत वोटों का आधार रखने वाला कुशवाहा अब लव की छतरी तले राजनीति को अंजाम भी देना चाहती। कम वोट बैंक के बाबजूद अब तक कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश कुमार की अगुआई में राजनीति करने को बाध्य थे। अब उनसे पगहा छुड़ाकर कुशवाहा अपना एक अलग नेतृत्व की भूमिका की तलाश में है। बीजेपी ने इस नब्ज को पकड़ राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की होगी। वही राजनीतिक गलियारों की माने तो बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी की जोड़ी के सहयोग से जेडीयू की राजनीति को अलविदा करने की राह पर यह

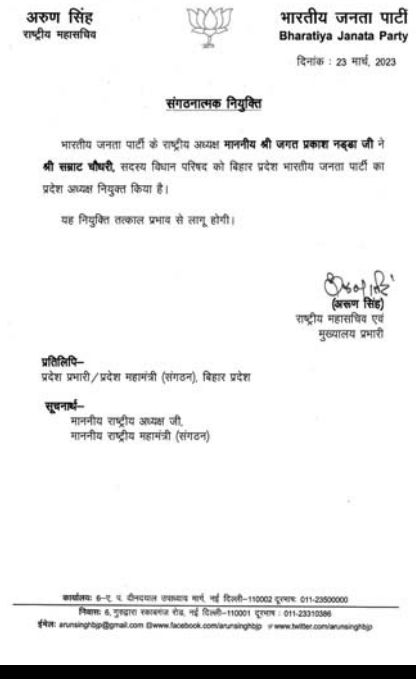

अरुण सिंह
राष्ट्रीय महासचिव

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

दिनांक : 23 मार्च, 2023

संगठनात्मक नियुक्ति

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष **माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी** ने **श्री सम्राट चौधरी**, सदस्य विधान परिषद को बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।

यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(अरुण सिंह)
राष्ट्रीय महासचिव एवं
मुख्यालय प्रभारी

प्रतिलिपि–
प्रदेश प्रभारी/प्रदेश महामंत्री (संगठन), बिहार प्रदेश

सूचनार्थ–
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी,
माननीय राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन)

कार्यालय: 6-ए, प. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 दूरभाष: 011-23500000
निवास: 6, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : 011-23310386
ईमेल: arunsinghbjp@gmail.com @www.facebook.com/arunsinghbjp www.twitter.com/arunsinghbjp

सम्राट चौधरी

कदम बढ़ा रहा है। नॉर्थ बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और मध्य और दक्षिण बिहार में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की राजनीति के विरुद्ध गोलबंदी कर 2 प्रतिशत की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार की घेराबंदी कर बीजेपी की नई राजनीति का सूत्रपात करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी की नियुक्ति नीतीश खेमे से उसी जाति के एक महत्वपूर्ण नेता उपेंद्र कुशवाहा के दलबदल के मद्देनजर हुई है। इसका उद्देश्य कुशवाहा समाज के बीच संख्यात्मक रूप से कमजोर कुर्मी जाति के लिए दूसरी भूमिका निभाने को लेकर पहले से मौजूद नाराजगी को भड़काना और इस मुद्दे को भुनाना है। बीजेपी के इस कदम से नीतीश कुमार की जदयू को नुकसान हो सकता है। वही उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने जेडीयू से नाता तोड़ कर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई है, जेडीयू से नाता टूटने के बाद ही बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद ये कयास लग रहे थे कि उनका बीजेपी से गठजोड़ हो सकता है और इस फैसले के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी में बहुत सीमित समझौता हो सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पुरानी पार्टी आरएलएसपी को बीजेपी ने तीन सीटें दी थी और पार्टी जीती भी थी, लेकिन सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब उनकी जगह सीमित हो गई है। स्पष्ट है कि सम्राट चौधरी की जाति के जरिए बिहार बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को साधने की कोशिश में है।

16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार 1990 से सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीतिक पारी राजद से शुरू की थी। 1997 में राजद के गठन के समय जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसकी तीन सदस्यीय कमेटी में से एक सदस्य चौधरी होने चितरंजन गगन थे। शकुनी राजनीति में सेना से रिटायर के बाद आए थे, लेकिन सम्राट बहुत ही कम उम्र में राजनीति में सक्रिय रहने लगे थे। वो बहुत कम उम्र में विधायक और मंत्री भी बने। जिसकी बाकायदा समता पार्टी से एमएलसी रहे पीके सिन्हा ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी। इसके बाद 19 मई 1999 को बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद की शपथ ली। 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और निर्वाचित हुए। साल 2010 में विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बनाए गए थे। 2 जून 2014 को शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद बीजेपी में शामिल हुए और साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। वर्तमान में सम्राट चौधरी विधान परिषद में विरोधी दल के नेता है। सनद् रहे कि सम्राट चौधरी की अपनी राजनैतिक विरासत बहुत समृद्ध है। वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं, जो समता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं. शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार है और वो खुद भी विधायक और सांसद रहे। जेडीयू में रहते हुए साल 2014 में शकुनी चौधरी का नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान सुर्खियों में आया था, जो उन्होने भागलपुर में चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी का प्रवेश सक्रिय राजनीति में 1990 में हुआ। वही इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि 1995 में उन्हें एक राजनीतिक मामले में 89 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। 1999 में

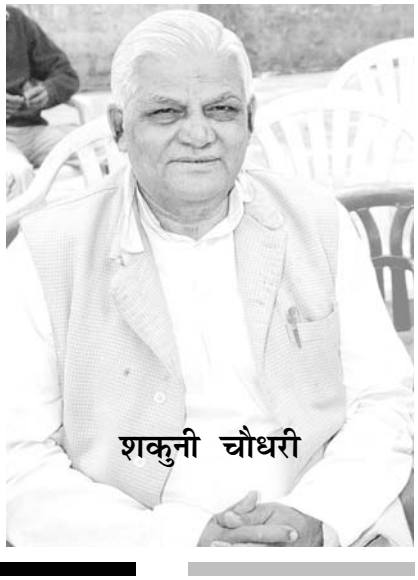
शकुनी चौधरी

लालू प्रसाद यादव

नीतीश कुमार

जीतनराम मांझी

राबड़ी देवी सरकार में वो कृषि मंत्री बने। लेकिन उनकी कम उम्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ। साल 2000 और 2010 में वो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। कभी लालू प्रसाद के लाडले रहे, सम्राट चौधरी साल 2014 में राजद छोड़कर जदयू में शामिल हुए थे। तब वह नीतीश कुमार के बेहद खास माने जा रहे थे। इतने खास कि पार्टी में शामिल होते ही सम्राट चौधरी को पहले एमएलसी बनाया गया और फिर नगर विकास विभाग मंत्री, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और जीतन राम मांझी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना दिया। 2015 तक जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार के बीच जबरदस्त दूरियां दिखने लगी और फिर जदयू दो खेमों में बंट गई। सम्राट चौधरी तब जीतनराम मांझी मंत्रिमंडल में मंत्री थे और उन्होंने मांझी का साथ देना शुरू कर दिया। सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करने का सिलसिला यहीं से शुरू हो गया। कई सालों तक मांझी खेमे का हिस्सा रहने के बाद सम्राट चौधरी ने 2018 में भाजपा जॉइन कर लिया। तब भाजपा विपक्ष में थी और बिहार में जदयू-राजद की सरकार थी। सम्राट चौधरी की भाजपा में एंट्री होने की 2 वजहें थीं, पहला कि कुशवाहा वोट और दूसरा उनका नीतीश विरोधी होना। भाजपा ने पहले उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया और फिर 2021 में एमएलसी और मंत्री।

गौरतलब है कि बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि 'मेरी प्राथमिकता पार्टी को विस्तार देते हुए बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना है, साथ ही हम अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करेंगे'। बता दें कि सम्राट चौधरी भाजपा की तरफ से जदयू और नीतीश कुमार पर बयानी हमले करते रहते हैं। वे अपने बयानों से नीतीश कुमार की उस राष्ट्रीय नेता की छवि को तोड़ते हैं, जिसे बनाने की कवायद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी करती रहती है। 54 साल के सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। सम्राट चौधरी का 2021 में भाजपा कोटे से नीतीश कैबिनेट में शामिल होना भी नीतीश कुमार के लिए बड़ा धक्का है। इससे पहले की भाजपा-जदयू सरकारों में वही चेहरे कैबिनेट में शामिल हुए हैं, जो नीतीश कुमार की पसंद के रहे थे। चाहे वह नेता जदयू का हो या भाजपा का। 2020 का परिणाम जदयू को सीटों के मामले में बेहद कमजोर कर दिया। लिहाजा, नीतीश कुमार उस तरह से मंत्रियों को चुनने में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए और यही वजह रही कि सम्राट चौधरी बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री बन गए। सम्राट, भाजपा में उन गिने-चुने नेताओं में से एक हैं, जो दूसरी पार्टी से आने के बावजूद इतनी जल्दी मंत्री पद तक पहुंच गए। पार्टी में उनकी तरक्की की बड़ी वजह उनका नीतीश विरोधी होना ही है।

बताते चले कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल सितंबर 2022 में ही पूरा हो गया था। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद से ही बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर कई नाम राजनैतिक गलियारों में थे। लेकिन बीजेपी ने अपना दांव 54 साल के सम्राट चौधरी पर लगाया है, जो एक नौजवान नेता है। हालांकि सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने की दो वजहें हैं-पहली वजह उनकी जाति, जो कोइरी है और दूसरी वजह उनका नौजवान और आक्रामक होना। बीजेपी अब चाहती है कि उनको सीएम के तौरपर

संजय कुमार जायसवाल

तेजस्वी के खिलाफ प्रोजेक्ट किया जाए। उनकी उम्र और जाति दोनों उनके साथ है। बीजेपी के इस फैसले को जातीय नजरिए से देखें, तो ओबीसी वोट बैंक में यादवों के बाद सबसे ज्यादा संख्या बल कुर्मी-कोइरी का है। यादवों की आबादी तकरीबन 15 फीसदी है, तो कुर्मी-कोइरी की सात फीसदी के करीब। कुर्मी-कोइरी में भी कोइरी की आबादी ज्यादा है। ऐसे में आरजेडी के यादव वोट बैंक का मुकाबला अगर किसी भी पार्टी को करना है तो उसमें कुर्मी-कोइरी वोट बैंक अहम भूमिका निभा सकता है। इसी वोट बैंक पर नजर होने के चलते ही राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साल 2022 में अशोक जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कहा था-'अगले साल ये कार्यक्रम गांधी मैदान में होना चाहिए, जिसमें कुशवाहा समाज के एक लाख से ज्यादा लोग इकठ्ठा हो'। लव-कुश (कुर्मी-कोइरी) भगवान राम से अलग नहीं किए जा सकते। बिहार में खेती से जुड़ी ये जाति इतनी महत्वपूर्ण है कि खुद नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 1994 में लव-कुश सम्मेलन किया था। नीतीश खुद कुर्मी जाति से आते हैं और इस कुर्मी-कोइरी के एकमुश्त वोट करने का राजनैतिक मतलब समझते है। कहा भी जाता है कि पिछले इस वोट बैंक पर नीतीश कुमार का एकाधिकार है। नीतीश लंबे समय तक इसके बड़े नेता बने रहे हैं, लेकिन अब भाजपा इसी वोटबैंक में सेंध लगाने में जुटी है। हालांकि नीतीश कुमार भी इस वोटबैंक को किसी हाल में मजबूत रखना चाहते हैं। कुशवाहा समाज से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज होकर अलग पार्टी बना ली है। इसके बाद भाजपा ने भी सम्राट

नीतीश कुमार

चौधरी के बहाने लव-कुश समीकरण को तोड़ने की कोशिश की है। नीतीश कुमार किसी हाल में कुशवाहा, कोइरी के वोट बैंक को छिटकना नहीं चाहते। यही कारण माना जा रहा है कि हाल

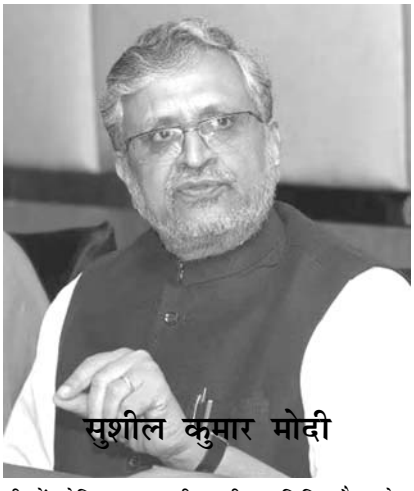

सुशील कुमार मोदी

ही में घोषित जदयू की राष्ट्रीय समिति और प्रदेश समिति में कुशवाहा नेताओं की भरमार दिख रही है। सम्राट चौधरी हाल के दिनों पर नीतीश कुमार पर सियासी रूप से हमलावर हैं और पार्टी के किए गए कार्यों को भी प्रभावी रूप से रखते हैं।

बहरहाल, उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद जदयू को यह कमजोरी दिख रही है। कहा जाता है कि पिछले दिनों प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनावों में भी कुशवाहा वोट का जदयू से मोहभंग होता दिखा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए सियासत के शतरंज में ऐसी चाल चली है, जिससे अपनी पार्टी को मजबूत किया जा सके और जदयू को कमजोर। जदयू ने कार्यकारिणी घोषित कर आगामी लोकसभा की चुनावी तैयारी की यह पहली बानगी प्रस्तुत की है। जदयू की इस नई कार्यकारिणी पर उपेंद्र कुशवाहा के जाने का भय दिखता है। लव-कुश समीकरण को मजबूत कर जदयू का यह प्रयास एक डैमेज कंट्रोल की

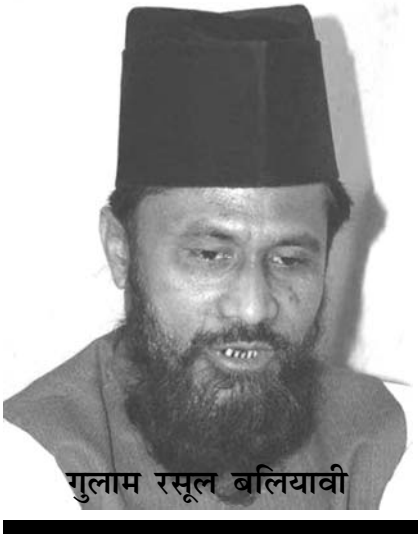

गुलाम रसूल बलियावी

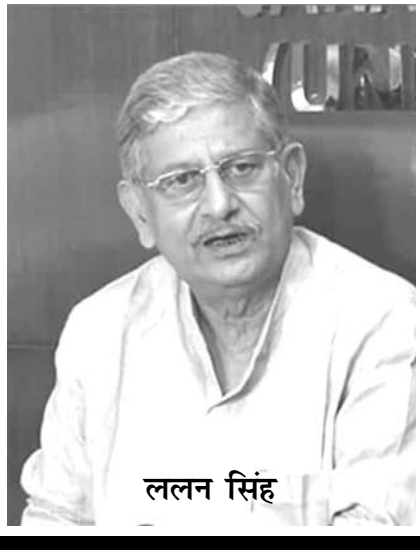

ललन सिंह

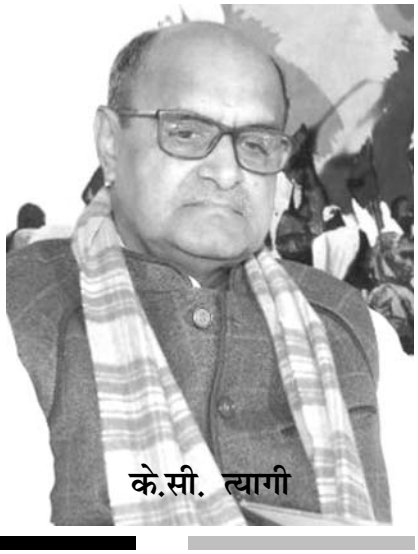

के.सी. त्यागी

उमेश कुशवाहा

तरह दिखता है जहां कुशवाहा नेताओं की तो भरमार है। यह चाहे राष्ट्रीय कमिटी हो या प्रदेश की कमिटी, कुशवाहा जाति से इस कार्यकारिणी में काफी लोग शामिल है। लव-कुश समीकरण के टूटने के साथ इस कार्यकारिणी से के.सी. त्यागी का जाना और गुलाम रसूल बलियावी का महत्वपूर्ण पद पर काबिज होना भी जेडीयू की लीक से हट कर दिख रहा है। के.सी. त्यागी का जाना ठीक वैसे ही है, जैसे एक म्यान में दो तलवार का नहीं रहना। के.सी. त्यागी ने तो आरसीपी सिंह के साथ भी कार्य करना स्वीकार नहीं किया था, लेकिन दवाब में वे जुड़े रहे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार ललन सिंह के नेतृत्व में काम करने से उन्होंने साफ इंकार कर दिया है। अब जेडीयू के पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 32 सदस्यीय राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा की है। इसमें कुशवाहा जाति से संतोष कुशवाहा, रामसेवक सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा और रामकुमार शर्मा को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके साथ ही सांसद आलोक सुमन पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं। प्रदेश कमिटी में अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के अलावा प्रदेश महासचिव के लिए दर्जनों नामों की सूचि है। वही प्रदेश सचिव के पद पर भी कुशवाहा जाति के लोग विराजमान हैं। यानी प्रदेश महासचिव और सचिव के पद पर कुल 24 पद कुशवाहा के पास। यूं कहे कि बिहार की राजनीति इन दिनों कुशवाहा वोट के इर्द गिर्द घूम रही है तो गलत नहीं होगा। जेडीयू ने प्रदेश अध्यक्ष सहित कुल 24 लोगों को जंबो कमिटी में शामिल कर अपना पत्ता खोल दिया। अब चूंकि लोहा को लोहा ही काटता है इस तर्ज पर बीजेपी ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाकर अपनी रणनीति का खुलासा कर भी दिया है। दरअसल, नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनावी युद्ध को संतुलित करने में सबसे कारगर वोट कुशवाहा का है। पिछड़ी जाति में यादव के बाद सबसे ज्यादा वोट कुशवाहा का है। यह लगभग 6 से 7 प्रतिशत के आसपास है। भाजपा की नजर कुशवाहा वोट पर है। यही वजह है कि भाजपा ने विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट कर कुशवाहा वोट को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद जदयू को यह कमजोरी दिख भी रही है। खास कर राज्य में हुए 2020 का विधान सभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव। यहां तक कि कुछ ही महीने पहले हुए तीन उपचुनावों में भी कुशवाहा के वोट बैंक का असर दिखा। कुशवाहा वोट भाजपा की तरफ ज्यादा जाता दिखा। कुशवाहा के भीतर भाजपा के बढ़ते प्रभाव को देख कर ही नीतीश कुमार इस जाति पर कुछ ज्यादा मेहरबान हुए और संगठन में कुशवाहा को ज्यादा हिस्सेदारी मिली है।

बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सम्राट चौधरी को तोहफे में गुलाब की फूलों का गुलदस्ता और श्रीमदभगवदगीता दिया। इसके साथ ही माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी से आगामी चुनावों को लेकर भी चर्चा की। आगे के लिए पीएम मोदी से टिप्स भी मिला। नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा किए जाने के बाद सम्राट चौधरी ने विधिवत बिहार बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभाली। वही दूसरी तरफ राजधानी पटना की सड़कें पोस्टरों से पटी हुई नजर आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया है। पोस्टर पर लिखा है कि बिहार का योगी आ गया है और इस पर चौधरी की एक बड़ी तस्वीर लगी है।

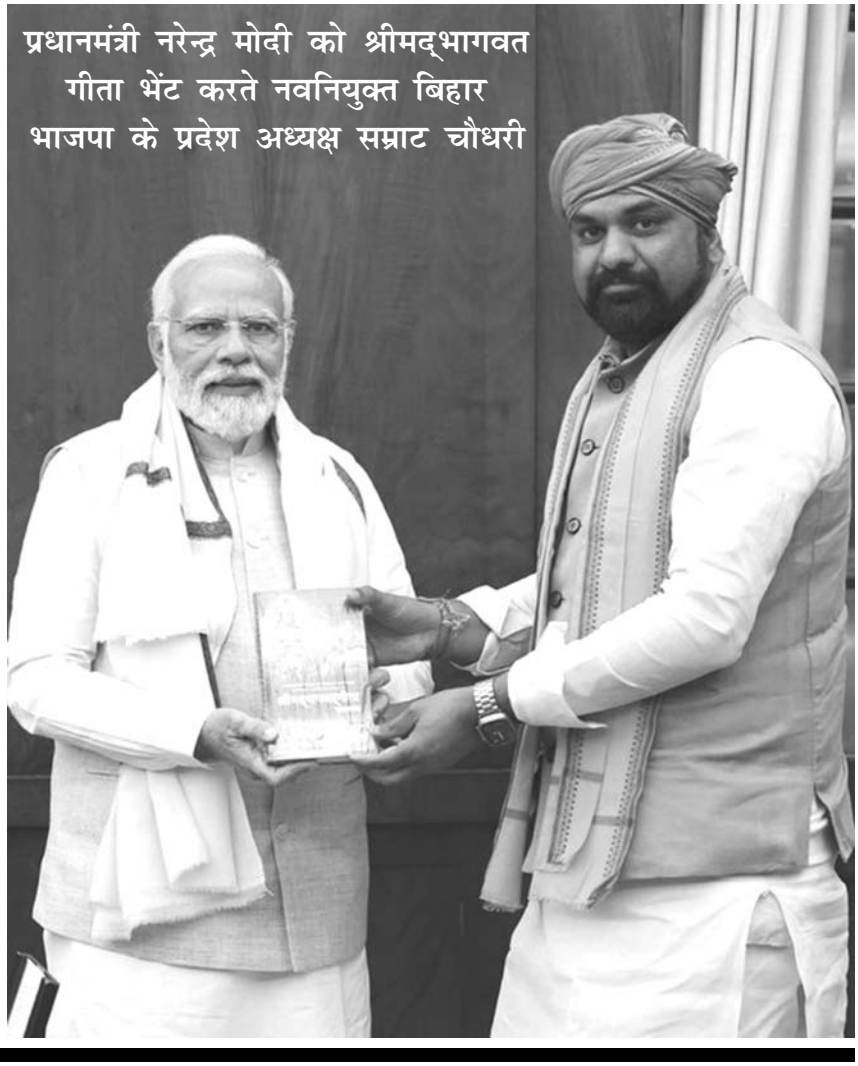

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को श्रीमद्भागवत गीता भेंट करते नवनियुक्त बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी

सीपी जोशी को राजस्थान तो वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली और मनमोहन सामल को ओडिसा का मिला प्रभार

चार राज्यों में अध्यक्षों का बदलाव

बीजेपी की क्या है चुनावी रणनीति?

सी.पी. जोशी

वीरेंद्र सचदेवा

मनमोहन सामल

प्रदेश अध्यक्षों की सूचि में बीजेपी ने बिहार में कुशवाहा समाज के नेता सम्राट चौधरी के अलावा राजस्थान में ब्राह्मण चेहरे सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया है, जहां इस साल चुनाव होना है। वहीं बीजेपी ने ओडिशा में मनमोहन सामल और दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा को अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन नए चेहरों को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पहले बात करते हैं राजस्थान में ब्राह्मण चेहरे सीपी जोशी की तो बता दें कि बीजेपी ने राजस्थान में सतीश पूनिया को हटाकर चित्तौड़गढ़ से दूसरी बार सांसद बने सीपी जोशी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ज्ञात हो कि पूनिया के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन इस साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उन्हें हटाकर नया सियासी दांव चला है। सीपी जोशी ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा हैं। उन्हें गैर विवादास्पद चेहरा माना जाता है। बीजेपी ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है। इसके अलावा संगठन में चल रही खींचतान को भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। सीपी जोशी की आरएसएस में अच्छी पकड़ है। जोशी चित्तौड़गढ़ में पहली बार 2014 में फिर 2019 में लोकसभा चुनाव जीते। जोशी बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें संगठन का भी अनुभव है। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने के इरादे से इनकी नियुक्ति की गई है। राजस्थान की दो प्रमुख जातियां राजपूत और जाट अक्सर राजनीतिक स्पेक्ट्रम के अलग-अलग छोर पर रहती हैं। ब्राह्मण चेहरे की घोषणा करके बीच का रास्ता निकालने का प्रयास भाजपा ने किया है। दरअसल, सीपी जोशी हाल ही में हुए ब्राह्मण पंचायत में शामिल हुए थे। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रदेश के ब्राह्मण समाज को साधने के लिए ये अहम फैसला लिया है। सीपी जोशी राजस्थान की चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने साल 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद पार्टी ने दोबारा उन पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया। दूसरी तरफ सतीश पूनियां का तीन साल का कार्यकाल पूरा हो गया। सतीश पूनिया ने 15 सितंबर 2019 को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का पद संभाला था। पूनिया साढ़े तीन साल तक इस पद पर रहे। बीजेपी ने कई बार नए चेहरों को प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर मौका देकर चौंकाया है। बीजेपी राज में अशोक परनामी की जगह चुनावी साल में मदन लाल सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर चौंकाया था। सैनी के देहांत के बाद सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी गई थी। केंद्र में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने हर बार नए चेहरों को मौका देकर चौंकाने वाला ट्रेंड बरकरार रखा है। सीपी जोशी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना भाजपा की खेमेबाजी पर पानी डालने के लिए भी अहम है। अब तक प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पुनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अलग-अलग खेमा था। अभी हाल ही में सतीश पुनिया ने पेपर लीक मामले में प्रदर्शन का ऐलान किया तो वसुंधरा राजे उसी दिन अपने जन्मदिन पर कार्यक्रम कर रहीं थीं। इन दोनों के अलावा राजस्थान राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन ने पोस्टर राजनीति पर कहा कि क्या बिहार में भाजपा ने उन नेताओं को छोड़ दिया है जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की और अब वे चौधरी से उम्मीदें लगा रही है। चौधरी करीब पांच साल पहले ही भाजपा से जुड़े हैं। जदयू के विधान पार्षद एवं प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ''ऐसा लगता है कि भाजपा नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार और जनक राम जैसे लोगों को भूल गई है। ये सभी जद (यू) और भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री थे।'' ये सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या दलित समुदाय से नाता रखते हैं। अगले साल होने

में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का अलग खेमा है। वह अपना अलग ही कार्यक्रम चलाया करते हैं। अभी हाल ही में वीरांगनाओं का मामला उन्होंने उठाया। भाजपा के लिए सबसे बड़ी समस्या अलग-अलग खेमे बना चुके इन नेताओं को एकजुट करना था। इस कड़ी में माना जा रहा है कि सीपी जोशी कारगर साबित हो सकते हैं। सीपी जोशी के सभी नेताओं से अच्छे संबंध हैं और उनको किसी एक खेमे का नहीं माना जाता है। हाल ही में मेवाड़ क्षेत्र के दिग्गज भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया को राज्यपाल बना दिया गया। सीपी जोशी भी उसी क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा सीपी जोशी को आगे बढ़ाना चाहती है। सीपी जोशी का चयन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हिंदी पट्टी वाले इलाकों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव नहीं खेला, लेकिन राजस्थान में यह दांव चला है। वही सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने मेवाड़ को साधने की कोशिश की है। मेवाड़ में ब्राह्मण और वैश्य बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। उदयपुर से विधायक रहे गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद मेवाड़ में बीजेपी के पास कोई प्रभावी नेता नहीं रह गया था। ऐसे में जोशी को नई जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने इस बेल्ट में खुद को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिलों में ब्राह्मण और वैश्य वर्ग का खासा वोट बैंक है।

गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्षों की सूचि में एक नाम वीरेंद्र सचदेवा का है जिन्हें दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि वीरेंद्र दिल्ली में पिछले तीन महीने से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में हार के बाद आदेश गुप्ता ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस दौरान उनके नेतृत्व में पार्टी विपक्षी पार्टियों खासकर आम आदमी पार्टी पर काफी हमलावर रही। उनका परिवार पाकिस्तान से आने के बाद चांदनी चौक में बस गया था। उन्होंने यहीं से अपनी राजनीति की शुरुआत की। वह 1988 से राजनीति में एक्टिव हैं। उन्होंने मंडल स्तर से लेकर जिला अध्यक्ष तक की भूमिका निभाई। साल 2007 में उन्हें चांदनी चौक का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद साल 2014 में वे मयूर विहार जिले के अध्यक्ष चुने गए। साल 2009 में प्रदेश में मंत्री रहे और 2017 में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। 11 दिसंबर 2022 को उन्हें दिल्ली भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वही ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी सचदेवा के जरिए पंजाबी मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी। ये पार्टी की पंजाबियों के बीच मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश है। पिछले दो प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता बिहार और यूपी से हैं। ऐसे में दिल्ली में इन राज्यों के प्रवासियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पार्टी ने इन्हें चुना था। क्योंकि बिहार और यूपी के लोग दिल्ली की आबादी में बड़ा हिस्सा हैं। बीजेपी सूत्रों ने कहा कि गुप्ता को हटाए जाने के बाद पार्टी के दिल्ली कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल में सचदेवा प्रभावशाली रहे हैं। इसके अलावा सचदेवा की संगठन और आरएसएस में भी अच्छी पकड़ है। ऐसे में वो दिल्ली में सामंजस्य बिठाने में सफल हो सकते हैं। उन्हें संगठन की बेहतरीन समझ है। वह पार्टी ग्राउंड लेवल तक मजबूत करेंगे। संगठन में अच्छी पकड़ होने के कारण ही उन्हें कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का प्रमुख भी बनाया जा चुका है। वह पत्रकारिता से राजनीति में आए।

बताते चले कि विधानसभा चुनाव से पहले इस बदलाव के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ओडिशा के पूर्व राजस्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनमोहन सामल को पार्टी ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मनमोहन सामल ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में समीर मोहंती का स्थान लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहंती का तीन साल का कार्यकाल इसी साल जनवरी में खत्म हुआ था। बता दें कि बीजेपी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाल को ओडिशा की कमान सौंपी है, ताकि बेहतर रणनीतियां बनाई जा सके और राज्य में बहुमत से बीजेपी की सरकार बने। पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी है। ज्ञात हो कि ओडिशा के तटीय इलाकों में सामल एक बड़ा राजनीतिक चेहरा हैं। सामल की आदिवासी समाज पर अच्छी पकड़ है। बीजेपी उनके जरिए क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। वह केंद्रीय नेतृत्व के करीबी हैं। मनमोहन सामल ओडिशा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बता दें कि समल को उनकी संगठनात्मक ताकत और अनुभव के चलते प्रेसिडेंट पद के लिए चुना गया है। पूर्व मंत्री होने के साथ वे तब भी राज्य में यूनिट प्रेसिडेंट रहे हैं जब भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन वाली सरकार थी। कहा जा रहा है कि ओडिशा में विपक्षी नेता जयनारायण मिश्रा पश्चिमी ओडिशा से हैं, इसलिए भाजपा ने तटीय क्षेत्र से अध्यक्ष का चुनाव किया है।

बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी ने चार राज्यों बिहार, राजस्थान, दिल्ली और उड़ीसा में नये अध्यक्ष बनाकर संगठन में बदलाव किया है तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी फेरबदल की संभावना देखी जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व जहां किसी आदिवासी चेहरे को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है तो वहीं दूसरी ओर ओबीसी से भी कई नामों पर चर्चा हो रही है। आदिवासी चेहरों में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और समीर उरांव के नाम सामने आ रहे हैं तो दूसरी ओर ओबीसी से रघुवर दास और आरिफ साहब का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी नेतृत्व भारी फेरबदल के मूड में है। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के तीन वर्ष में भी नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं होने पर भाजपा रणनीति बदल रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक किसी आदिवासी नेता को अहम भूमिका दी जा सकती है। अर्जुन मुंडा, समीर उरांव और पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को दायित्व सौंपा जा सकता है। बाबूलाल मरांडी को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो विधायक दल के नेता की जिम्मेवारी किसी ऐसे विधायक को मिलेगी, जिसकी छवि ईमानदार और लड़ाकू किस्म की हो, साथ ही संगठन का भी अनुभव हो। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को केंद्र में महत्वपूर्ण दायित्व दिया जा सकता है। संगठन के शीर्ष स्तर पर यह मंथन जारी है। यह सारे बदलाव 2024 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए होगा। केंद्र के रणनीतिकार झारखंड के संगठन को और सशक्त करना चाहते हैं। बूथ स्तर तक के संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व आदिवासी और विधायक दल के नेता का दायित्व किसी मूलवासी विधायक को दिया जाना है।

वाले लोकसभा चुनाव से पहले चौधरी को राज्य इकाई प्रमुख के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। इन चुनाव के बाद राज्य में 2025 में विधानसभा चुनाव भी होंगे। इस कदम को भाजपा द्वारा कुशवाहा जाति के वोटों को काटने और महागठबंधन के पक्ष में ओबीसी के एकीकरण को विफल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ राजद के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि पोस्टर भाजपा के ''राजनीतिक दिवालियेपन'' को दर्शाता है। शाहीन ने कहा कि सम्राट चौधरी जब राजद में थे, तब उनका क्या कद था? वह पार्टी के 100

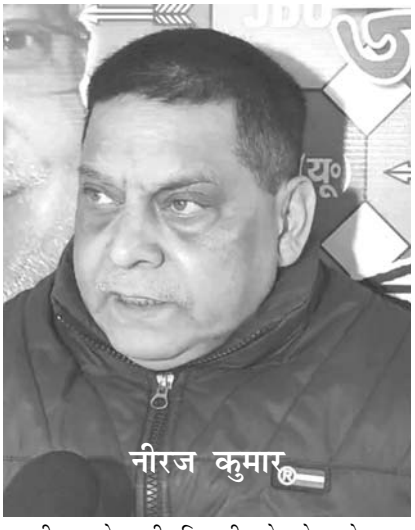
नीरज कुमार

विधायकों में से एक थे। जद (यू) में जाने पर भी उनका यही कद था। बिहार में भाजपा का कोई नेतृत्व नहीं है और उसकी हताशा सभी देख सकते हैं। वहीं भाजपा के नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पोस्टर पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहने से मना कर दिया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला हम विधानसभा चुनाव जीतने के बाद करेंगे, जिसे हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता के कारण जरूर जीतेंगे। इस बीच, चौधरी राष्ट्रीय राजधानी में हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की हैं। सम्राट ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवद् गीता की एक प्रति भेंट की है।

बहरहाल, एक बात तो सच है कि बिहार में बीजेपी को नीतीश कुमार जैसा साथी चाहिए, जो हर तबके के वोट पर थोड़ा-बहुत असर डाल सके। 'जाति' जिस बिहार में चुनाव

तारकेश्वर प्रसाद

का फैक्टर बनती है, वहां किसी ऐसी जाति के चेहरे को आगे करना बीजेपी की मजबूरी है, जो अपनी सबसे बड़ी बिरादरी के वोट के साथ दूसरी जातियों के वोट पर भी असर डाल सके। हालांकि लोकसभा चुनावों में यह बड़ा फैक्टर नहीं बनता, फिर भी असर तो डालेगा ही। बीजेपी के लिए फिलवक्त सबसे महत्वपूर्ण 2024 का लोकसभा चुनाव फतह करना है। यह सबसे बड़ी चुनौती भी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास हिन्दुत्व के साथ दलित-पिछड़ों का भरोसा जीतने की भी चुनौती है। बिहार की बात करें तो बीजेपी के पास अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जो भरोसा जगा सके कि वह उसकी नैया पार लगा देगा। सियासत के दगे कारतूस जैसे सहयोगी नेता-समर्थक या दल बीजेपी के लिए डूबते के लिए तिनके का सहारा ही साबित हो सकते हैं। उनके जरिये बड़ा खेल बिहार में संभव नहीं है। कौन-कौन हो सकते हैं बीजेपी के खेवनहार, जरा इस पर गौर करते हैं। बिहार में बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं सुशील कुमार मोदी, लेकिन

प्रेम कुमार

जनक राम

नन्दकिशोर यादव

आरसीपी सिंह

बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना कर बिहार की राजनीति से विदा ही कर दिया है। सुशील मोदी को नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद माना जाता था। लालू परिवार के खिलाफ उनका हल्ला बोल सर्वविदित है। लालू परिवार के खिलाफ उनके बयानों और ट्वीट का अगर आकलन किया जाये तो शायद इस मामले में उनकी जगह गिनीज बुक आफ रिकाड्र्स में जरूर दर्ज हो जाएगी। रोज-रोज लालू परिवार की आलोचना के साथ सुशील मोदी के निशाने पर तो अब नीतीश भी आ गये हैं। इसके बावजूद बीजेपी सुशील मोदी पर भरोसा करेगी, इसमें संदेह लगता है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास लव-कुश समीकरण साधने के लिए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह जैसे नेता जरूर हैं, लेकिन वे चुनाव नहीं जिता सकते। इसलिए बीजेपी उन पर भी दांव लगा सकती है। उनके आने से बीजेपी के पारंपरिक वोट तो मिल ही जाएंगे, नीतीश के न रहने पर लव-कुश समीकरण वाले वोटों में भी सेंध लग सकती है। अब सवाल है कि बीजेपी को उनको कितना तरजीह देती है। यादवों के वोट तो बीजेपी को मिलने से रहे। अपवाद छोड़ दें, बीजेपी को यादव वोट कभी नहीं मिलते। इसलिए किसी यादव नेता पर बीजेपी दांव लगाने से परहेज करेगी। आरजेडी का जब खस्ताहाल था, तब भी यादवों के 16-17 प्रतिशत वोट उसे मिलते रहे हैं। यह 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों के परिणामों से स्पष्ट है। बीजेपी के भूपेंद्र यादव लंबे समय तक बिहार के प्रभारी रहे। इसके बावजूद यादव वोटरों को वे नहीं लुभा पाये। हालांकि यादव बिरादरी के दो दमदार चेहरे बीजेपी के पास हैं। इनमें एक हैं नित्यानंद राय तो दूसरे नंदकिशोर यादव। रामकृपाल यादव भी शुमार किये जा सकते हैं। इसके बावजूद बीजेपी इनमें किसी चेहरे को बिहार में अपने नेता के तौरपर उभारेगी, इसमें संदेह है। इसलिए कि जिस तरह मुसलमानों के वोट बीजेपी को कभी नहीं मिलते, उसी तरह यादवों के वोट भी आरजेडी के अलावा कोई दल अब तक झटक नहीं पाया। अब बात करे सर्वण नेता की तो बीजेपी अगर सवर्ण नेता को सामने करती है तो इससे पिछड़ी जाति और दलितों के वोटर बिदक सकते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा खुद को खेवनहारों की कतार में आगे निकलने के लिए कम सक्रिय नहीं हैं। वे भी नीतीश और लालू परिवार के खिलाफ हल्ला बोलने में सुशील मोदी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार का

उपेन्द्र कुशवाहा

साथ बीजेपी की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण रहा है। नीतीश ने न सिर्फ अपने लव-कुश समीकरण वाले वोट पर अधिकार जमाये रखा, बल्कि आरजेडी के वोटर आधार को भी उन्होंने अपने पाले में किया। यही वजह रही कि वे लालू यादव के बाद बिहार में दमदार पोलिटिशियन बने रहे। सच कहें तो लालू को टक्कर देते भी रहे। 2015 में ऐसा ही मौका था, जब यह साबित हुआ कि लालू का साथ उनको फायदे में रख सकता है। अगर एंटी इन्कबैंसी को फैक्टर भी मानें तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर लव-कुश समीकरण के 7-9 प्रतिशत वोट थोक में ट्रांसफर करा सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के लीडर नीतीश की खुल कर आलोचना नहीं करते। अब सवाल उठता है कि बीजेपी को

रामकृपाल यादव

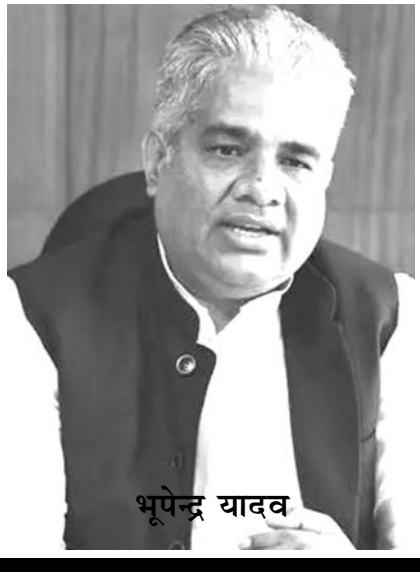
भूपेन्द्र यादव

नित्यानन्द राय

विजय कुमार सिन्हा

अगर बिहार में 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर पार पाना है तो उसे कोई एक चेहरा सामने लाना ही पड़ेगा, ताकि वोटरों को अपना मन बनाने में सहूलियत हो। बीजेपी की अभी ताकत उसके पारंपरिक वोटर हैं, लेकिन बिहार का जैसा मिजाज रहा है, उसमें कोई सर्वस्वीकार्य चेहरा तो सामने रखना ही पड़ेगा।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में भाजपा की तरफ से जिस तरह की तैयारी की जा रही है उसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ भाजपा के बड़े नेताओं की पूरी फौज बिहार पर फोकस की हुई है। लगातार बिहार के दौरे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता जा रहे हैं और लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। वहीं गृहमंत्री अमित शाह 6 महीने के अंदर चौथी बार बिहार दौरे कर चुके और जेपी नड्डा ने कुछ महीने पहले ही बिहार का दौरा किया था तो बता दें कि राजद, कांग्रेस और जदयू को मात देने के लिए बिहार में भाजपा की तरफ से 'सम्राट' कार्ड खेला गया है। 2024 के चुनाव से पहले भाजपा ने बिहार भाजपा की कमान सम्राट चौधरी के हाथ में सौंप दी है। वहीं अब भाजपा की तरफ से एक और ब्रह्मास्त्र बिहार के लिए छोड़ा गया है। दरअसल नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जानेवाले सुनील ओझा को पार्टी ने बिहार में सह प्रभारी नियुक्त किया है। जेपी नड्डा की तरफ से सुनील ओझा को बिहार भाजपा का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही इसकी घोषणा भी की है। ज्ञात हो कि सुनील ओझा गुजरात के रहनेवाले हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के बाद बिहार भाजपा के संगठन में एक और बदलाव ने पार्टी की सोच को साफ कर दिया है। भाजपा किसी भी कीमत पर बिहार में अपनी मजबूती को बरकरार रखने और अपनी जमीनी ताकत को और बढ़ाने के मुड में नजर आ रही है। सनद् रहे कि सुनील ओझा यूपी के सह प्रभारी थे। ऐसे में बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े के साथ मिलकर अब सुनील ओझा वहां प्रदेश में काम करेंगे क्योंकि तत्काल उनके मनोनयन को प्रभावी रूप दे दिया गया है। सुनील ओझा पीएम मोदी के कितने करीबी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र का काम संभालते रहे हैं। वह गुजरात में भावनगर से विधायक भी रह चुके हैं। बता दें कि मिर्जापुर में बन रहे गढ़ौली आश्रम की वजह से सुनील ओझा चर्चा में आए थे। लोग इसे ही ओझा का यूपी से बिहार में ट्रांसफर की वजह बता रहे हैं। ऐसे में अब बिहार में सुनील ओझा के प्लान का भाजपा को कितना फायदा मिलेगा यह तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा।●

बिहार बीजेपी के नये प्रभारी सुनील ओझा के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी

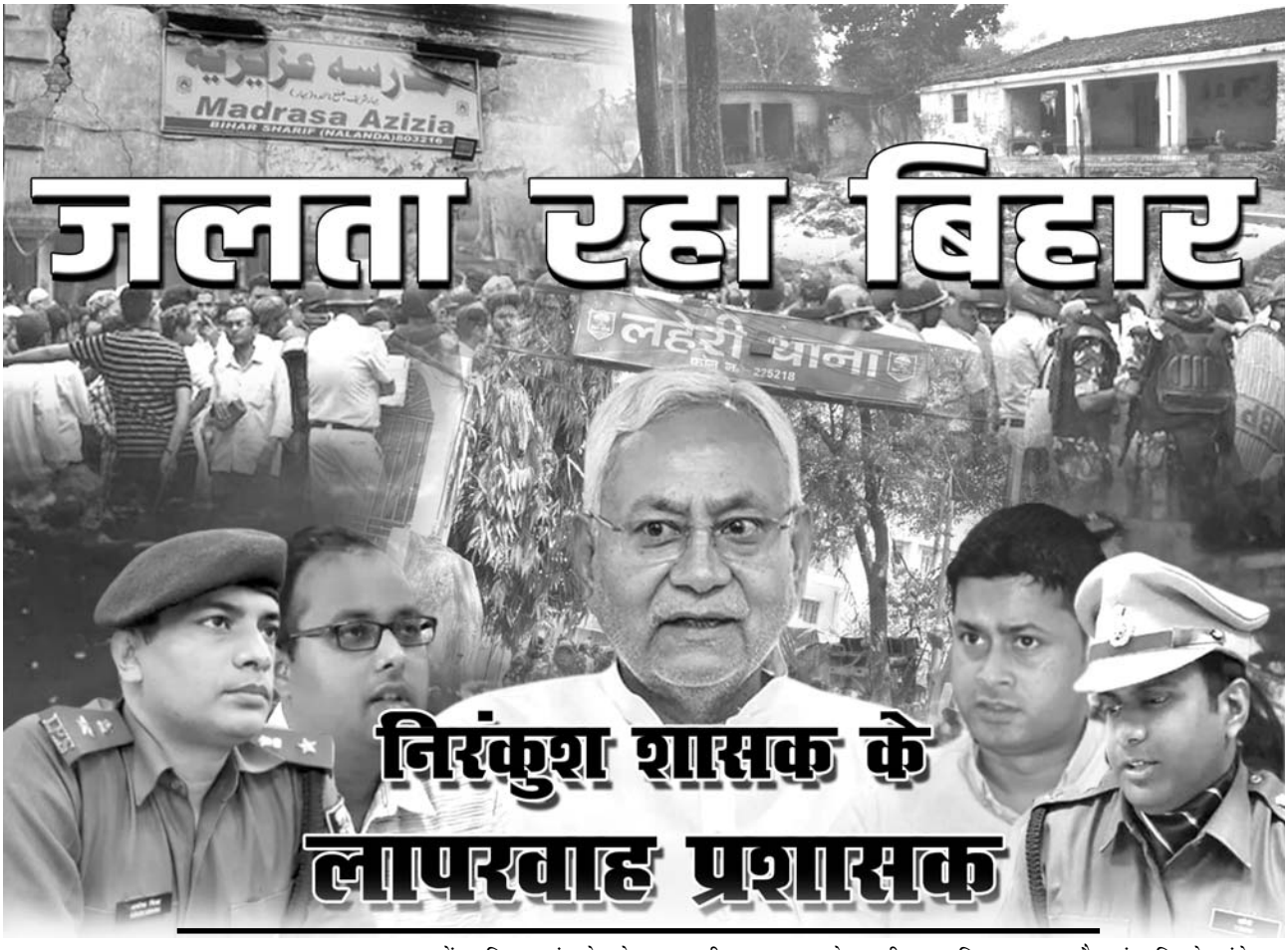

जलता रहा बिहार

निरंकुश शासक के लापरवाह प्रशासक

● मिथिलेश कुमार/ललन कुमार

विश्व को शांति का पैगाम पहुंचाने वाले बिहार स्वयं अशांति और हिंसा की अंतहीन कहानी का पर्याय बन चुका है। भगवान बुद्ध, महावीर की धरती आज सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है। खासकर नालन्दा का अपना ऐतिहासिक बजूद कायम है। यह वही नालन्दा है जहां जीवंत दस्तावेज के रूप में मौजूद खंडहर इस बात का प्रमाणिक दस्तावेज है जहाँ विश्व के विभिन्न देशों के छात्र यहां ज्ञान अर्जित करने आते थे। यह वही नालन्दा है जहां पांच पहाड़ियों के बीच राजगीर के मनोरम वादियों में विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। शांति स्तूप जैसे विश्व के ऐतिहासिक धरोहर में शामिल एवं यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध स्तूप चारो दिशाओं में शांति का संदेश देता है। यह वही नालंदा है जहां स्वर्ण भंडार, जरासंध का अखाड़ा सहित गर्म जल का कुंड है। एक तरफ सीता कुंड में हिन्दू

समुदाय के लोग स्नान करते हैं दूसरे तरफ मकदूम कुंड में मुस्लिम समुदाय के लोग पैगम्बर को याद कर कुंड में डुबकी लगाते हैं। गंगा-यमुनी की पारम्परिक सभ्यता और संस्कृति के ढांचे इस बात का साक्षी है कि यहां के लोग एक दूसरे धर्म के प्रति उतने ही आस्थावान है। राजगीर का सप्तधारा न जाने किस कालखंड से निरंतर कालांतर से आज तक बहते आ रहा है, यह वही नालंदा है जहां बाबा मखदूम का मजार है और कुल देवता के रूप में बाबा मनीराम का अखाड़ा भी है। किवदंती या किस्से और कहानियां में वर्णित है नालंदा सूफी संतों की भूमि रही है जहां मुस्लिम मंदिरों में आस्था रखते हैं वही हिंदू मजार पर चादर पोशी करते हैं। और वही नालंदा में अगर सांप्रदायिक तनाव हो तो क्या कहा जा सकता है 31 मार्च की काली शाम बिहारशरीफ के लिए उसके इतिहास में काला अध्याय है जहां रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प के तोड़फोड़ लाठी-डंडे, पत्थरबाजी, आगजनी सहित गोली चलने की बात सामने आई

है।

पिछले 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में हुई घटना कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में चूक या राजनीतिक षडयंत्र है यह कहना मुश्किल है। अगर जानकारों की मानें तो घटना के 6 दिन बाद भी जो बात छनकर आ रही है उसमें शत-प्रतिशत प्रशासनिक चूक का नतीजा है प्रशासन को इस बात का आभास भी था कि बदलते परिवेश में भारी संख्या में जुलूस में शामिल लोगों को अनुशासित ढंग से जुलूस को रूट के अनुसार पुलिस की निगरानी में पार करना प्रशासनिक पुलिस की जिम्मेदारी थी, जिसे नालंदा पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ा। हालांकि अगर लोगों की माने तो शोभायात्रा के पूर्व विशेष समुदाय के लोगों की मंशा और उनलोगों के द्वारा ईंट पत्थर संग्रह करने की बात थानाध्यक्ष एवं सदर डीएसपी को दी गयी थी परन्तु पुलिस ने इसे गम्भीरता से नही लिया। कई लोगों ने कहा कि सामान्य दिनों में सोगरा कॉलेज के पास कई पुलिसकर्मियों की डियूटी रहती थी जो आने जाने वाले वाहनों की जांच करते थे लेकिन घटना के दिन वह भी नदारद थी। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है। इतने बड़े जुलूस को पूर्व में निर्धारित रुट के अनुसार यात्रा को गतिमान रखना पुलिस की जिम्मेवारी थी परन्तु पुलिस ने इसे नजरअंदाज कर दिया। घटनास्थल की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो गगन दीवान विशेष समुदाय की सघन आबादी बाला क्षेत्र है साथ ही साथ कब्रिस्तान के बाहर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मात्र दो पुलिस की तैनाती आखिर किस हद तक लॉ एंड आर्डर की बात को प्रदर्शित करती है यह बड़ा सवाल है।

बिहार शरीफ में जली हुई दुकानें, गोदाम और घर से छिपकर बाहर की तरफ झाँक रहे लोगों को देखकर शहर में फैली दहशत

महसूस की जा सकती थी। यहाँ की वीरान सड़कें ठीक तीन साल पुराने कोविड लॉकडाउन की याद दिला रही थीं। लेकिन भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री की तैनाती के बीच बार-बार गुजरती पुलिस और प्रशासन की गाड़ियाँ हालात को बयाँ करने के लिए काफी थीं। यहाँ सड़कों पर आम लोग तो नजर नहीं आ रहे थे, एक-दो लोग कहीं-कहीं किसी जरूरी काम से घर से बाहर जरूर दिख रहे थे। दरअसल यहाँ पुलिस लगातार एलान कर रही है कि लोग बिना किसी वजह के घर से बाहर ना निकलें। बिहार शरीफ नालंदा जिले का मुख्यालय है यहाँ की आबादी करीब साढ़े तीन लाख मानी जाती है, जिसमें मुस्लिम आबादी भी करीब 30 से 35 फीसदी है। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बिहार शरीफ में भड़की हिंसा में अब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हैं। इस हिंसा में लाखों की संपत्ति भी जल कर राख हो चुकी है और अब भी कुछ दुकानों से निकलता धुआँ देखा जा सकता था। यहाँ सांप्रदायिक उन्माद में एक मदरसे की लाइब्रेरी को भी आग के हवाले कर दिया गया और दूसरे समुदाय ने पुस्तकों के एक गोदाम में आग लगा दी। इस आगजनी के कारण कई बेशकघीमती और ऐतिहासिक पुस्तकें जल कर राख हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। बिहार शरीफ की परंपरा रही है कि यहाँ रामनवमी की मुख्य शोभा-यात्रा दशमी के दिन निकाली जाती है. यानी राम नवमी के दूसरे दिन। लेकिन इस बार शोभा-यात्रा के बाद जो हिंसा भड़की है, उसके बाद से यहाँ हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह हिंसा एक बार फिर से भड़क उठी थी। बिहार शरीफ में हिंसा रोकने के लिए इलाकघे में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है और लोगों से घरों में रहने की अपील की गयी।. यहाँ घटना के दिन से ही धारा 144 लागू कर दी गई थी। ताकि कहीं भी भीड़ ना जुट सके. पुलिस ने शुक्रवार की हिंसा के आरोप में करीब

30 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन शनिवार शाम को यहाँ और भी बड़ी हिंसा हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। अगले दिन भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में यहाँ हालात पर कघबू पाने की कोशिश की गई है। यहाँ हिंसा के पीछे की वजहों को जानने के लिए पुलिस कमिश्नर और आईजी ने भी शहर के अलग-अलग इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी देखा है। पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने बताया कि बिहार शरीफ में पिछले साल भी रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई थी। यहाँ मुहर्रम में भी कोई हिंसा नहीं हुई थी। अशोक मिश्रा के मुताबिक, इस बार रामनवमी की शोभा यात्रा में भीड़ काफी ज्यादा थी। इस यात्रा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मिलकर करते हैं, इस बार की यात्रा में लोग ज्यादा उत्तेजित नजर आ रहे थे।

घटना के बाद नालंदा पुलिस और जिला प्रशासन ने रविवार को शहर के सभी 51 वॉर्ड के सदस्यों के साथ मीटिंग की और उनके साथ मिल कर शहर में शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। अब तक कुल पंद्रह प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। गोली बारी में हुई मौत पर मुख्यमंत्री ने परिजनों को पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा

किया है। वहीं मृतक के स्वजनों ने कहा कि हमारे परिवार में मौत भी हुई और मुझे अन्य मामले में आरोपित भी किया गया है। जबकि घटना से मेरा कोई सबन्ध नही है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बयान दिया है कि बिहार शरीफ में किसी ने गड़बड़ी की है और पुलिस उसकी जाँच कर रही है, जो भी इसके पीछे होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक हिंसा में शामिल करीब 80 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है।

☞ **कैसे हुई घटना :-** बिहार शरीफ में रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए अलग-अलग मोहल्लों की झाँकियां श्रम कल्याण केंद्र के स्टेडियम तक आती हैं। यहाँ से सब मिलकर एक शोभा यात्रा निकालते हैं जो शहर में घूमते हुए करीब तीन किलोमीटर दूर मणिराम अखाड़े तक जाती है। इस साल भी करीब तीन बजे यह शोभायात्रा निकाली गई और लोग राँची रोड, मुरारपुर होते हुए अखाड़े की तरफ बढ़े। लेकिन राँची रोड पर गगन दीवान इलाके तक शोभा यात्रा के पहुँचते-पहुँचते ही माहौल बदलने लगा। दरअसल शोभा यात्रा के दौरान गगन दीवान के पास झांकी के ऊपर पत्थर फेंकने की बात फैलते ही जुलूस में शामिल लोग उग्र हो गए। वहीं दूसरे तरफ से रोड़े बाजी शुरू हो गयी। लोग जब तक सँभलते गोली भी चलनी शुरू हो गयी। पुलिस के अनुसार छह लोग ही घायल हुए लेकिन भीड़ की जो स्थिति थी उसमें दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर भी आ रही थी, जिसे निजी अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा था। उधर मुरारपुर मस्जिद के पास नारेबाजी हुई और दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। मस्जिद में

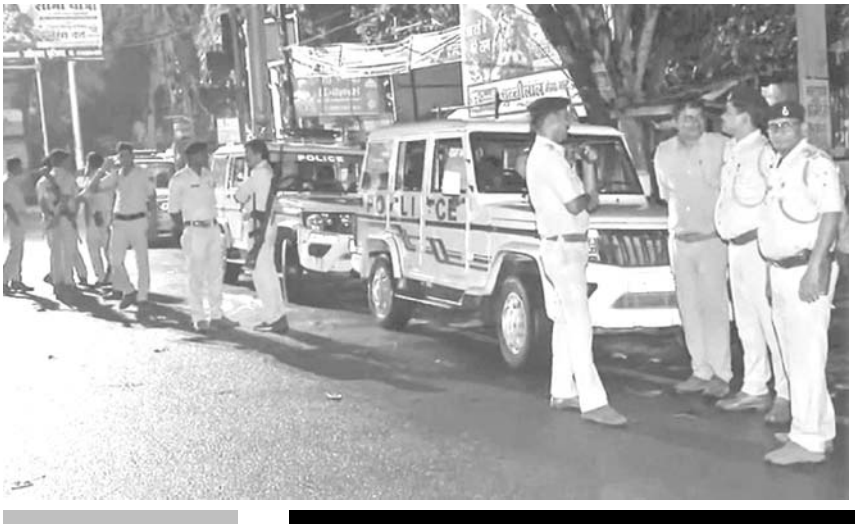

मौजूद मोहम्मद सोहराबुद्दीन का कहना है कि पिछले 15 साल के अनुभव में उन्होंने बिहार शरीफ में ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी थी। उनका आरोप है कि लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और मस्जिद की मीनारों के अलावा अंदर की दीवार और शीशे तक तोड़ दिए। उनका दावा है यहाँ गोलीबारी भी की गई थी। नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के मुताबिक गोलीबारी में कुछ लोगों को गोली के छर्रे से चोट लगी थी। इसी मस्जिद के ठीक पीछे एक मदरसा है जो 1910 में बना था और इसे 1930 में सरकार से मान्यता भी मिल गई थी। इस मदरसा के अजीजिया में भी तोड़फोड़ और आगजनी की निशानी आसानी से देखी जा सकती है। इस मदरसे में बच्चों के पढ़ने के क्लासरूम को आग के हवाले कर दिया गया। पंखे, बिजली के तार सब कुछ तबाह हो चुके हैं। यही नहीं इस उपद्रव में मदरसे के क्लासरूम की दीवारों तक को तोड़ने की कोशिश हुई। लेकिन यहाँ हुई हिंसा का सबसे बड़े नुकघ्सान यहाँ मौजूद कई ऐतिहासिक किताबों को आग के हवाले कर देने से हुआ है। वकील मोहम्मद सरफराज मलिक के मुताबिक इसमें अरबी और फारसी की कई बेशकीमती किताबें थीं जो जलकर राख हो चुकी हैं। इनमें से कई सैकड़ों साल पुरानी दुर्लभ किताबें थीं।

☞ **हिंसा फैलती गई :-** मस्जिद और मदरसे पर शुरू हुई हिंसा को जब तक पुलिस संभालती, तभी यह शहर के कई इलाकों में फैलने लगी। इसी इलाके में लहेरी थाना क्षेत्र में ही जूते और चप्पलों की एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। उनका कहना है कि गगन दीवान में सबसे पहले हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद यह हिंसा फैलती गई, उसी हिंसा में सामने के जूते-चप्पल की दुकान में भी आग लगा दी गई। इलाके में सड़क पर जहाँ-तहाँ हिंसा के निशान मौजूद थे। प्रमिला कॉम्प्लेक्स में जहाँ कई दुकानें और गोदाम बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स में भी बड़ी हिंसा और आगजनी की गई थी। यहाँ हार्डवेयर की एक दुकान पर जम कर तोड़फोड़ की गई और फिर इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इस जगह हुई हिंसा में अरुण कुमार की एक कार और तीन ई-रिक्शा पूरी तरह जलकर राख हो गए, जबकि किताब के एक थोक विक्रेता के गोदाम में आग लगा दी गई। यहाँ अब भी कई जली हुई किताबें चारों तरफ बिखरी हुई हैं और अरुण कुमार कुछ मजदूरों के साथ अपने कॉम्प्लेक्स और किराएदारों की बची-खुची संपत्ति को समेटने का असफल प्रयास करते रहे। उनका कहना है, ये किसी धर्म का काम नहीं, ये सब लुटेरे हैं। एक जगह पर चिकेन शॉप पर आग लगाई गई और उसके बाद दूसरे समुदाय ने हमारे कॉम्प्लेक्स पर हमला कर दिया। यहाँ दीवार को तोड़कर दुकान के अंदर आग लगाई गई। हालाँकि पुलिस ने फैली हिंसा और उपद्रव को काबू में कर लेने का दावा किया था और बिहार शरीफ में हालात काबू में दिख रहे थे। लेकिन फिर से कई इलाकों में हिंसा शुरू हो गई। इस दौरान भी दोनों समुदायों के बीच नारेबाजी और पत्थरबाजी हुई। स्थानीय पुलिस अधीक्षक के मुताबिक गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई। अगर हम चार दशक पूर्व की बात करें तो बिहारशरीफ में 1981 में बड़ी हिंसा हुई थी जो यहाँ के ग्रामीण इलाकों तक फैल गई थी। साल 1998 और साल 2000 में यहाँ छिटपुट हिंसा हुई थी। बीते चार दशक से यहाँ माहौल शांतिपूर्ण था।

इससे पहले सासाराम में 31 मार्च को शहर के नवरत्न बाजार में दो पक्षों में जमकर झड़प हुई जिसमें पथराव भी जमकर हुआ। पथराव में दो पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। करीब 15 राउंड फायरिंग की भी सूचना है। गोलियां चलने से भयभीत दुकानदार जान बचाकर भागे। पथराव के बाद बाजार की दुकानें बंद हो गई हैं। सड़क पर पत्थर बिखरे पड़े हैं। बवाल कर रहे लोगों द्वारा कई घरों में घुसकर मारपीट करने की भी सूचना मिल रही है। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। और डीएम-एसपी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पूरे इलाका छावनी में तब्दील हो गया था। घटना के कई दिन बाद तक अफवाहों का बाजार गर्म रहा।लोग पलायन

पर भी मजबूर होते दिखे। लोगों के चेहरे पर भय का खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था।

☞ **पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी ने घटना के बाद दिया बयान :-** अमित शाह पर राबड़ी का पलटवार, बीजेपी खुद दंगा करवाती है और फिर हल्ला भी करती है, जांच में पता चलेगा राबड़ी देवी ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि आरएसएस और बीजेपी के आदमी पूरे देशभर में घूम रहे हैं। यही लोग दंगा करवाते हैं। सरकार जांच करवाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उलटा करके सीधा लटका देंगे वाले बयान पर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी को दंगा कराने वाली पार्टी बताया। बयान पर राबड़ी ने कहा कि वे खुद ही उलटे हो जाएंगे। नवादा में आयोजित एक जनसभा में अमित शाह ने महागठबंधन सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने सासाराम और बिहारशरीफ में हुई हिंसा को लेकर नीतीश सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। अमित शाह ने मंच से कहा था कि लोकसभा चुनाव में हमें 40 की 40 सीट जिता कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में लाइए। हम दंगाइयों को उलटा करके सीधा लटका देंगे। शाह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्माई हुई है। आरजेडी के साथ ही जेडीयू और कांग्रेस के नेता ने भी इस पर पलटवार किए हैं।

☞ **मुख्यमंत्री ने भी किया पलटवार, एक राज कर रहा है, दूसरा उसका एजेंट :-** बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारशरीफ और सासाराम में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह

मंत्री अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना ही उन्हें जमकर लपेटा। सीएम नीतीश ने कहा कि ये लोग दिल्ली में क्या कर रहे हैं देख लीजिए। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार हो रहा है। दो लोग हैं, जिसमें से एक राज कर रहा है और दूसरा उसका एजेंट है। ये लोग सब इधर-उधर करने का काम कर रहे हैं। नीतीश के इस बयान से कयास लगाए जा रहे है कि राज करना बोलकर एक तरफ वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एजेंट बोलकर असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार ने जगजीवन राम की जयंती के मौके पर बुधवार को मीडिया से बात की। इस दौरान नालंदा और सासाराम हिंसा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत दोनों जगहों पर दंगा करवाया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अचानक से वहां ऐसा क्यों हुआ, इसका जल्द ही सच सामने आएगा। सीएम नीतीश ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर बिहार का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जांच में सब सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना कहा एक जगह जिनको जाना था वहां जान-बूझकर करवाया है। यह सब साजिश के तहत हुआ है। नीतीश ने बताया कि दोनों ही जिलों की स्थिति पर उनकी नजर है। अधिकारी जांच कर रहे हैं। हालात काबू में हैं और घर-घर जाकर चेकिंग की जा रही है। जल्द ही उपद्रवियों और दंगाइयों की साजिश सबके सामने आएगी।

बहरहाल बिहारशरीफ एवं सासाराम में जनजीवन सामान्य होने में बहुत समय लगेगा। प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से सद्भावना मार्च निकालकर आपसी भाईचारे को बनाने एवं एक दूसरे सम्प्रदाय के लोगों में अनजाने डर और भय का माहौल को खत्म करने का सन्देश दिया। ●

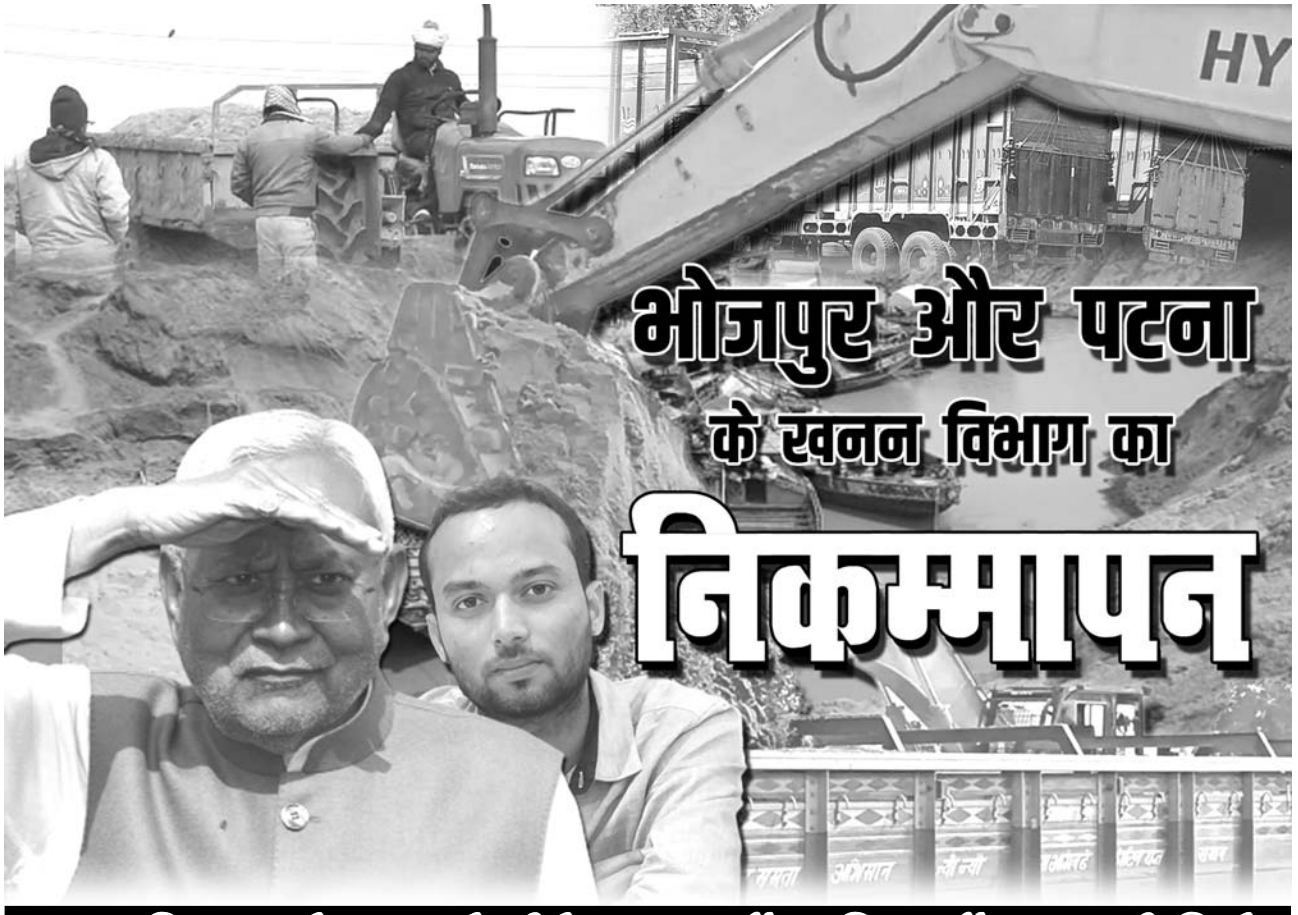

भोजपुर और पटना के खनन विभाग का निकम्मापन

खनन विभाग के नाक के नीचे चल रहा है पासिंग और दलाली गिरोह

● सागर कुमार/के.के. सिंह

बिहार और झारखंड बंटवारे के बाद बिहार को दो प्रमुख नाम मिले जिनमें एक तो पिछड़ों वंचितों की आवाज कहलाने वाले राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का नाम आता है और दूसरा जिस पर बिहार के आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई है वह तमाम नदियों से निकलने वाला बालू का आता है और इसकी महत्व तब और बढ़ गई जब बिहार में पूर्ण शराब बंदी लागू हो गई खैर यह केवल कहने की बात है कि बिहार में शराबबंदी लागू है। तो हम यहां पर आपको बताते चलें कि बालू केवल एक शब्द मात्र नहीं है बल्कि बिहार की एक बहुत बड़ी पूंजी के रूप में आज भी स्थापित है।

विदित हो की बालू उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहां से यह निकलती है क्योंकि इन क्षेत्रों में रहने वाले अधिकतर लोगों का व्यवसाय बालू है, अधिकतर मजदूरों का काम बालू से चलता है, कहने का अर्थ यह है कि इन क्षेत्रों में अगर चूल्हा

जलता है तो उसका प्रमुख वजह बालू है लेकिन इसका एक स्याह पक्ष यह भी है की इसी बालू के काल में कई लोगों की जान समाहित हो गई। बालू में होने वाले अंधाधुन कमाई बालू माफियाओं के बीच में खूनी संघर्ष को जन्म दिया और जल्द ही यह खूनी संघर्ष वृहद रूप लेते हुए वरदान के साथ-साथ इन क्षेत्र के लोगों के लिए अभिशाप बन गई। हाल की कुछ घटनाओं का अध्ययन कर आकलन करने पर पता चलता है कि पटना और भोजपुर के इलाकों से ही लगभग दर्जनों लाशें केवल बालू माफियाओं के वर्चस्व की लड़ाई में गिरी हैं। परंतु प्रशासन न जाने क्यों सुस्त है? या फिर यूं कहें की प्रशासन मस्त है। खैर बालू माफियाओं पर पूरी तरह से अंकुश पाना तो पटना और भोजपुर पुलिस के लिए एक सपना जैसा है परंतु फिर भी पटना पुलिस और एसटीएफ की विशेष टीम के द्वारा पिछले दिनों बालू घाटों पर लाश गिराने वाले दो गुटों में से एक फौजिया गिरोह का सरगना , मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, परंतु फिर भी

इस क्षेत्र में अवैध और ओवरलोडेड बालू की समस्या, और पैसा लेकर अवैध बालू ट्रकों का पासिंग करवाने के कारण क्षेत्र में ट्रकों की लंबी लाइनें और जाम लगने की समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन और खनन विभाग की ना कोई तैयारी है , ना कोई नीति है और ना ही कोई सोच है।

समस्या केवल यही नहीं है, केवल सच की टीम पत्रकार सागर कुमार और संयुक्त संपादक के के सिंह अपनी जान पर खेलकर रात रात भर और दिन दिन भर उन क्षेत्रों में जब लगातार रिपोर्टिंग करना शुरू किया , गांव वाले लोगों से , ट्रक ड्राइवरों से , गाड़ी मालिकों से, खनन के पदाधिकारियों , प्रशासन डीटीओ के पदाधिकारियों से बात करना शुरू किया ,तब इन क्षेत्रों की समस्याएं खुलकर हमारे पास आने लगी। हम कुछ समस्याएं आपको बताने जा रहे हैं। भोजपुर के सहार अजीमाबाद, चांदी, कोईलवर, बड़हरा और पटना के बिहटा ,मनेर ,रानी तालाब के साथ-साथ छपरा के डोरीगंज इत्यादि थाना अंतर्गत बालू माफियाओं का एक पूरा गैंग काम करता है। और यह आम प्रक्रिया है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस क्षेत्र का बच्चा-बच्चा जानता है कि इन क्षेत्रों में अवैध बालू ओवरलोडेड बालू किधर से आती हैं किधर जाती हैं और कौन-कौन से अधिकारी पदाधिकारी और कौन सा थाना इनसे पैसे ऐंठता है। अवैध मतलब घाटों पर से बिना चालान कटाए बालू ले जाने से सर्वप्रथम तो बिहार को और राजस्व की क्षति होती है, और ओवरलोडेड बालू ले जाने से सड़कें खराब होती है और सड़कों के खराब होने से इन क्षेत्रों में बराबर ही एक्सीडेंट और जाम की समस्याएं बनी रहती है। हाल ही में बड़हरा थाना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। यहां पर आपको बताते चलें की बालू की अवैध और ओवरलोडेड ढुलाई को रोकने की सबसे पहली जिम्मेवारी खनन विभाग की है।

और बिहार के पटना भोजपुर और छपरा के खासकर इन क्षेत्रों में खनन विभाग के अधिकारी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं और यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं इसके हमारे पास पुख्ता प्रमाण भी हैं और इन क्षेत्रों के ग्रामीण और बच्चे चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं की खनन विभाग अगर चाहें तो इन क्षेत्रों में से एक भी अवैध और ओवरलोडेड ट्रक चलना बंद हो जाए परंतु खनन विभाग अपनी नाकामी को मानने को तैयार नहीं। हम जब भोजपुर के खनन पदाधिकारी आनंद कुमार से मिलने उनके आरा स्थित कार्यालय में पहुंचे तो पहले तो हमें वहां का ऑफिस का स्ट्रक्चर एक सरकारी ऑफिस की तरह नहीं लगा और दूसरी तरफ खनन पदाधिकारी ऑन रिकॉर्ड हमारे कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हमने अवध और ओवरलोडेड बालू से रिलेटेड पासिंग कराने वाले गिरोह से रिलेटेड , थाना द्वारा पैसे लेकर के पासिंग प्रक्रिया कारण ट्रकों के लंबे लंबे चार से पांच 5 दिन रोड जाम रहने से रिलेटेड, बालू माफियाओं से रिलेटेड कई सवाल भोजपुर खनन पदाधिकारी से हमने पूछा परंतु सभी सवालों के जवाब देने से खनन पदाधिकारी साफ मना कर दिए। हमने खनन के और भी जो इंस्पेक्टर थे उन सभी लोगों से बात की लेकिन किसी भी पदाधिकारी ने हमें स्पष्ट और सटीक जानकारी नहीं दी और ना ही उनके पास कोई ठोस जवाब थे, वही पुराना और घिसा पिटा जवाब कि इस क्षेत्र में अवैध ओवरलोडेड बालू रोकना मुश्किल है , नामुमकिन है असंभव है इस तरह के शब्द मुझे वहां पर उनके अधिकारियों के द्वारा सुनने को मिले। कुछ लोगों ने नाम ना छापने की शर्त पर यह भी कहा कि खनन के पास सीमित संसाधन है। कर्मियों की पदाधिकारियों की संख्या काफी कम है, इस

वजह से इस क्षेत्र में बालू माफियाओं पर शिकंजा कस पाना काफी मुश्किल है और हमें हंसी तो तब आई जब इनके पदाधिकारी हमसे ही कहने लगे कि अगर आप किसी बालू माफिया को या पासिंग करने वाले गिरोह के किसी व्यक्ति को या किसी दलाल को जानते हैं तो हमें बताइए, अब बताइए की नीतीश कुमार जी खनन के पदाधिकारियों को क्या केवल इसलिए रखे हैं कि मीडिया कि लोग जाकर उन्हें बालू माफियाओं के और पासिंग कराने वाले गिरोह के लोगों का नाम नंबर देंगे तब जाकर खनन पदाधिकारी काम करेंगे? क्या इन लोगों की अपनी जमीर मर चुकी है ? क्या इन पदाधिकारियों के पास अपना निकम्मा पन दिखाने के लिए और कोई जवाब नहीं बचा है? हम केवल सच के माध्यम से खनन के बड़े अधिकारियों से भी बात करने के प्रयास में हैं परंतु हम सुबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहेंगे कि उनके कोई भी अधिकारी पदाधिकारी आखिर मीडिया से बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? और बात करते हैं तो सही जानकारी क्यों नहीं देते हैं?

आखिर क्यों यह लोग इनके क्षेत्रों में अपने काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं ? आखिर क्या वजह है कि इतने तंत्र लगाने के बाद भी इतने सरकारी पैसे खर्च करने के बाद भी , इतने नए नीति निर्धारण करने के बाद भी , इन क्षेत्रों के लोग परेशान हैं। इन बालू वाले सड़कों पर चलना दुश्वार हो गया है जब ट्रक वाले खुले रूप से बालू लेकर इन सड़कों पर चलते हैं तो इन सड़कों पर धूल कणों से आसपास के ग्रामीण परेशान हैं इनके बच्चे दमा जैसे अन्य कई बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। चार-चार पांच-पांच दिन ट्रक ड्राइवर जाम में रहने की वजह से एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है। रोड खराब हो रहे हैं, लगातार घटनाएं घट रही हैं फिर भी ना जाने क्यों इस क्षेत्र के प्रशासक सूबे के मुखिया मौन हैं? आखिर यह जवाब देगा कौन? और बात यहीं नहीं रुकती है हमने भोजपुर खनन विभाग के कार्यालय में दलालों की भरमार को देखा। हमारे पास स्पष्ट प्रमाण हैं कि भोजपुर खनन कार्यालय में जो दूरदराज से गरीब ट्रक वाले चालान जमा करने के लिए आते हैं तो उन्हें दलालों के चक्कर में पड़कर ठगी का शिकार होना पड़ता है। और यह दलाल कहीं ऑफिस के बाहर नहीं रहते हैं बल्कि खनन के कार्यालय में खुले रुप से बैठते भी हैं । अब यह बता पाना मुश्किल है कि यह खनन विभाग के कार्यालय में बैठने वाले दलाल आखिर किसका संरक्षण पाकर सरकारी कार्यालय में बैठते हैं और दूरदराज से आने वाले गरीब ट्रक ड्राइवरों और मालिकों से चालान कम करवाने के नाम पर और गाड़ी जल्दी निकलवा देने के नाम से मोटी रकम ऐंठ लेते हैं । केवल इतना ही नहीं बल्कि ये दलाल उन लोगों को डराते धमकाते भी हैं और अगर मीडिया इनके मार्ग में रुकावट आती है तो मीडिया को भी धमकी देने से बाज नहीं आते हैं। हमने जब इन दलालों की शिकायत खनन पदाधिकारी भोजपुर से किया और उन दलालों के खिलाफ उनको सबूत भी दिया तो उनके तरफ से कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। यह हमें इस बात से आशंकित करता है कि हो ना हो इन दलालों के संबंध या तो भोजपुर के खनन पदाधिकारियों, अधिकारियों या फिर ऊपर के किसी बड़े अधिकारी और पदाधिकारियों के साथ है और दलालों के माध्यम से बिहार के गरीबो का चुसा हुआ पैसा कहीं ना कहीं भोजपुर के खनन पदाधिकारियों या फिर ऊपर के अधिकारियों पदाधिकारियों के खाते में जरूर जाता है क्योंकि बिना इनके संरक्षण और मिलीभगत के भोजपुर खनन कार्यालय में बैठकर कोई दलाल गरीबों के पैसे कैसे ऐंठ सकता है। भोजपुर खनन विभाग में जाने पर हमें यह

आनंद प्रकाश
खनन पदाधिकारी, भोजपुर

जानकारी मिली की यहां पर मात्र 4 इंस्पेक्टर और एक खनन पदाधिकारी हैं और इन्हीं भरोसे पूरे जिले का खनन विभाग है। अगर इन अधिकारियों के समस्या की बात करें तो सबसे बड़ा समस्या इन के सामने में यह है कि इनके पास अपना खुद का था सरकारी या विभाग का गाड़ी चालक और मिस्त्री नहीं होता है जिस वजह से दूसरे गाड़ी के चालक से पकड़ी हुई गाड़ियों को हटवाया जाता है और उसमें काफी असुविधा होती है। कभी-कभी गाड़ी चलान न होने की डर से ट्रक ड्राइवर ट्रक को ऑटोमेटिक लॉक करके गाड़ी रोड पर छोड़कर ही भाग जाते हैं जिससे कि पूरी सड़क जाम हो जाती है तो इस समस्या से निदान के लिए में बिहार के खनन पदाधिकारियों को गाड़ी अनलॉक करने वाले मिस्त्री की अति आवश्यकता है जो त्वरित लौक को तोड़कर, चालक के सहायता से पकड़ी गई ट्रक को एक किनारे में लगा सके। इसके बाद इन पदाधिकारियों को अपनी सेफ्टी की अपने सुरक्षा की ही, अपने जानमाल की क्षति होने का भी डर सता रहा है। इन क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या यह भी है की विभाग के द्वारा जो बालू लदी गाड़ियां अवैध और ओवरलोडेड होने के कारण पकड़ी जाती हैं उन्हें फाइन देने तक निजी पार्किंग में रखा जाता है और निजी पार्किंग वाले ट्रक वालों से मनमौजी पार्किंग चार्ज लेते है। ट्रक ड्राइवरों के अनुसार पार्किंग वाले एक ट्रक का 1 दिन का चार्ज 1000 तक लेते हैं। अब हमें यह समझ में नहीं आया कि यह बड़े-बड़े पार्किंग निजी हैं या सरकारी। अगर यह पार्किंग सरकारी है तो इनका आवंटन कैसे और किस आधार पर होता है और अगर निजी है तो फिर खनन विभाग का इन पार्किंग वालों से क्या सांठगांठ है यह एक बड़ा प्रश्न है!

☞ **अब बात करते हैं पुलिस प्रशासन की** :- कोईलवर छपरा मार्ग पिछले कई दिनों से जाम है और इस जाम का मुख्य वजह किसी भी ट्रक ड्राइवर या आम आदमी से पूछने पर लोग यही कहते हैं कि इन क्षेत्रों के थाना के दलाल गाड़ी पासिंग करने के नाम पर प्रत्येक गाड़ी वालों से पैसे ऐंठते हैं। ट्रक ड्राइवर 2 में और लोगों ने तो हमारे कैमरे पर यहां तक कहा कि चाहे गाड़ी पर ओवरलोड हो या ना हो चाहे गाड़ी में चालान हो या ना हो सभी लोगों को प्रत्येक थाना पासिंग का पैसा देना पड़ता है और यह पैसे लेने वाले पुलिस नहीं होते हैं बल्कि पुलिस के दलाल होते हैं और एक निश्चित समय पर सभी से पैसे लेकर उनको पासिंग दिया जाता है और तब गाड़ियां धड़ल्ले से निकलना शुरू होती है इसी पासिंग की प्रक्रिया और पैसे के लेनदेन में समय व्यतीत होता है जिससे ट्रकों को रोका जाता है और यही इस क्षेत्र में जाम की बड़ी समस्या है वैसे भोजपुर के बबुरा और छपरा के बॉर्डर पर पुलिया क्षतिग्रस्त होने से भी जाम की समस्या बढ़ी है परंतु थाना के द्वारा जो पासिंग कराने के लिए पैसे का लेनदेन और बंदरबांट होता है यह एक बड़ी समस्या है आप इस क्षेत्र में रात दिन पासिंग कराने वाले गिरोह को बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए देख सकते हैं और इन क्षेत्रों की पुलिस किसी भी बड़े गिरोह को पकड़ने में अभी तक असफल रही है या फिर यूं कहें इन धंधे में लिप्त दलालों के द्वारा जो पैसे इन लोगों के पास जाते हैं उनसे इनके पॉकेट गर्म है जनता पस्त है और यह लोग मस्त हैं।

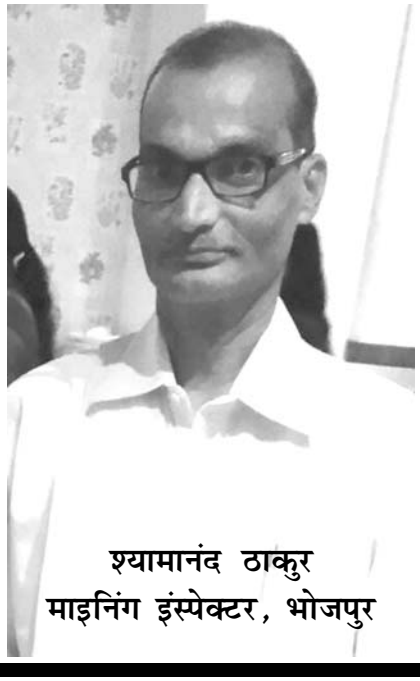

श्यामानंद ठाकुर
माइनिंग इंस्पेक्टर, भोजपुर

☞ **ड्राइवरों के द्वारा बताया गया थाना पासिंग का रेट :-**

सहार थाना	-	मनमाना
अजीमाबाद थाना	-	मनमाना
चांदी थाना	-	1000
कोईलवर थाना	-	500
बड़हरा थाना	-	500
बिहटा थाना	-	सीधे बड़े बालू माफियाओं से संपर्क और भारी-भरकम रकम
रानी तालाब थाना	-	मनमाना
मनेर थाना	-	मनमाना

☞ **बालू के चक्कर में नप गए थानेदार** :- बालू की कहानी पटना के क्षेत्र के लिए कुछ नई बात नहीं है परंतु केवल सच ने जब से इन इलाकों बालू माफियाओं के खिलाफ लगातार खबर चलाया है तो पटना के नए नवेले और काफी तेजतर्रार जुझारू एसएसपी राजीव मिश्रा ने इसको गंभीरता से लिया है और पटना जिले के दो थाना प्रभारियों की छुट्टी कर दी है। सबसे पहले तो बालू लोड वाहनों से अवैध रूप से रुपया वसूली करने के आरोप में थाना प्रभारी की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए पटना जिले के रानी तालाब थाना प्रभारी विमलेश पासवान को मार्च 2023 को निलंबित कर मुख्यालय पुलिस केंद्र भेज दिया गया और थाने की कमान 2018 बैच के दरोगा रवि शंकर कुमार को दे दी गई। उसके बाद पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने एएसपी पालीगंज की रिपोर्ट पर पटना जिले के नौबतपुर थाना के थानाध्यक्ष रफीफुर रहमान को 9 अप्रैल 2023 को निलंबित कर पुलिस केंद्र भेज

दिया गया और उनकी जगह पर 2009 बैच के इंस्पेक्टर, प्रशांत कुमार भारद्वाज नौबतपुर थाने की कमान दे दी गई। आपको बताते चलें कि 21 मार्च 2023 को बिहटा थानेदार सनोवर खान को भी एसएसपी राजीव मिश्रा ने टीचर के इकलौते बेटे तुषार के अपहरण और हत्या के मामले में लाइन हाजिर कर दिया था।

लगातार कई दिनों तक बालू घाटों पर रिपोर्टिंग करने , इन इलाकों के थाने , खनन कार्यालय , डी. टी. ओ. कार्यालय , बालू घाट पर और बालू घाट वाले इलाकों में रात दिन कड़ी मेहनत से घूम घूम कर लोगों से , ट्रक ड्राइवरों से ,ग्रामीणों से , नेताओं से आम आदमी से , महिलाओं से , बुजुर्गों से , बच्चों से यात्रियों से, इत्यादि सभी लोगों से बातचीत करने और इन क्षेत्रों में लगातार केवल सच के कैमरे पर रिपोर्ट दिखाने के बाद हमने यह महसूस किया है कि भोजपुर पटना और कुछ हद तक सारण जिले के खनन विभाग के पदाधिकारी पूरी तरह से निकम्मे हो चुके हैं। इन इलाकों में अवैध, ओवरलोडेड , बिना ढके हुए (अर्थात बालु के धूल कण उड़ाते हुए) बालू ले जाना और इसके वजह से सड़कें खराब होनी अत्यधिक लंबी-लंबी कई दिनों तक जाम की समस्या, इन क्षेत्रों में आए दिन सड़क दुर्घटना और इन इलाकों के ग्रामीण लोगों को 24 घंटे और सातों दिन बालू और धूल के कण के कारण दमा और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होना, बालू घाटों पर वर्चस्व की लड़ाई में दर्जनों लोगों की जान जाना, और इन क्षेत्रों की सड़कों पर रात दिन पासिंग और दलाली गिरोह का सक्रिय होना इन सभी के जिम्मेदार अगर कोई है तो वह इन क्षेत्रों के खनन पदाधिकारी ही हैं दूसरा कोई और नहीं है। क्योंकि यह सारी समस्याएं एक दूसरे से रिलेटेड

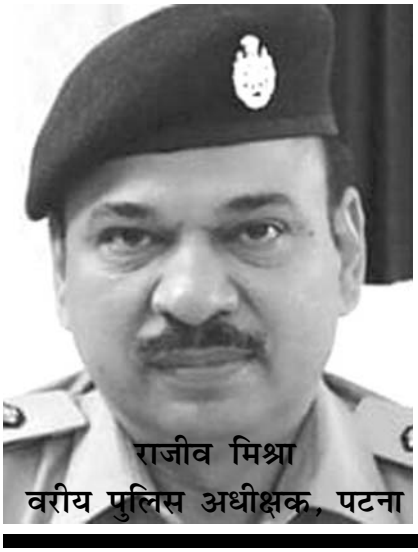

राजीव मिश्रा
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना

है और सब एक दूसरे की पूरक हैं।

अब इस पूरे प्रकरण में हमें केवल तीन संभावनाएं दिखती हैं , पहला तो यह कि इन क्षेत्रों के खनन पदाधिकारियों खनन इंस्पेक्टरों में बालू माफियाओं का भरपूर खौफ है और यह लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं और डर के कारण ही ये ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरी संभावना यह लगती है कि क्षेत्र के खनन विभाग के सभी अधिकारी और पदाधिकारी बालू माफियाओं से बिके के हुए हैं, उसके लिए हम सरकार से यह मांग करेंगे कि इन क्षेत्र के सभी खनन पदाधिकारियों, माइनिंग इंस्पेक्टर और प्रशासन के अधिकारियों डीटीओ के अधिकारियों के मोबाइल ट्रैक किए जाएं । कॉल व्हाट्सएप और मैसेज बॉक्स को खंगाला जाए साथ ही उनके और उनके परिवार के संपत्ति की जांच भी कराई जाए। तीसरा और अंतिम संभावना हमें यह लगता है कि यह सब प्रकरण बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के छवि को बिगाड़ने की बड़ी राजनीतिक साजिश का एक हिस्सा है। क्योंकि इन तीनों संभावनाओं के अलावा और कोई बड़ा और ठोस कारण हमें नहीं दिखता है जिस कारण से इन क्षेत्रों के खनन अधिकारी पदाधिकारी ,इंस्पेक्टर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और बस दिखावे के लिए चालान और कुछ गाड़ियां पकड़ कर अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं। केवल सच बिहार में आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ रहा है , जनता के पैसे पर पलने वाले अधिकारी और पदाधिकारी, नेता कैसे जनता को गुमराह करके उनसे पैसे ठग लेते हैं और उनके हित का काम नहीं करते हैं । इन सब का पर्दाफाश करने के लिए केवल सच ग्राउंड जीरो पर उतरकर रात दिन मेहनत करके आपके समक्ष सच लेकर आती है और हम चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान हो और गरीब जनता को उनका हक मिले। इसलिए इस पूरे प्रकरण में केवल सच का पक्ष यह है कि पटना भोजपुर और सारण जिले के खनन पदाधिकारी अगर वास्तव में इन समस्याओं के हल ढूंढना चाहतें है तो इन्हें इन क्षेत्रों के सभी खनन पदाधिकारी, खनन इंस्पेक्टर, सभी थानों के थानाध्यक्ष, इन सड़कों पर गस्ती करने वाले पुलिस, इन क्षेत्रों के आसपास ग्रामीणों के नेता, आम नागरिक, कुछ ट्रक ड्राइवर, खलासी और इन क्षेत्रों के बालू के बड़े कारोबारी के साथ एक बड़ी और व्यापक मीटिंग करनी चाहिए। और मीटिंग में इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा करके समस्या का निराकरण निकालने की सार्थक और ठोस पहल करनी चाहिए। खनन विभाग के सभी जिलों के अधिकारियों और संबंधित थाना क्षेत्रों के थानाध्यक्षों में आपसी सामंजस्य बैठाकर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि बालू का उठाव जिन जगहों से होता है अर्थात बालू घाटों पर ही कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि वहां से ही अवैध और ओवरलोडेड बालू बाहर ना निकले और खूनी जंग भी ना हो तब जाकर इन समस्याओं का हल संभवत: निकल पाएगा।●

निजी विद्यालय बना स्टेशनरी मॉल

लूट रहे अभिभावक, चुप है प्रशासन

● **मिथिलेश कुमार**

1 अप्रैल को प्राय: लोग दूसरे को अप्रैल फूल बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन उन्हें यह पता नही होता है कि यह माह वैसे अभिभावकों के लिए आर्थिक परेशानी का सबब बनता है जिनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम से सीबीएसई पैटर्न पर संचालित हो रहे निजी विद्यालय में पढ़ते हैं। हालांकि निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवार ही बच्चों को तालीम दिलाते है लेकिन बजट उनका भी बिगड़ता है। अप्रैल माह से विद्यालय में नए सत्र का प्रारम्भ होता है और यही से शुरू होता है आर्थिक दोहन का खेल एक से दो माह की फीस के साथ स्कूलों में डेवलपमेंट फीस के नाम पर ली जाने वाली मोटी रकम भरनी है तो कॉपी-किताब भी खरीदना है। कॉपी- किताब का सेट इतना महंगा है कि उसे खरीदने में अभिभावकों के पसीने निकल जा रहे हैं। कई निजी स्कूलों में तो पहली व आठवीं कक्षा की किताबों का सेट छह से 10 हजार रुपये पड़ रहा है। उधर, प्रशासन और शिक्षा विभाग इस लूट पर चुप्पी साधे हुए है। इन दिनों विद्यालय मॉल बन गया है जहां किताबें, कॉपियां,स्कूल ड्रेस,जूता, मौजा, टाई, बेल्ट,बैग से लेकर स्टेशनरी की सभी सामग्री के लिए अभिभावक लाइन में खड़े रहते हैं। इक्के दुक्के विद्यालय ही वैसे है जहाँ पुस्तकें उपलब्ध नही होती है वहां दुकानदार से सेटिंग कर किताबें बेचते हैं।स्कूलों द्वारा तय निजी प्रकाशकों की किताबें एनसीईआरटी की किताबों से पांच गुना तक महंगी हैं। एनसीईआरटी की 256 पन्नों की एक किताब 65 रुपये की है जबकि निजी प्रकाशक की 167 पन्नों की किताब 305 रुपये में मिल रही है। अभिभावकों का भी यही सवाल है कि ऐसी कौन की किताबें स्कूल पढ़ा रहा है जो 500 से 600 रुपये में मिल रहीं हैं। इतनी महंगी तो बीए एमए की किताबें भी नहीं आतीं। कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहता क्योंकि शिकायत के बाद पुस्तक विक्रेता या विद्यालय पर कार्रवाई हो न हो, स्कूल उस बच्चे पर जरूर कार्रवाई कर देगा। ऐसे में सवाल है कि क्या अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत नही है यह बड़ा सवाल है। अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाने के लिए इसलिए भेजते हैं कि बदलते परिवेश में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के गिरते स्तर एवं समाज में लोगों के बीच दिखाबे का प्रचलन भी इसका कारण है। निजी विद्यालयों के संचालको की गहरी पैठ भी अधिकारियों से रहती है जिसके कारण कोई कार्रवाई नही होती है।

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

☞ **किस कक्षा की किताबों का सेट कितने**

का :-

नर्सरी	2611 से 4000 रुपये
केजी	2625 से 4560 रुपये
एलकेजी	3341 से 4500 रुपये
पहली कक्षा	6000 से 8000 रुपये
दूसरी कक्षा	3300 से 4500 रुपये
चौथी कक्षा	7000 से 8000 रुपये
आठवीं कक्षा	8000 से 10000 रुपये
नौवीं कक्षा	4000 से 8000 रुपये

अभिभावक ने बताया बच्चे की किताबों का सेट 5500 रुपये का मिला है। इसमें कई ऐसी पुस्तकों हैं जिन्हें स्कूल में केवल टर्म 1 की परीक्षा से पूर्व कुछ दिन के लिए पढ़ाया जाएगा। किताबें धूल खाती हैं 305 रुपये का अंग्रेजी की कहानियों की किताब में से पेपर में केवल पांच अंकों का प्रश्न आता है, जिसे लेना मजबूरी है क्योंकि स्कूल ने सूची थमा दी है। सीबीएसई के स्कूलों में भी निजी प्रकाशकों की किताबें पढ़ा रहे केस-3 किताबें 4000 रुपये में आई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से होने के बावजूद बच्चों को लेने एनसीईआरटी की जगह निजी प्रकाशकों की किताब लेने को कहा जाता है। एनसीईआरटी की पुस्तकें तो हर दुकान में मिल जाती हैं पर निजी प्रकाशकों की किताबें लेने के लिए हमें निश्चित दुकान पर आना पड़ता है। कहीं और ये किताबें नहीं मिलतीं। मिलीभगत से चल रहा खेल किताबें खरीदने पहुंचे एक अन्य अभिभावक ने बताया दुकान पर स्कूल का नाम बता दो और वह आपको पुस्तकों का पूरा सेट थमा देंगे। बिना स्कूल और पुस्तक विक्रेता की मिलीभगत के यह कैसे मुमकिन है कि एक दुकान पर तो स्कूल की एक भी पुस्तक नहीं मिलती, वहीं दूसरी ओर बताई गई दुकान पर स्कूल का नाम और कक्षा बता देने भर से सभी पुस्तकें मिल जाती हैं। एक अन्य अभिभावक ने बताया छुट्टी के दिन बच्चे की पुस्तकें लेने आते हैं और विभाग से शिकायत करनी होगी तो अलग से छुट्टी लेनी पड़ेगी प्रशासन हमारी पहुंच से बाहर है। नगर के नामी गिरामी विद्यालय के अभिभावक ने बताया की कक्षा 9 की किताबें

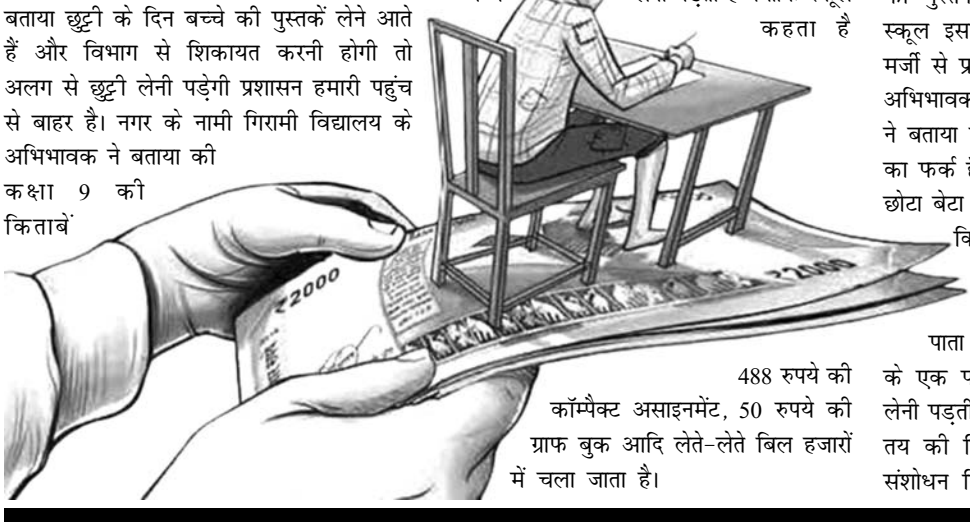

488 रुपये की कॉम्पैक्ट असाइनमेंट, 50 रुपये की ग्राफ बुक आदि लेते-लेते बिल हजारों में चला जाता है।

हिन्दी दैनिक
02 सोन वर्षा वाणी
औरंगाबाद, गुरुवार, 6 अप्रैल 2023
www.sonvarshavani.com sonvarshavani.com/epaper
ई-पेपर
नवादा

निजी विद्यालय बना स्टेशनरी मॉल, अभिभावकों को अप्रैल फूल बना रहे निजी विद्यालय, लुट रहे अभिभावक, चुप है प्रशासन

स्कूलों में नया सत्र शुरू, विद्यालय एवं चुनिंदा दुकानों से ही किताबें लेना अभिभावकों की मजबूरी

अभिभावक ने बताया बच्चे की किताबों का सेट 5500

विद्यालय अपनी मनमानी कर फिजूल की चीजें लेने के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने बताया एटलस, मानव मूल्य की पुस्तक, व्याकरण, ग्राफ बुक, आदि ऐसी चीजें साल कहीं नहीं लगतीं, फिर लेनी पड़ती हैं क्योंकि स्कूल कहता है

अभिभावकों का शोषण हो रहा है। स्कूल और निजी प्रकाशकों की दादागिरी पर प्रशासन भी चुप है और अभिभावकों के हित के लिए कुछ नहीं कर पा रहा प्रशासन ने निर्देश जारी किए थे कि सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी, पर कोई भी निजी स्कूल इसका पालन नहीं कर रहा सब अपनी मर्जी से प्राइवेट पब्लिशर की किताबों की सूची अभिभावकों को थमा रहे हैं। एक अभिभावक ने बताया उनके दो बच्चे हैं। दोनों में एक साल का फर्क है। इसके बावजूद बड़े बेटे की किताबें छोटा बेटा प्रयोग नहीं कर पाता क्योंकि हर साल किताबों में कोई न कोई बदलाव कर दिए जाते हैं। किताबों के कवर भी बदले होते हैं जिससे पता नहीं चल पाता कि यह पुरानी पुस्तक है या नई पुस्तक के एक पन्ने के संशोधन के लिए नई किताब लेनी पड़ती है। इसकी कोई समय सीमा क्यों नहीं तय की कि कितने समय के बाद पुस्तकों में संशोधन किया जाता है।●

मोदी जी का 2024 चुनाव में राजनीतिक कद

● भूपेन्द्र कुमार

नरेन्द्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री तथा भारत के 14 वें प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता हैं। आज वो हमारे देश के प्रमुख प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त राजनेता है। इन्होंने विदेशों में जाकर सभी बड़े-बड़े देशों से मित्रता स्थापित की। भारत का विकास करने में मोदी जी का बड़ा योगदान रहा है।

अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महज एक साल का समय ही बचा है। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपने-अपने स्तर पर तैयारियाँ शुरू कर दी है, लेकिन तमाम सर्वे और चुनावी विश्लेषकों के अनुसार भाजपा को अभी बढ़त हासिल है और मोदी जी का 2024 में प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। विपक्ष अभी एकजुट नहीं हो सका है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने 2024 आम चुनाव के लिए नया टारगेट सेट कर दिया है। यह टारगेट 2019 में बीजेपी को मिली 303 सीटों की तुलना में कहीं अधिक है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 545 है।

2024 के आम चुनाव में अब 400 दिन रह गए हैं। ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए यह और भी खास हैं। वे इतिहास बनाने की दहलीज पर खड़े हैं। मोदी के नेतृत्व में पार्टी दो बार जीत उन्हें देश के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में अलग मुकाम पर खड़ा करेगी। इसके पहले दो ही प्रधानमंत्री दो कार्यकाल पूरा करके तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं। पहले दो चुनाव में युवा वोटर मोदी की ओर चले गये और मोदी सरकार को इसका फायदा मिलता गया और यही वजह है कि मोदी का राजनीतिक कद हर चुनाव में लगातार बढ़ता गया। एल.ए.सी. पर चीन की फौज के पीछे हटने से भारत की साख बढ़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वैदेशिक नीति में जबरदस्त प्रभाव आया है। हम विश्व नेता के रूप में विश्व गुरू के रूप में भारत स्थापना की प्रारंभ हो चुका है।

बीजेपी सरकार बेरोजगारी और किसानों की समस्या दूर करने में भले ही सक्षम ना हो पायी हो पर आम जनता मौजूदा सरकार से उतनी भी नाराज नहीं है, और कांग्रस ने भी कोई उतना अच्छा कार्य नहीं किया कि आम जनता उन्हे वोट दे। कोई भी विपक्षी पार्टी ने मोदी सरकार जैसा कार्य नहीं किया है, इसलिये जनता को मोदी सरकार को सत्ता में लाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। धारा 370 50ए, तीन तलाक, देश का विकास और देश गरीबों का जिस तरह से मोदी जी ने ख्याल रखा है आम जनता उनके पक्ष में ही नजर आती है। जितने कार्यक्रम मोदी जी ने चलाये हैं, जितनी जल्दी सडके बनी है, और गाँव-गाँव बिजली पहुँची है, गाँव-गाँव तक शौचालय पहुँचे हैं, और बेटी पढ़ओ, बेटी बचाओ अभियान के लिए उनका जो मकसद था वो एक-एक कर पूरा हो रहा है। 2024 में आतंकवाद और राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी को 2024 चुनाव में बड़ी सफलता मिलेगी जिसमें मोदी जी की पार्टी की अपनी जो उपलब्धि होगी वो 70%-75% पूरे सीट की होगी। नरेन्द्र दामोदर दास मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगें और उनका कद भी सफलताओं से पहले से बड़ा होगा।

लोकसभा चुनाव में करीब एक साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी. ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मोदी पार्टी ने चुनावी जंग के माहिर महासचिवों की एक टिम बनाई हैं जिसमें सुनील बंसल, तरूण चुक, और विनोद तांबे शामिल हैं। नरेन्द्र मोदी पार्टी के ये त्रिमुर्ति लगातार इन सीटों पर मिल रहे राय के आधार पर रणनीति बना रही है। 2019 में बीजेपी जिन सीटों पर हारी है उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हारी हुई सीट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 50-60 सभायें और दूसरे कार्यक्रम कर सकते हैं। राहुल गाँधी जो विपक्ष कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वे भारत जोड़ो अभियान से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रहे हैं। मोदी का राजनीतिक कद उनकी गलत ब्यान और फैसले से बढ़ा हे और उनसे लाभ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गाँधी की जगह कोई परिपक्व नेता होना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी हर काम लिंक से हटकर करते हैं, इसलिए जनता के बीच उनकी छवि एक कुशल नेता की है। एनडीए सरकार के कामकाज को लेकर जो सर्वे किए गए हैं वो मोदी सरकार के पक्ष में है। पर विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को लोकर केन्द्र सरकार पर लगातार हमले कर रही हैं। निशान बना रही है, तो वहीं पी.एम. मोदी के तरकश में तीन तीर ऐसे हैं, जिससे उनकी नैया पार लगती दिख रही है। जिस तरह गुजरात में मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीन बार की हैट्रिक लगाई थी उसी तरह केन्द्र में प्रधानमंत्री रहते हुए हैट्रिक लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना महामारी से निपटने को मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसके अलावा धारा 370 हटाने वाली श्रेणी में 14 प्रतिशत और राम मंदिर निर्माण वाले वर्ग 12 प्रतिशत लोग मोदी का समर्थन करते हैं। आम जनता में महंगाई को लेकर, सबसे बड़ी असफलता बताया है। ये सब के बावजूद 2024 में मोदी का कद सबसे बड़ा है और वो ही फिर से प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे क्योंकि इस वक्त भारत की राजनीति में पि.एम. मोदी की टक्कर का नेता विपक्ष में नहीं है। दूसरी बात पी.एम. मोदी की लोकप्रियता अभी भी पूरे देश में सब पर भारी है। तीसरी बात बीजेपी में अभी मोदी के कद का नेता फिलहाल नहीं है। वैसे भी भगवा दल अपने इस सबसे बड़े जिताऊ नेता के साथ मैदान में उतरकर जीत की लक्ष्य बरकरार रखना चाह रही है। उधर विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव से लेकर उपराष्ट्रपति चुनाव तक में बिखरा-बिखरा नजर आ रहा है। ऐसे में मजबुत मोदी के सामने विपक्ष फिलहाल तो छितराया नजर आ रहा है। सारे विपक्ष्ज्ञ के बड़े नेता दागी हैं, या फिर योग्य और परिपक्व नहीं है।

बीजेपी ने पिछले महीने हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 की तैयारियों पर ही जोर दिया। इस बैठक में पी.एम. मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया गया। इस बैठक में बीजेपी नेताओं ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार परिवारवाद वंशवाद को लेकर निशाना साधा। नरेन्द्र मोदी 2024 के पहले 10 लाख रोजगार देने का ट्वीट कर चुके हैं। इसे मिशन मोदी में पूरा करने के लिए मंत्रालयों को निर्देश दिया जा चुका है। यानि बीजेपी हर वो तैयारी, रणनीति बना रही है, जहाँ से चूक की गुंजाइश नहीं है। मोदी की अपील और विपक्षी बिखराव ने बीजेपी की जीत आसान कर दी है, तो उनका कद 2024 चुनाव में हर नेता से बढ़ता नजर आ रहा है। उनकी पार्टी अपने सहयोगी दलों को साधना शुरू कर चुकी हे। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडयू और बीजेपी की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी ने साफ कर दिया कि राज्य में पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। केन्द्र की राजनीति के केन्द्र में कौन-कौन आएगा इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे कई दल कुछ मुद्दों पर साथ आने की कोशिश तो करते हैं, लेकन ये सभी मिलकर सीधे पीएम मोदी को टक्कर देते फिलहाल नजर नहीं आते हैं।●

जैव ईंधन पर एक अभूतपूर्व पुस्तक

जैव ईंधन (बायोफ्यूल्स) को हमेशा ऊर्जा के सबसे प्रमुख नवीकरणीय संसाधनों में से एक के रूप में देखा गया है। भारत में जैव ईंधन गैर-पारंपरिक और स्वच्छ ईंधन की जरूरतों को पूरा करने की दौड़ में सबसे आगे है। पिछले कुछ वर्षों में बायोडीजल के उत्पादन और खपत में विस्मयकारी परिवर्तन देखा गया है। पटना की बेटी, डॉ समिधा बंका अग्रवाल ने अपने प्रोफेसर डॉ० सचिन प्रकाशभाई पारिख के साथ जैव ईंधन पर एक अभूतपूर्व पुस्तक लिखी है। पत्रिका के प्रधान संपादक अरूण कुमार बंका द्वारा हुए वार्तालाप को अधिक से जानते हैं :-

★ समिधा जी, लेखक बनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया?

मेरा झुकाव हमेशा से लेखन की ओर रहा है। चाहे वो शोध लेख, निबंध या ब्लॉग हों। हालांकि, इस पुस्तक को लिखने के लिए मेरे पति श्री प्रेरक अग्रवाल ने उत्साहवर्धन किया है। इसके अलावा, मेरे प्रोफेसर और गाइड डॉ० सचिन प्रकाशभाई पारिख थे, जिन्होंने पुस्तक की रूपरेखा और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मेरा मार्गदर्शन किया। मैं, मेरे पिताजी श्री रवि प्रकाश बंका जी का खास रूप से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी पुस्तक की त्रुटि सुधार में विशेष योगदान दिया है। इसके साथ ही मैं अपने शिक्षकों, परिवारजनों और दोस्तों को धन्यवाद देने का अवसर लूँगी, जिन्होंने हमेशा मुझपर विश्वास किया और मेरे हर कदम में मेरा समर्थन किया है। उनके बिना यह पुस्तक कभी सफल नहीं होती।

★ आपको अपनी पुस्तक के लिए विचार कैसे आया?

मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूं और मेरा शोध का विषय बायोडीजल उत्पादन के लिए प्रक्रिया गहनता है। अत: मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र होने के नाते मैंने जैव ईंधन पर इस पुस्तक को लिखना चुना। इसके अलावा, जैव ईंधन आज ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की दौड़ में सबसे आगे हैं। भारत ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के सफल कार्यान्वयन के साथ, अब यह आज की चर्चा का विषय बन गया है। अब जैव ईंधन को जल्द ही सभी क्षेत्रों में ऊर्जा का अपरिहार्य स्रोत बनने जा रहा है।

★ अपनी पुस्तक के बारे में और बताइए?

यह किताब हर पहलू से बायोडीजल की जानकारी देती है। पुस्तक में नवीनतम तकनीकी विकास और विभिन्न प्रमुख बायोडीजल उत्पादक देशों की नीतियों को शामिल किया गया है। हम इस उन्नति को बिना किसी भाषाई बाधाओं के भारत के अधिकतम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और इसलिए बायोडीजल के क्षेत्र में वर्तमान प्रगति को व्यक्त करने के लिए हिंदी को माध्यम के रूप में लिया गया है। यह पुस्तक सभी छात्रों, शोधकर्ताओं, के साथ-साथ सभी आम आदमी के लिए है, जो भारत और विदेशों में जैव ईंधन उत्पादन और उपयोग की स्थिति जानने में रुचि रखते हैं। हम इसे भारत

आप इस पुस्तक को एमेजन से खरीद सकते हैं या किन्डल पर भी पढ़ सकते है। पुस्तक के लिए इसे स्कैन करे।

में हर उस व्यक्ति तक पहुँचाना चाहते हैं, जिनके लिए अंग्रेजी संबंधित अवधारणाओं को समझना मुश्किल है।

★ आपकी पुस्तक अन्य पुस्तकों से अलग कैसे है?

आज तक निम्नलिखित तीन विशेषताओं के साथ बाजार में कोई पुस्तक नहीं है:-

☞ हिंदी में जैव ईंधन पर पुस्तक

☞ दुनिया भर से जैव ईंधन पर नीतियों सहित पुस्तक

☞ आज तक बायोडीजल उत्पादन के लिए उपलब्ध सभी प्रौद्योगिकियों का संक्षिप्त संग्रह और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुस्तक आम आदमी की भाषा में लिखी गई है, ताकि कोई भी साधारण व्यक्ति अवधारणाओं को समझ सके।

★ क्या आप अपनी लेखन प्रक्रिया का वर्णन कर सकती हैं?

मैं कहूँगी, यह पुस्तक की बुनियादी रूपरेखा और संरचना के साथ शुरू हुआ था, जिसके प्रत्येक खंड के लिए गहन अनुसंधान और पाठ विकास का पालन किया गया। इसके साथ ही, व्याकरण और शब्दावली के संदर्भ में भाषा की जांच की गई। अंत में, पठन सामग्री को एक अंतिम टचअप दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन के साथ कि पुस्तक त्रुटि मुक्त है और सामग्री स्पष्ट तरीके से निर्धारित की गई है। आखिर में एक प्रकाशक को ढूंढना था जो एक पांडुलिपि को आकर्षक पुस्तक में बदल दे, जहां प्रतिलिपी मीडिया हाउस बेंगलुरु से मेरे प्रकाशक "द राइट ऑर्डर" मेरी सहायता के लिए आगे आए। अत: मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ।

★ आपकी पुस्तक लिखने का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा क्या था?

मुझे इस बारे में पूरा यकीन है। यह दुनिया भर के देशों की नीतियों के बारे में लिखना था। यह सुनिश्चित करना कि यह दर्शकों को बोर न करे और साथ ही सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रों को शामिल किया जा सके। इसके अलावा, हिंदी में तकनीकी पुस्तक लिखना एक आसान काम नहीं है।

★ आपकी पुस्तक लिखने का सबसे रोमांचक हिस्सा क्या था?

मुझे लगता है कि कवर पेज। मेरा मानना है कि पहली छाप अंतिम छाप है और पुस्तक का कवर पेज बहुत ही आकर्षक है।

★ समिधा जी, आखिर में आप हमारे रीडर्स से क्या कहना चाहेंगी?

मैं सभी से यही कहूँगी कि किताबें

पढ़ना आज भी ज्ञान का सबसे उचित माध्यम है, इसे अपनी जिंदगी का भाग बनाए रखिए। मेरी पुस्तक अवश्य पढ़ें, मुझे आपके समीक्षा और सुझावों का इंतजार रहेगा।

★ पुस्तक के लेखकों के बारे में जाने :-

समिधा बंका अग्रवाल, केमिकल इंजीनियरिंग (स्नातक) में महाविद्यालय में स्वर्ण पदक विजेता होने के साथ-साथ जीटीयू से संबंधित एल.डी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मास्टर की डिग्री में भी यूनिवर्सिटी गोल्डमेडलिस्ट हैं। उनके पास केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का शिक्षण अनुभव है। वे 1 पेटेंट, 2 कॉपीराइट्स और पीयर-रिव्यू किए गए पत्रिकाओं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 10 से अधिक पेपर की हकदार हैं। उन्होंने गुजरात के विभिन्न कॉलेजों में विशेषज्ञ व्याख्यान दिए हैं और 5 वर्षों से बायोडीजल उत्पादन के लिए प्रक्रिया गहनता के क्षेत्र में शोध कर रही हैं। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र केमिकल इंजीनियरिंग, जैव ईंधन, प्रक्रिया गहनता और केमिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग हैं। वे साथ-साथ ही एक ब्लॉगर, विद्याविद्, शोधकर्ता, अन्वेषक और पर्यवेक्षक भी हैं।

डॉ. सचिन प्रकाशभाई पारिख, ISTE, IICHE, FIE वर्तमान में गुजरात में तकनीकी शिक्षा के संयुक्त निदेशक हैं। उनके पास 25 से अधिक वर्षों का संयुक्त शिक्षण और औद्योगिक अनुभव है। वे कई संस्थानों और शैक्षिक बोर्डों के सदस्य और प्रमुख हैं। उनके पास कई पेटेंट, असंख्य शोध पत्र हैं और उन्होंने अपने करियर में कई पीएचडी छात्रों का मार्गदर्शन किया है। उन्हें GUJCOST और DST सहित विभिन्न प्रतिष्ठित एजेंसियों से अनुसंधान अनुदान और राष्ट्रीय ख्याति के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपना डॉक्टरेट और पोस्ट-ग्रेजुएशन प्रतिष्ठित एमएसयू, बड़ोदरा से किया है और स्नातक बैंगलोर विश्वविद्यालय से किया है।●

जन सरोकार से भटक रहा मीडिया
सोशल मीडिया पत्रकार बनाम प्रिंट मीडिया

● मिथिलेश कुमार

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति और नियति मीडिया की स्वतंत्रता के आधार पर ही परखी जाती है। मीडिया को कई बार जनता की आवाज और उसके अधिकारों के सजग प्रहरी के रूप में रेखांकित किया जाता है। उसकी इसी भूमिका और उससे की जाने वाली अपेक्षाओं से मिलकर बनते हैं, मीडिया के सरोकार या जनसरोकार। जिस तरह नाटक बिना दर्शकों की भागीदारी के नहीं खेला जा सकता वैसे ही सामाजिक सरोकारों के बिना पत्रकारिता असंभव है। कई तरह की ललित कलाएं स्वांत: सुखाय भी चलती हैं। यह अलग विषय है। यह भी संभव है कि ऐसे स्वांत: सुखाय के दौर में ही कुछ ज्ञानवर्द्धक और रोचक रचना हो जाय तो समाज के लिए दशकों तक काफी उपयोगी हो मनोरंजक हो। साहित्य की भी कई विधाओं की रचनाएं स्वांत: सुखाय हो सकती हैं-बल्कि यही माना जाता है कि काव्य रचना का बड़ा हिस्सा स्वांत: सुखाय ही होता है लेकिन पत्रकारिता, बिना समाज के संभव ही नहीं है। ऐसे में कोई यह मान ले कि पत्रकारिता समाज से मुँह फेरकर या उसे कम महत्व देकर चल सकती है तो यह उसका भ्रम हो सकता है।

बंगाल गजट जिसे टिकीज गजट भी कहते हैं। अविभाजित भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र है। 29 जनवरी, 1780 ई. को भारत में सबसे पहली बार किसी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। इसके प्रकाशन के छिआलिस वर्ष बाद भारत में हिंदी पत्रकारिता का उद्‌भव हुआ। कोलूटोटा, 37 आमड़ातल्ला गली, कलकत्ता से युगल किशोर शुक्ल के संपादन में 'उदंत मार्तण्ड' नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन ज्येष्ठ बदी 9 विक्रम संवत् 1883 तदनुसार 30 मई 1826 ई. में आरंभ हुआ। स्वाधीनता आंदोलन के समय पत्रकारिता को मिशन मानकर कई प्रतिभावान नायकों ने पत्रकारिता को भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का सहयोगी बनाया और निर्भीक पत्रकारिता की मशाल प्रज्ज्वलित की। पत्रकारिता के पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी ने पत्रकारिता के लिए ऐसे आदर्शों का परचम फहराया जिसे लेकर चलना कांटों भरा था, फतेहपुर जिला के राजनीतिक सम्मेलन का नेतृत्व करते हुए 1923 में उन्होंने कहा था- ष्मैं संग्राम का पक्षपाती हूँ। मैं समस्त सत्ताओं का विरोधी हूँ। फिर चाहे वह सत्ता मौजूदा नौकरशाही की हो या जमींदारी की, धनवानों की हो या ऊंची जातियों की इस संबंध में उन्होंने 29 जनवरी को हरदोई जेल में अपनी डायरी में लिखा था- 'जीवनभर अमानुषिकता, असज्जनता के विरुद्ध लड़ता रहा। ईश्वर बल दे कि आगे भी लड़ सकूं।'

पत्रकारिता के पुरोधा बाबू विष्णु राव पराड़कर ने समय की पत्रकारिता के गति के आधार पर आगे की पत्रकारिता और पत्रों के संदर्भ में जो भविष्यवाणी की थी उसके अनुसार पत्र निकालकर सफलतापूर्वक चलाना बड़े- बड़े धनियों अथवा सुसंगठित कंपनियों के लिए ही संभव होगा। पत्र सर्वांग सुंदर होगे। आकार बड़े होंगे, छपाई अच्छी होगी, मनोहर, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक चित्रों से सुसज्जित होंगे, लेखों में विविधता होगी, कल्पकता होगी, गंभीर गवेषणा की झलक होगी, ग्राहकों की संख्या लाखों में गिनी जाएगी। यह सब कुछ होगा पर पत्र प्राणहीन होंगे। उनका यह कथन आज की पूरी अखबारी पत्रकारिता पर शत-प्रतिशत खरा उतर रहा है।

बीसवीं शताब्दी संघर्षो कुछ नया कर गुजरने की शताब्दी रही है। इस शताब्दी के मध्य में भारत स्वतंत्र हो गया था और आजादी के बाद 'लोकतांत्रिक-समाजवादी' राष्ट्र के रूप में देश ने नया इतिहास लिखा। इस बीच दरभंगा महाराज ने आर्यावर्त हिंदी में और इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ किया वहीं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के संपादन में सर्चलाइट और दैनिक प्रदीप का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। दोनों कहें या चारों दैनिक अखबार ने बिहारी जनता को बिहारी जीवन के कई अछूते विषयों से रू-ब-रू कराया। कुछ दिनों तक बिहार में अखबार से मतलब दैनिक आर्यावर्त और दैनिक प्रदीप को माना गया। इसके बाद नवराष्ट्र, विश्वमित्र, दैनिक आज आगे चलकर दैनिक नवभारत टाईम्स फिर पाटलीपुत्र टाइम्स, दैनिक जनशक्ति, आत्मकथा, दैनिक प्रभात खबर और कई दैनिक साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं ने बिहार के विकास गाथा से पाठकों को रू-ब-रू कराया। और अखबारों ने सामाजिक क्रांति, सामाजिक सुधार, कला संस्कृति को स्थान दिया। उन दिनों की पत्रकारिता की विशेषता थी कि वे समन्वय के भावों को, विशिष्ट प्रतिभाओं को स्थान देते थे। रविवारीय अंकों को लोग सुरक्षित रखते। थे। अखबार जन सरोकार के प्रति सजग था। अखबारों के उन उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय जिसमें माना जाता है कि अखबारों की भूमिका समाज को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन प्रदान करना करना है का पालन कर रहे थे।

1990 में जो वैश्वीकरण या उदारीकरण की नीतियां सामने आयीं उसने छोटे उद्योगों, खान-पान, पहनावा, लोक संस्कृति, सिनेमा, आचार-विचार के साथ-साथ तेजी से समाज की सोच को प्रभावित करना शुरू कर दिया। आगे चलकर अखबारों या प्रिंट मीडिया के साथ दूरदर्शन और चैनलों के विस्तार ने मीडिया शब्द को व्यापक स्थान दिलाया। अब मीडिया से तात्पर्य है वह सब ढंग के संवाद-प्रेषण की इकाई से 21वीं शताब्दी नई तकनीकी और कंप्यूटरीकरण के नाम संवाद प्रेषण सहज हुआ

और चौनलों का प्रभाव बढ़ा है। उदारीकरण ने धीरे-धीरे राज्य की कल्याणकारी भूमिका को भी समाप्त कर दिया। इसका असर अब मीडिया में दिखने लगा है और धीरे-धीरे बाजार या कहें विज्ञापनदाताओं के इशारे पर नाचने लगे जिसके एवज में उनको पूरा विज्ञापन मिलने लगा। विज्ञापन आगे, संवाद पीछे, विचार विलुप्त, संस्कृति और साहित्य के नाम पर महानगरों के तथाकथित विद्वानों के टिप्स दिखाए और लिखे जा रहे हैं। साहित्यिक पत्रकारिता करने वालों की छुट्टी हो रही है। संपादक नामक संस्था बेहद कमजोर हो चुकी है। अब संपादक की भूमिका प्रबंधक की ज्यादा हो गई है। पिछले दिनों या आजकल बड़े मीडिया समूह के संपादक से अगर कोई वरिष्ठ पत्रकार पैरवी करता है तब संपादक की टिप्पणी होती है-'यार तुम तो अभी भी आदर्शवाद का पुराना राग अलाप रहे हो। अब मीडिया बहुत बदल गया है और आने वाले दिनों में और भी बदलेगा। अब किसी को जनसरोकार, विचारधारा, निष्पक्षता और ज्ञान नहीं! आदेश को लागू करने और टीम के साथ जुटकर काम करने की आवश्यकता है। आप अगर वैसे करके दिखाएंगे और समय के साथ बदलेंगे तो संस्थान में रहेंगे और तरक्की करेंगे नहीं तो बाहर हो जाएंगे। यह मात्र एक उदाहरण है, इस ढंग की स्थिति कायम है और मीडिया में व्यक्ति और विचार के स्तर पर जनसरोकारों को लगातार धकियाकर हाशिये पर लाया है। ऐसा इसलिए तो हुआ ही कि पत्रकारिता अब मिशन से प्रोफेशन बन गयी है साथ ही इसलिए भी हुआ कि ग्रोथ अब सामाजिक न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गयी है इसी के साथ यह भी है कि मीडिया के व्यवसाय में अब वैसे पूंजीपति और उद्यमी आ रहे हैं जिनका मकसद पत्रकारिता के माध्यम से समाज और सत्ता के रिश्तों के बीच हस्तक्षेप से कहीं ज्यादा आर्थिक लाभ और पक्षपाती राजनीतिक ताकत हासिल करना है।

आज से सत्तर साल पूर्व प्रेमचन्द ने अहसास किया था कि सामंतवाद, राजा, नवाबों के दिन लदने वाले हैं और आगे के समय में महाजन शक्तिसम्पन्न होंगे। उन्होंने महाजनी सभ्यता पर विस्तार से लिखा है। आज कारपोरेट घरानों का प्रभाव बढ़ा है। भूमण्डलीकरण के इस दौर में अंग्रेजी और अंग्रेजी के व्यापक प्रभाव का मुकाबला प्रेमचंद के देशी हथियार से किया जा सकता है? क्या आज फिर से प्रेमचंद तक पहुंचना पुरागमिता होगी? क्या यह चिंता का विषय नहीं है कि हम अपनी उसी देशी पहचान और विरासत को धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं जिसकी तरफ प्रेमचन्द और फणीश्वरनाथ रेणु जैसे लेखकों ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया था? आज हमारी अस्मिता के जितने टुकड़े जाति, उपजाति आदि के आधार पर होते जा रहे हैं वैसा जटिल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साम्प्रदायिक समस्याएं गंभीर हो गई है।

आज 21वीं शताब्दी की मीडिया की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह विकल्पहीनता के सिद्धांत पर काम करता है वह कभी नीति के स्तर पर तो कभी नेतृत्व के स्तर पर। यह जनता और जनसरोकारों का अपमान जैसा है। ऐसा प्रदर्शन प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक तरफ जनता के भीतर से उठने वाली वैकल्पिक चर्चा को दरकिनार कर देता है और दूसरी तरफ नए विचारों के विकास की संभावना

को नष्ट कर देता है। यह स्थिति अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की होती तो ज्यादा चिंता नहीं होती लेकिन यह उस प्रिंट मीडिया की भी बनी जो पिछले तीन सौ सालों से सच को उजागर करते हुए और तमाम क्रांतिकारी और राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रकाशन करते हुए बड़ा हुआ था। इस दौरान तेजी से विकसित हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या तो आतंकवादी एवं उग्रवादी हिंसा को दिखाते हुए लोकप्रिय हुआ या फिर साम्प्रदायिक आंदोलनों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हुए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हद तो उस समय कर दी जब उसने भूत-प्रेतों और ग्लैमर भरे नृत्यों को समाचार की तरह पेश करना शुरू कर दिया। वह अपने आलोचकों पर यह कहते हुए टूट पड़ता है कि आखिर हमने भारी पूँजी से खड़ा किया चैनल चलाना या देशसेवा करनी है।

मीडिया के संदर्भ में गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबू विष्णुराव पराड़कर ने भविष्यवाणी की थी वह आज सामने है। दैनिक समाचार पत्रों में जो अतिरिक्त रंगीन पृष्ठ होते हैं उसकी रंगानी तेवर पिता-पुत्र एक साथ बैठकर अखबार का रंगीन पृष्ठ जिसमें महज फिल्मी अभिनेत्रियों के फूहड़ किस्म के बड़े-बड़े चित्र छपने लगे हैं नहीं देख सकते। आजकल नगरों और महानगरों के लेखक जैसे कमरा नम्बर एक, प्लेटफार्म नम्बर दो नाम से साहित्यिक सामग्री परोस रहे हैं ठीक इसी तरह अब दैनिकों में हैलो दिल्ली, हैलो पटना जैसा शीर्षक लगने लगा है। 1994 के बाद अखबारों ने पाठकों की रुचि को संवारने के बजाए बिगाड़ने और बाजारानुकूल तालमेल के साथ कारपोरेट कंपनियों के हितों के लिए काम करना शुरू किया है। यह पिछले 28 वर्षों से चलते हुए चरम पर आ पहुँचा है। अब मीडिया का काम चोर को चोरी करने और चौकीदार को पहरा देने का हो गया है। स्थानीय जिसे आंचलिक कहा जाता है, की खबरों में हिंसा, मारकाट को प्रमुखता मिलती है, सबसे अच्छा रपट या संवाद अपराध वाले कार्यक्रमों को मिलती हैं। प्राय: जब संवाददाताओं की बैठक होती है तो मीडिया के संचालक बड़े घराने से जुड़े संपादक आयोजित कार्यशालाओं में संवाददाताओं को निर्देश देते हैं वही खबरें छापिए जो सकारात्मक हों और देश की अर्थव्यवस्था की खुशनुमा तस्वीर पेश करे। जैसे कि क्रिकेट में देश की जीत शेयर बाजार का उछाल, मध्यमवर्ग के प्रोफेशनलों का ऊंचा वेतन, किसी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी की बड़ी-छोटी उपलब्धि और किसी कंपनी के विकास वगैरह। उन कार्यशालाओं में हिदायत दी जाती है कि कहीं मजदूरों की छंटनी और किसानों की आत्महत्या की खबर हो तो उसे प्रमुखता नहीं दी जाय। कारपोरेटों के नियंत्रण में चलने वाली मीडिया लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है कारण लोकतंत्र की शक्ति विविधता और बहुलता में निहित होता है। भारतीय संविधान में श्लोकतंत्र के साथ समाजवादश को जोड़ा गया है अर्थात् लोकतंत्र के साथ समानता कायम हो और शोषण-दोहन का अंत हो। इस बारे में प्रेस परिषद् के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी. सी. सावंत, प्रभात जोशी और दूसरे कई समाज के हित चिंतकों ने सुझाव दिए हैं। देश में सहकारिता और दूसरे तरीकों से नया मीडिया खड़ा करने की कोशिशें चल रही हैं। कहीं सफल है, कहीं असफल। आज लगातार धुंधलाते जनसरोकारों को नए सिरे से खोजने और उसे मीडिया की आत्मा के रूप में प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है।●

लेखक :-राम रतन सिंह रत्नाकर
वरिष्ठ साहित्यकार
मकनपुर, नवादा

सारस पर सियासत

उत्तर प्रदेश में अमेठी के मोहम्मद आरिफ के पास एक साल से रह रहे सारस पक्षी को वन विभाग ले कर चला गया है। आरिफ ने घायल सारस का इलाज किया था उसके बाद से वो पक्षी उनके पास ही रहने लगा। वो आरिफ के साथ ही खाना खाता और घूमता था। आरिफ का कहना है कि उन्होंने उस सारस को कभी कैद में नहीं रखा वो एक आजाद पंछी था। उनका ये भी कहना है कि इससे पहले वन विभाग का कोई अधिकारी इस बारे में उससे जानकारी लेने नहीं आया। सारस और आरिफ की कहानी मीडिया में देखने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आरिफ और उस सारस से मिलने अमेठी गए और उनके साथ ली गई तस्वीर भी साझा की। वन विभाग की कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वन सारस को इसलिए ले जाया गया क्योंकि उन्होंने आरिफ और सारस से मुलाकघत की थी। जिसके बाद इस मामले पर राज्य में सियासत तेज हो गई है।

☞ **अखिलेश यादव ने क्या कहा?** :- लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद आरिफ भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने आरिफ के बारे में कहा, 'उन्होंने सारस के साथ दोस्ती दिखाई और उसकी सेवा की जिससे ये इनका मित्र बन गया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई सारस किसी इंसान के साथ रहे और उसका व्यवहार बदल जाए। यह तो शोध का विषय है कि सारस इनके पास कैसे रुक गया।' इस दौरान अखिलेश ने आरोप लगाया कि, 'इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं मिलने चला गया था। क्या यही लोकतंत्र है? अगर सरकार सारस को छीन रही है, तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुँच जाने की। किसी अधिकारी की हिम्मत है कि वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह सिर्फ इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल कर आ गया।'

☞ **प्रियंका गांधी ने भी किया आरिफ का समर्थन** :- कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी वन विभाग की इस कार्रवाई के बारे में फेसबुक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, 'अमेठी के रहने वाले आरिफ और एक सारस पक्षी की दोस्ती, जय-वीरू की तरह थी। साथ-साथ रहना, साथ खाना, साथ आना-जाना। उनकी दोस्ती इंसान की जीवों से दोस्ती की मिसाल है। आरिफ ने उनके प्रिय सारस को घर के सदस्य की तरह पाला, उसकी देखभाल की, उससे प्यार किया। ऐसा करके उन्होंने पशु-पक्षियों के प्रति इंसानी फर्ज की नजीर पेश की है जो कि काबिल-ए-तारीफ है।' उन्होंने ऑस्कर अवार्ड पाने वाली भारत की डॉक्यूमेंट्री एलिफैंट व्हिस्पर्स का हवाला देते हुए लिखा, 'द एलिफैंट व्हिस्पर्स को ऑस्कर मिला जो एक हाथी और इंसान की संवेदनशील कहानी पर आधारित है। ये कहानियां हमें इसलिए भावुक करती हैं क्योंकि मनुष्य का जीवन और पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने भी सहजीवन हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।' 'सरकारों का भी यही काम है कि ऐसी कहानियों से प्रेरणा लें और वन्य जीवों व इंसानों के बीच मोहब्बत भरे रिश्ते से संवेदना के मोती चुनें।'

☞ **क्या है सरकार का कहना?** :- अमेठी के स्थानीय रिपोर्टर्स से 20 मार्च की एक सरकारी चिट्ठी मिली है जिसमें उत्तर प्रदेश के अपर प्रधान मुख्य संरक्षक सुनील चौधरी ने अमेठी के वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी को उनके 14 मार्च के पत्र का जवाब देते हुए लिखा है कि, 'मोहम्मद आरिफ के घर के आस-पास व खेतों में सारस पक्षी को देखा गया है। आपसे उस सारस पक्षी को उसके प्राकृतिकवास समसपुर पक्षी विहार में छोड़ने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है। आपको यह भी अवगत कराया गया है

कि सारस पक्षी को उक्त स्थल पर छोड़ने के लिए जनपद अमेठी से एक राजकीय पशु चिकित्सक साथ में सहयोग के लिए जाएंगे।' पत्र में अतएव वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-48 । में मौजूद अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अमेठी में आरिफ के घर के आस-पास व खेतों में पाए गए सारस पक्षी को समसपुर पक्षी विहार में उसके प्राकृतिकवास में छोड़ने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अपर प्रधान मुख्य संरक्षक सुनील चौधरी और अमेठी के वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी डीएन सिंह दोनों से फोन पर इसकी पुष्टि करने की कोशिश की गई और साथ ही समसपुर पक्षी विहार के रेंजर से सारस की मौजूदा हालत के बारे में जानने की कोशिश की लेकिन किसी से भी फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। पत्रकार विवेक कुमार मौर्या ने रायबरेली के क्षेत्रीय वन अधिकारी, रुपेश श्रीवास्तव से सारस को समसपुर पक्षी विहार में रखने के बारे में बात की। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सारस पक्षी को समसपुर के पक्षी विहार में 21 मार्च को छोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि पक्षी को खुला छोड़ दिया गया है और किसी कमरे में नहीं रखा गया है। ये भी जानकारी दी कि सारस को पक्षी विहार एसडीओ लेकर आए थे। रुपेश श्रीवास्तव ने बताया कि, 'सारस फिलहाल पक्षी विहार परिक्षेत्र में है।' अगर पक्षी यहां से उड़ जाता है तो क्या उसे वापस विहार में लाया जाएगा? इस पर रूपेश श्रीवास्तव ने कहा, 'अगर कहीं गाँव में चला जाता है या घर में चला जाता है तो उसे वापस लाया जाएगा।' अधिकारीयों के मुताबिक सारस अपने आप खा रहा है लेकिन फिर भी उसे अलग से गेहूं, पानी और रोटी दी जा रही है। तो क्या मोहम्मद आरिफ समसपुर में सारस को देखने आ सकते हैं? इस पर क्षेत्रीय वन अधिकारी रुपेश श्रीवास्तव ने कहा कि, 'वो आ सकते हैं और टिकट लेकर देख सकते हैं। पहचान पाएंगे तो पहचान भी लेंगे।'

☞ **सारस संरक्षण के बारे में क्या कहते हैं जानकार? :-** संवाददाता गीता पांडेय ने सारस के संरक्षण के बारे में और जानने के लिए वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के समीर कुमार सिन्हा से बात की। समीनर सिन्हा के मुताबिक, 'किसी भी संरक्षित पक्षी या जानवर को रखना गैरकानूनी है। उन्हें खिलाना पिलाना भी गैरकानूनी है।' समीर सिन्हा के मुताबिक संरक्षण और करुणा दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो कहते हैं, 'आप किसी पक्षी को बचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको उसे कघनूनी तौर पर सुपुर्द करना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरे भी ऐसे पक्षी पाल सकते हैं।' समीर सिन्हा का यह भी कहना है कि, 'जंगली जानवरों की जंगली प्रवृत्ति होती है। तब क्या होता अगर वो पक्षी किसी पर हमला करता?' सारस के बारे में और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि, 'सारस एक राजकीय पक्षी है। सही यह होगा की हम वेटलैंड्स को बचाने की कोशिश करें और पक्षी के हैबिटैट को बचने की कोशिश करें। फिर प्रकृति अपना काम खुद्द करेगी।' ●

उसे छोड़ दें, वो मेरे पास वापस आ जाएगा : आरिफ

अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद बीबीसी हिंदी ने मोहम्मद आरिफ से सपा कार्यालय के बाहर बात की। आरिफ ने बताया कि वन विभाग की टीम मंगलवार को सारस को लेकर चली गई थी। आरिफ ने एक वीडियो भी बीबीसी हिंदी को दिया जिसमें सारस को एक टेंपो में रखकर ले जाया जा रहा है। मौके से जुड़े कुछ वायरल वीडियो में आरिफ निराशा से भरे नजर आ रहे हैं। आरिफ ने बीबीसी को बताया कि वन अधिकारियों ने उनसे कहा कि, 'ऊपर से आदेश आ गया है, ये समसपुर (पक्षी विहार) जाएगा।'

आरिफ से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी वन विभाग से संपर्क कर सारस के बारे में जानकारी दी थी, तो उन्होंने ने कहा, 'मुझे वाइल्ड लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं खेती किसानी करता हूँ। तो उस विषय में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। पर इतना जानता हूं कि जब हम इसको कैद करेंगे, बाँध के रखेंगे, जकड़ कर रखेंगे, तब तो वन विभाग का वो सवाल उठता है। वो अपने स्वयं इच्छा से आता था।' आरिफ ने माना कि सारस एक संरक्षित पक्षी है और उसे पक्षी विहार ले जाकर वन विभाग अपना काम ही कर रही हैं। तो फिर आरिफ को क्या आपत्ति है? इस बारे में वो कहते हैं, 'हमें कोई समस्या नहीं है। हमने उसे किसी तरह से बाँध के तो रखा नहीं था। कैद करके नहीं रखा था। वो खेतों में घूम रहा था, जहाँ जी करता था उड़ जाता था। वापस आ जाता था। ना कभी पकड़ कर रखे थे, ना बांध कर रखे थे। वन विभाग का वाइल्ड लाइफ का क्या नियम है, हमें ज्यादा मालूम नहीं है। बस वो लोग ले गए।' आरिफ कहते हैं कि सारस को पास के समसपुर पक्षी विहार ले गए हैं। आरिफ का दावा है कि वन विभाग के अधिकारियों ने उनसे कहा कि वो समसपुर पक्षी विहार के पास 20 से 25 दिन दिखाई न दें। अंत में आरिफ ये भी कहते हैं कि, 'आगे उसको छोड़ दें, वो वापस आ जाएगा मेरे पास।'

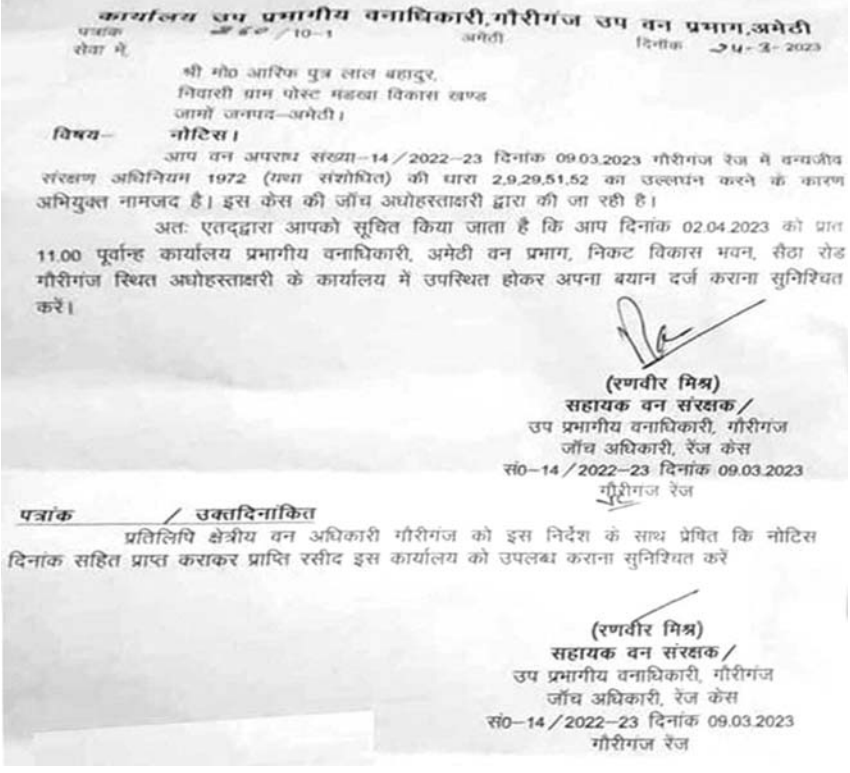

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौरीगंज उप वन प्रभाग, अमेठी

पत्रांक [illegible]/10-1 अमेठी दिनांक 24-3-2023

सेवा में,

श्री मो० आरिफ पुत्र लाल बहादुर,
निवासी ग्राम पोस्ट मंडखा विकास खण्ड
जामों जनपद-अमेठी।

विषय- नोटिस।

आप वन अपराध संख्या-14/2022-23 दिनांक 09.03.2023 गौरीगंज रेंज में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) की धारा 2,9,29,51,52 का उल्लंघन करने के कारण अभियुक्त नामजद है। इस केस की जाँच अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जा रही है।

अतः एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 02.04.2023 को प्रातः 11.00 पूर्वान्ह कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग, निकट विकास भवन, सैठा रोड गौरीगंज स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

(रणवीर मिश्र)
सहायक वन संरक्षक/
उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौरीगंज
जाँच अधिकारी, रेंज केस
सं0-14/2022-23 दिनांक 09.03.2023
गौरीगंज रेंज

पत्रांक / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी गौरीगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नोटिस दिनांक सहित प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें

(रणवीर मिश्र)
सहायक वन संरक्षक/
उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौरीगंज
जाँच अधिकारी, रेंज केस
सं0-14/2022-23 दिनांक 09.03.2023
गौरीगंज रेंज

सीएनजी व पीएनजी की कीमतों में आयेगी कमी

● रीता सिंह

घरेलू फील्डों से निकाले जाने वाली गैस की कीमत तय करने को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने किरीट पारिख समिति की रिपोर्ट के कुछ हिस्से को स्वीकार करते हुए नई कीमत नीति को मंजूरी दी है। इस फैसले पर सरकार लंबे समय तक अमल में करना चाहती है। वजह यह है कि यह ना सिर्फ देश में सीएनजी व पीएनजी की खपत को बढ़ावा देगा बल्कि घरेलू बाजार में गैस कीमतों को लेकर एक स्थिरता बना कर रखेगा। इस फैसले से देश में सीएनजी व पीएनजी की कीमतों में 11 फीसदी तक की कमी आने की संभावना जताई जा रही है। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती को देखते हुए भाजपा भी इसे चुनावी साल में खूब प्रचारित करने की योजना बना कर चल रही है। कैबिनेट ने किरीट पारिख समिति की रिपोर्ट के कुछ हिस्से को स्वीकार करते हुए ही नई कीमत नीति को मंजूरी दी है। अगर समिति की पूरी सिफारिशें लागू की गई जाती तो घरेलू गैस की कीमतों में और वृद्धि हो जाती। माना जा रहा है कि पिछले एक वर्ष में पीएनजी व सीएनजी की कीमतों में भारी वृद्धि के मद्देनजर केंद्र सरकार चुनावी साल में इन दोनो में और वृद्धि करने का जोखिम नहीं लिया है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने गुरुवार को जो फैसला किया है, उसके मुताबिक देश के पुराने गैस फील्डों से निकालने जाने वाली प्राकृतिक गैस की कीमत हर महीने तय होगी। यह कीमत हर महीने जिस दर पर भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल की खरीद करता है उसकी 10 फीसद होगी। लेकिन इसकी सीमा चार डॉलर से 6.50 डॉलर प्रति यूनिट ही होगी। यानी क्रूड की खरीद बहुत ज्यादा कीमत पर हो तब भी घरेलू कीमत 6.50 डॉलर से ज्यादा नहीं होगी और क्रूड कीमत में भारी गिरावट आ जाए तब भी यह चार डॉलर प्रति एमएमबीटीयू (मिलियन मैट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट- गैस मापने की इकाई) से कम नही होगी। फार्मूला लागू होने से अभी जिन फील्डों से कंपनियों को 8.57 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू दी जा रही है वह घट कर 6.50 डॉलर हो जाएगी।

भाजपा की तरफ से बताया गया है कि इस फैसले से दिल्ली में सीएनजी की कीमत 5.97 रुपये प्रति किलो घट कर 73.59 रुपये और पीएनजी की कीमत छह रुपये घट कर 47.59 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। पीएम नरेन्द्र मोदी ने इस फैसले के बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि इस फैसले से घरेलू उपभोक्ताओं को कई तरह के फायदे होंगे। यह पूरे सेक्टर के लिए एक सकारात्मक कदम है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव से ग्राहकों को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

☞ **क्रिसिल ने कहा-गैस की कीमत में स्थिरता आएगी :-** क्रिसिल रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा है कि इस फैसले से पीएनजी व सीएनजी की कीमतों में 9 से 11 प्रतिशत की कमी आने वाली है। इससे देश में गैस की कीमत में काफी स्थिरता आएगी व वैकल्पिक ईंधनों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। अगर पहले का फार्मूला लागू होता तो गैस कीमतें मौजूदा स्तर से बढ़कर 11 डालर प्रति यूनिट हो जाती। बता दें कि बीते दो वर्षों के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गैस कीमतें काफी अस्थिर रही हैं। घरेलू बाजार में इस दौरान गैस की कीमत 1. 79 डालर प्रति यूनिट से लेकर मौजूदा 8.57 डालर प्रति यूनिट रही है।

☞ **ऑटो उद्योग ने कहा-मिलेगी राहत :-** घरेलू ऑटो मोबाइल उद्योग ने गैस कीमत तय करने के फैसले का स्वागत किया है। आटोमोबाइल सेक्टर के सबसे बड़ा संगठन सियाम के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल ने कहा है कि घरेलू ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता से बचाने का फैसला देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बड़ी राहत है। इससे सीएनजी गाडिघ्यों की मांग बढ़ेगी और स्वच्छ ईंधन ज्यादा लोकप्रिय बनेगा। घरेलू स्तर पर प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होगी। ●

नीतीश सरकार की दोगली नीति बहाना इफ्तार पार्टी

बिहार में सियासी इफ्तार का दौर शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीएम आवास में इफ्तार पार्टी देंगे. मुख्यमंत्री ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है. मुख्यमंत्री आवास में दिए जाने वाले इफ्तार पार्टी की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही है. नीतीश कुमार जब से बिहार में सत्ता संभाले हैं कोरोना के काल को छोड़ दें तो हर साल इफ्तार पार्टी देते रहे हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बीजेपी विपक्ष में रही है तब मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टियों को लेकर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है. इस बार भी इफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री पर बीजेपी निशाना साध रही है. महागठबंधन के घटक दलों के साथ बीजेपी के नेताओं को भी आज के इफ्तार में आमंत्रित किया गया है. देखना यह होगा कि नीतीश के इफ्तार में बीजेपी के नेता शामिल होंगे कि नहीं? **रिपोर्ट :- रीता सिंह**

बिहार में शराबबंदी है : कितना सच?

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति का सच क्या है इसे बिहार के लोग खूब अच्छी तरह समझ चुके हैं। किंतु बिहार के बाहर इस नीति का नगाड़ा इतना बज रहा है कि बिहार से बाहर के लोग इस नीति के प्रति काफी आकर्षित हो रहे हैं। मुख्य मंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी एक जन कल्याणकारी नीति है और अगर यह सही तरीके से जमीन पर लागू हो जाए तो अपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित कमी आ सकती है, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि लाख ढोल पीटने के बावजूद बिहार में शराबबंदी की स्थिति यह है कि इसे शत-प्रतिशत असफल कहा जा सकता है। होली के अवसर पर शराबबंदी का नंगा सच सब ने देखा। पूरा का पूरा शहर और गांव का गांव शराब खोरों के हवाले रहा। सज्जनों का घर से निकलना मुश्किल था शराबबंदी कानून के बाद से बिहार में अवैध रूप से शराब बनाने और बेंचने का कारोबार फल-फूल रहा है। सच्चाई तो यह है कि शराब बनाने का धंधा बिहार में कुटीर उद्योग का रूप ग्रहण कर चुका है। बहुत से चाय बेचने वाला अब शराब बेचने में लग गया है। शराब की होम डिलीवरी होने लगी है कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफे का बिजनेस बन चुका

है शराब बनाने की भट्टी बिहार के गांव में एक आसान रोजगार बन चुका है। इस नीति के प्रति बिहार के बाहर एक ग्लैमर बना हुआ है। इसी ग्लैमर के कारण बिहार की शराबबंदी की चर्चा अन्य राज्यों में होती है, दरअसल शराबबंदी एक अच्छी नीति है लेकिन सरकार की नियत भी ठीक होनी चाहिए। शराबबंदी का वास्तविक रूप देखना है बिहार से बाहर के प्रतिनिधियों को गोपनीय ढंग से बिहार का भ्रमण करना चाहिए होली के अवसर पर बिहार में शराब की सहज उपलब्धता ने प्रमाणित कर दिया है बिहार में शराबबंदी का सच क्या है। बिहार में शराबबंदी कैसे सफल हुआ यह जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से एक टीम आई थी। इस 20 सदस्यीय टीम में छत्तीसगढ़ के 8 विधायक और 12 अधिकारी शामिल थे। उत्पाद अधिकारियों के अनुसार टीम में सात बार विधायक रहे क्योंकि पूर्व मंत्री सतनारायण शर्मा के नेतृत्व में आई थी। विधायकों में द्वारिका धीश यादव, रश्मि आशीष सिंह, शिशुपाल सॉरी ,गुंडर देही, कुंवर सिंह निषाद संजरी संगीता सिन्हा दिलेश्वर साहू और पुरुषोत्तम कुमार शामिल थे। इस टीम में शामिल आबकारी आयुक्त निरंजन दास, विभाग के विशेष सचिव एसपी त्रिपाठी, अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव, रामपुर के सहायक जिला आबकारी राजीव झा आदि मौजूद थे। बिहार में शराबबंदी से उत्साहित होकर बिहार का गुणगान करते वापस लौटे। बताया जाता है कि बिहार से सीख कर गए लोगों ने बिहार के तरह पूर्ण शराब मुक्त करेंगे।●

अमेरिका में राष्ट्रव्यापी हिंदू संगठन बना संघ, 34 प्रांतों में चल रही है शाखा

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने बताया कि भारत के प्रमुख हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कि अमेरिकी संगठन ने सदस्यों और शाखाओं की संख्या में तेजी से विस्तार किया है। जिससे इसके सदस्यों, शाखाओं की संख्या तीन गुना से अधिक हो गई है। अब भारत से बाहर अमेरिका में इसकी सबसे ज्यादा शाखाएं है। एचएसएस अमेरिका में सबसे बड़ा हिंदूवादी संगठन बन गया है। अमेरिका के 50 प्रांतों में से 34 प्रांतों में इसकी शाखाएं हैं और देश भर के 160 शहरों में 260 साप्ताहिक शाखाएं लगती है। इसके 30,000 से अधिक सदस्य हैं जो 2010 के बाद से तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। 2022 तक शाखाओं के नियमित उपस्थिति 10000 से 12000 के बीच है लेकिन अगर एच एस के

कार्यक्रमों और संघ परिवार समर्थित परियोजनाओं में कभी-कभी उपस्थिति या भागीदारी को गिनें तो समर्थकों की संख्या 5 लाख से अधिक हो जाती है। जबकि अमेरिका में भारतवंशी अमेरिकीयों की संख्या करीब 40 लाख है। एचएसएस और उसके सहयोगी समूह -वर्ल्ड हिंदू काउंसिल ऑफ अमेरिका, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल सक्रिय है जो कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों में सक्रिय है 500 से अधिक विश्वविद्यालयों कॉलेजों और स्कूलों में इनकी यूनिट है जहां यह हिंदुओं और गैर हिंदुओं के बीच हिंदू धर्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए फेलोशिप कार्यक्रम चलाता है हिंदू नेता बिंदु पटेल ने कहा कि इस समाज को देने की भावना के साथ सेवा दिवाली भोजन वितरण जैसे अभियान समुदायों के बीच चलाता है।●

मोबाइल या व्हाट्सअप कॉल उठाने से पहले सावधान?

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

अनजान नम्बर से फोन आने पर सावधान हो जाएं, कुछ ही मिनटों में आपके एटीएम कार्ड के बारे में जानकारी, आपको ईनाम मिलने के बारे में सूचना या फिर आधार कार्ड और बैंक कार्ड अपडेट किये जाने के बारे में कोई मैडम आपके मोबाइल पर सूचना देती है। तरह-तरह के एसएमएस आपको चेतावनी देते हैं और सावधान भी करते हैं कि आपको लिंक भेजा जा रहा है, आपके खाते में पैसे आ रहे हैं तो हमें डिटेल दीजिए। कृपया सावधान हो जाइये, ये सब साइबर क्राइम हैं और आपको लूटने के तरीके इजाद किये जाते हैं। नई कड़ी में एक बुजुर्ग के पास व्हाट्सऐप कॉल गई और उसने उठा ली। फिर आवाज आई सामने देख और जब बुजुर्ग ने मोबाइल पर सामने देखा तो एक डर्टी पिक्चर उभर आई। लगभग 20 सैकेंड तक बुजुर्ग समझ नहीं पाया और दूसरे ही दिन एक अलग नंबर से उन्हें फोन आया कि आपने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की है और इसका वीडियो हमारे पास है। (दरअसल जब बुजुर्ग ने 20 सैकेंड तक वीडियो देखा था तो उन्होंने बुजुर्ग की फोटो उस लड़की के साथ जोड़ दी थी।) यह बुजुर्ग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गया और दो लाख रुपये देकर छूटा। मरता क्या न करता। आजकल ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है। यूथ को मोबाइल पर लड़कियां बातों में बरगला लेती हैं और फिर उनसे ब्लैकमेलिंग करके पैसे ऐंठती हैं। फेसबुक हो या व्हाट्सएप कॉल सावधान रहने का समय आ गया है। सामाजिक होने के नाते सैकड़ों लोगों के फोन मुझ तक आते हैं और ये फोन उन लोगों के हैं जिनके घरों में से कोई न कोई साइबर क्राईम के तहत लूट का शिकार हो चुका है। सवाल पैदा होता है आखिर हम कैसे बचें? जरा भी आप चूक गए या किसी भी आए हुए मैसेज पर क्लिक कर दिया तो समझो आपकी सारी जमा पूंजी एक ही झटके में लुट जायेगी। आखिरकार हमें बचने के तौर-तरीके भी इजाद करने होंगे। आज के कंप्यूटर युग में घर बैठे सुविधा कौन नहीं चाहता लेकिन हमें टैक्नोलॉजी के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे साइबर क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे पकड़ पाना कठिन काम है।●

आईआईटी पटना को बिहार राज्य के लिए नोडल केन्द्र बनाया गया

● रीता सिंह

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के साथ जोड़ा गया है। आईआईटी पटना और एनआईटी त्रिची क्रमशः दोनों राज्यों के लिए समन्वयक संस्थान हैं। 18-30 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा 9 अप्रैल, 2023 तक https ://ebsb-aicte.india.org पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। पूरे बिहार से 45 छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें तमिलनाडु भेजा जाएगा। और इसी तरह, एनआईटी त्रिची यात्रा के समय को छोड़कर इस अभियान के तहत 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए तमिलनाडु के युवाओं को बिहार भेजेगा। इस एक्सपोजर टूर के दौरान छात्रों को उस राज्य में स्थित ऐतिहासिक महत्व की समृद्ध विरासत को जानने और समझने का भी अवसर मिलेगा। इसके साथ ही इन चयनित छात्रों को राज्य के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। दोनों राज्यों के युवाओं की यात्रा जोड़ीदार राज्यों के बीच विचारों, ज्ञान और कौशल के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। ●

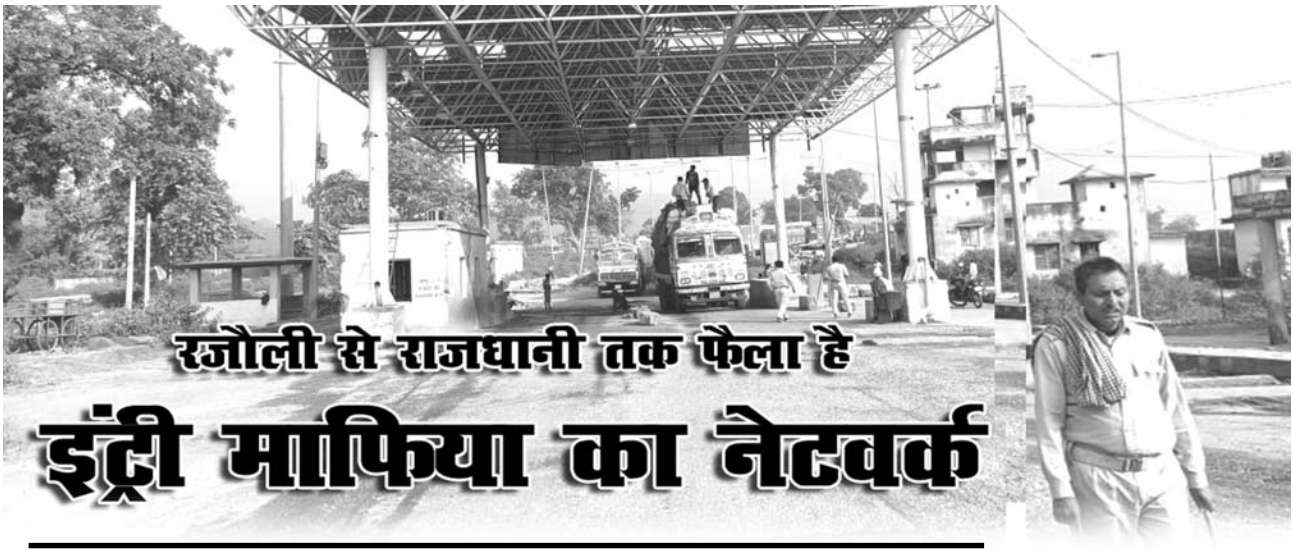

रजौली से राजधानी तक फैला है इंट्री माफिया का नेटवर्क

● कृष्णा कुमार चंचल/मनीष कमलिया

जिले के बिहार-झारखंड सीमा पर रजौली प्रखंड क्षेत्र के चितरकोली पंचायत अंतर्गत समेकित जांच चौकी पर इंट्री का धंधा परवान पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को बदल कर 20 किया गया है।इस पर इन दिनों इंट्री माफिया के काले धंधे में शामिल लोग चांदी काट रहे हैं। इंट्री माफिया का नेटवर्क रजौली से राजधानी तक फैला है। प्रतिदिन जांच चौकी से हजारों ट्रकों का आवागमन होता है। कहने को अधिकारी लगातार कार्रवाई करते हैं,पर सच यह है कि महीने में कभी कभार कार्रवाई होती है। रजौली जांच चौकी पर बड़े ही आराम से इंट्री माफिया अपने इस गोरखधंधे को अंजाम देते हैं। काले कारनामे से सरकारी राजस्व को भारी चूना लगाने का खेल जारी है। आखिर कैसे बेखौफ इंट्री माफिया अपना जलवा रजौली के नेशनल हाईवे पर कायम रखे हुए हैं और इनको किनका संरक्षण प्राप्त है? यह जांच का विषय है। सूत्रों कि मानें तो तो इंट्री माफियाओं की सांठगांठ अधिकारियों से लेकर गृहरक्षकों तक है जो इनके लिए जासूसी का काम करते हैं। कब निकलना होता है या कब नहीं यह उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार ट्रकों को निकालते हैं। इसके अलावा जांच चौकी पर तैनात गृहरक्षकों के द्वारा वाहनों से दिन दहाड़े ओवरलोड ट्रकों से पैसा लेकर बिहार में आसानी से प्रवेश करा दे रहे हैं। इनसे अगर पूछताछ की जाए तो सभी माफियाओं के नामों का खुलासा आसानी से हो सकता है गृहरक्षक जवान जांच चौकी पर तैनाती करने के लिए लिए हमेशा लालायित रहते हैं। क्योंकि यहां अवैध काली कमाई भरपूर रूप से होती है।

☞ **क्या है इंट्री खेल का राज:-** पिछले कई वर्षों से इंट्री का खेल बंगाल एवं झारखंड के रास्ते बिहार में प्रवेश करने वाले वैसे ट्रकों की होती है जिसमें विना कागजात, ओवरलोड, अवैध सामान आदि लदा होता है। उन्हें सुरक्षित तरीके से राज्य के कई जिले से गंतव्य तक जाने के लिए शुल्क तय कर दी गई है।

जब तक इंट्री के धंधे में शामिल लोगों के द्वारा चालकों से राशि वसूल नहीं कर ली जाती तब तक उस ट्रक को इंट्री नहीं मिलती है। अगर जोर जबरदस्ती कर ट्रक चालक चल भी देता है, तो किसी न किसी बहाने उसको पकड़वा दिया जाता है। इसके बाद ओवरलोड या फिर कागजातों में कमी आदि के नाम पर कार्रवाई की जद में आकर ट्रक मालिक को नुकसान झेलना पड़ता है। वसूले गये रूपये में पदाधिकारियों व उनके चमचों में वितरण किया जाता है जिसे माफिया इंट्री का नाम देते हैं। यही कारण है कि मजबूर ट्रक चालकों को समझौता करना पड़ता है। निर्माण सामग्रियों को ढोने वाले ज्यादा निशाने पर रहते हैं। इलाके में भवन, सड़क, पुल-पुलिया आदि के निर्माण सामग्री को धोने वाले ट्रक को एंट्री दिलाने में दिन-रात इंट्री माफिया का दलाल सक्रिय रहते हैं। सैकड़ों ट्रकों पर आए दिन गिट्टी आदि समान लदे बिहार में बेरोकटोक सड़कों पर प्रवेश इनके द्वारा कराया जाता है। उनसे मोटा उगाही कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इससे सरकारी राजस्व का चूना लग रहा है।

☞ **रोली से राजधानी तक भरे हैं इंट्री माफिया सरदार :-** बंगाल-झारखंड से आने वाले ट्रकों का झारखंड सीमा समाप्त होते ही बिहार के समेकित जांच चौकी से प्रवेश करते ही इंट्री माफिया के ट्रक वालों के साठ-गांठ का एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। जिसके मार्फत इंट्री का खुलेआम खेल खेला जाता है। सूत्रों की मानें तो इस काले धंधे में सफेदपोशों के सांठगांठ से इंट्री माफिया बड़े ही सुनियोजित तरीके से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। विश्वनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दर्जनों लोग वाहन इंट्री के इस गोरखधंधे में शामिल हैं। इनलोगों के सहयोग से इंट्री माफिया रजौली से लेकर राजधानी तक बैठकर समेकित जांच चौकी रजौली को चला रहे हैं। पूर्व में जांच चौकी से दलालों के द्वारा जब्त गाड़ियों को मारपीट कर जबरन छुड़ाया गया था। जांच चौकी पर पूर्व में आरटीओ ललित दूबे के द्वारा गिट्टी

लोड ट्रक एवं हाइवा ट्रक को जब्त किया था जिसे जबरन वाहन इंट्री करने वाले दलालों ने चालक को मारपीट कर छुड़ा लिया था। दूसरी बार भी गिट्टी लोड हाईवा ट्रक को जब्त किया गया था। जिसे इंट्री माफिया का सरगना सह तथाकथित मुखिया अरूण कुमार के द्वारा गुर्गों के सहयोग से जबरन धक्का मुक्की कर छुड़ा लिया गया था। जिसके बाद थाने में तात्कालिक आरटीओ ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

☞ **कौन ओर कहां का है इंट्री माफिया:-** सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इंट्री माफिया की फेहरिस्त लम्बी है। इनमें से प्रमुख हैं:-रजौली चितरकली के मुन्ना यादव व अमांवां के टुन्ना कुमार, नेमदारगंज थाना क्षेत्र के दुधैली के शंकर पाण्डेय, बुन्देलखण्ड थाना क्षेत्र अंसार नगर के मो जावेद वह मोगलाखार के मो अकील खान, नगर थाना क्षेत्र के मो मिस्टर व मो गोल्डन वह मंगरबिगहा के मुकेश यादव, नालन्दा जिला बिहारशरीफ के शिवम् कुमार, सुबोध यादव उर्फ टाइगर के साथ पटना के रहने वाले सोनू कुमार प्रमुख हैं।

☞ **क्या कहते हैं अधिकारी;-** इस बाबत डीटीओ अनुराग कुमार ने बताया कि इंट्री माफिया का मामला मेरे संज्ञान में नहीं हैं। जब भी जांच चौकी का औचक निरीक्षण किया जाता है त्रुटिपूर्ण वाहनों से जुर्माना राशि की वसूली की जाती है। ●

अपराध और भ्रष्टाचार की पोषक हो चुकी है वर्तमान सरकार : प्रमोद

● **अमित कुमार सिंह**

बिहार में सत्ताधारी गठबंधन अपराध और भ्रष्टाचार का पोषक बन चुकी है लगातार बिहार का आपराधिक ग्राफ बढ़ रहा है जो सर्वविदित है प्रतिदिन दैनिक समाचार पत्रों के पन्नों पर अपराधिक घटनाएं सुर्खियां बन रही हैं विकास कार्यों के लिए सरकार का खजाना खाली हो चुका है कर्मचारियों का वेतन समय पर भुगतान करने में वर्तमान बिहार सरकार असफल साबित हो रही है बिहार और बिहारियों को 25 वर्ष पीछे धकेलने का काम सुशासन बाबू ने कर दिया है उक्त बातें अतिपिछड़ा आयोग के पूर्व सदस्य प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने दिल्ली से सासाराम पहुंच अमरा तालाब में आयोजित बैठक के संबोधन में कहीं। कार्यकर्ताओं ने सासाराम स्टेशन पर भव्य स्वागत करते हुए अमरा तालाब तक ले गये जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू की अति पिछड़ा विरोधी नीति का पर्दाफाश करने को लेकर अति पिछड़ी जाति के लोकप्रिय नेता प्रमोद चंद्रवंशी की मुहिम के तहत रोहतास एवं कैमूर जिले के चंद्रवंशी नोनिया प्रजापति सहित अन्य अति पिछड़ा वर्ग एवम शुभ चिंतकों की बैठक को संबोधित किया। आयोजित बैठक की अध्यक्षता रामसागर पंडित और संचालन संजीव मोहन ने किया । जेडीयू के दक्षिण बिहार के वरिष्ठ नेता एवम ओबरा से विधान सभा चुनाव चुनाव लडने वाले अति पिछड़ा वर्ग के लोकप्रिय नेता प्रमोद सिंह चंद्रवंशी का 2 अप्रैल को गृहमंत्री अमित शाह की सभा में बीजेपी मिलन समारोह की तैयारी एवं सफलता पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रमोद सिंह चंद्रवंशी ने नीतीश कुमार को अति पिछड़ा विरोधी बताया और कहा कि हमने पार्टी 30 वर्षो से सींचा और अति पिछड़ा के मान् सम्मान भी दिलाया लेकिन

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में नीतीश कुमार के एडेंजा से अति पिछड़ा बाहर हो चुका हैं। रोज अति पिछड़ा वर्ग की हकमारी हो रही है। हत्या एवं बलात्कार हो

रहा है और अपराधियों के विरूद्ध कारवाई को लेकर अतिपिछड़ी नेताओं की मांग को लगातार दरकिनार किये जा रहा है। पहले हम पूरे बिहार के अति पिछड़ा को हक दिलाते रहते थे। लेकिन आज कुछ नही कर पा रहे है। आज सड़क पर आकर बीजेपी के झंडे तले लड़ने की जरूरत है जिसके लिए प्रमोद चंद्रवंशी ने जेडीयू से इस्तीफा दिया है उक्त बातें प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने स्वयं बैठक के संबोधन में कहते हुए भारत के प्रथम ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथो को मजबूत करने का निर्णय लिया है। श्री चंद्रवंशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अति पिछड़ा वर्ग का सच्चे हितैषी बताकर रोहणी कमीशन के रिपोर्ट जल्द लागू करने के लिए भाजपा को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने दुखद शब्दों में अपने भाई के हत्यारों को भी सजा दिलाने में असमर्थ बताते हुए वर्तमान की सत्ताधारी गठबंधन को अपराधियों का संरक्षक बताया। इस बैठक में पूर्व प्रमुख रामकुमारी देवी, मंगल चंद्रवंशी, विजयकांत सिंह, गोलू चंद्रवंशी, चंदन चंद्रवंशी, गुड्डू चंद्रवंशी, उदय सिंह मोहन चौधरी, केशव चौधरी, सासाराम के प्रमुख प्रतिनिधि प्रकाश कुमार, संजीव मोहन, राघवेंद्र सिंह, पन्ना लाल स्वर्णकार, पप्पू कुमार, सुनील प्रजापति इत्यादि लोगो ने संबोधित करते हुए प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी के हाथ मजबूत करने के लिए भारी संख्या में 2 अप्रैल को सासाराम रेलवे मैदान में आने का संकल्प लिया। ●

सीएम ने जदयू को रख दिया गिरवी : उपेन्द्र कुशवाहा

● मिथिलेश कुमार

जदयू से बगावत कर राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी का गठन करने के बाद विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा शुक्रवार को कौआकोल के सोखोदेवरा गांव पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने जेपी आश्रम अवस्थित लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद सोखोदेवरा गांव में उपस्थित विशाल जनसभा को सम्बोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की वर्तमान सरकार खासकर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह विरासत बचाओ नमन यात्रा है। हम उस विरासत की बात करने आए हैं। जिस विरासत को आगे ले चलने का दायित्व बिहार भर के लोगों ने 2005 में बड़ी कुर्बानी देकर बड़ा संघर्ष करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा था। साल 2005 से पहले बिहार को बदनाम और बर्बाद करने वाली ताकत राज्य में सक्रिय हो गई। उन्हीं का विरोध कर के नीतीश कुमार सत्ता में आए और फिर वापस उन्हीं से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। बिहार को फिर बर्बाद करने की कगार पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। यही कारण हैं कि सीएम नीतीश ने एक एक कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सींचे हुए पार्टी जदयू आज बिहार में भ्रष्टाचार की जननी राजद पार्टी के हाथों गिरवीं रख दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम उस विरासत को ही बचाने के लिए निकले हैं। हम बिहार को बचाने के लिए निकले हैं, जो कि बिहार की जनता के सहयोग से ही संभव होगा। यहां हम जेपी का आशीर्वाद लेने आए हैं। जनता की ताकत बड़ी होती है,किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं। नीतीश कुमार ने खुद ही आरजेडी को हर चीज सौंपने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा से लैस जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो विरासत थी,उस विरासत को बचाने के लिए ही 90 के दशक में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन लालू प्रसाद ने अपनी ताकत का इस्तेमाल

आम जनों के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए किया। जिसकी दुर्गति वह भुगत रहे हैं। समाजवादी विचारों के कारण ही लालू प्रसाद के राजद शासनकाल के बाद लोगों ने नीतीश कुमार पर अपना भरोसा जताया। लेकिन राजनीति के अंतिम समय में नीतीश कुमार के निर्णय से लोग दहशत में हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का पहले का कार्यकाल काफी अच्छा रहा,लेकिन अंतिम समय में लिए गए फैसले से जनता भयभीत और दहशत में है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब आरजेडी सरकार में गठबंधन में है,तब बिहार में फिर से कानून व्यवस्था का भयावह मंजर दिखने लगा है। यह हाल तब क्या होगा,जब नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। नीतीश के साथ रहने वालों का क्या हश्र होगा? वह झलक अभी से ही दिख रही है। मौके पर पूर्व विधायक रणवीर सिंह, रमेश कुशवाहा, इंद्रदेव कुशवाहा, विनय महतो, राजेन्द्र कुशवाहा, मुसाफिर कुशवाहा, अनिल कुमार सिंह, डॉ० बीपीन कुमार आदि मौजूद थे।●

स्कूल के स्थापना दिवस पर बच्चों की प्रस्तुति

नवादा नगर के पटवासराय स्थित जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में विद्यालय के बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति से बच्चों ने उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया।समारोह का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंध निदेशक आर पी साहू एमडी निहारिका रानी एवं निदेशक रश्मि गुप्ता एवं इंजीनियर ऋषव ने दीप प्रज्वलित कर किया।इस अवसर पर बच्चों ने एकल गायन,समूह गायन,समूह नृत्य,लघु नाटक एवं कई झांकी प्रस्तुत किया। बच्चों ने अपने भाषण के माध्यम से कई बिंदुओं पर चर्चा किया। प्रबंध निदेशक आरपी साहू ने कहा कि विद्यालय में अध्ययन कर रहे सफल बच्चे ही हमारी पूंजी है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन हमेशा अभिभावकों के विश्वास और भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करता है और इसमें हमलोग सफल भी हुए है। प्रतिस्पर्धा के दौर में विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर शैक्षणिक माहौल में बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के निर्माण की जिम्मेवारी का निर्वहन विद्यालय प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षकों ,शिक्षिकाओं एवं छात्र-छात्राओं का योगदान भी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है।विद्यालय में बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रस्तुत किया।जिसमें सामाजिक कुरीतियों को हटाने एवं शिक्षा, पर्यावरण की रक्षा करने का भी संकल्प की झलक मौजूद थी। समारोह का संचालन श्रवण वर्णवाल एवं स्कूल के छात्रों ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ अभिकर्ता मनोज कुमार,प्राचार्य शैलेन्द्र सिन्हा, उप प्राचार्य कीर्ति नारायण सहित सैकड़ों की संख्या में अभिभावक मौजूद थे। **रिपोर्ट :- सन्दीप कुमार**

डीईओ ने उर्दू शिक्षक का वेतन किया बंद

● मिथिलेश कुमार

वैसे तो सूबे में फर्जी शिक्षकों की फौज है। उच्च न्यायालय के द्वारा फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच और नियोजन से सबंधित सभी कागजातों का फोल्डर जमा करने का आदेश देने के बाद भी बिहार में करीब 60 हजार से अधिक शिक्षकों का फोल्डर नही जमा हो पाया है। इससे प्रतीत होता है शिक्षक बहाली के खेल में पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने दोनों हाथ से लूट कर शिक्षक नियोजन किया है।ऐसा ही मामले में नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखण्ड स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक मो० कलीम उद्दीन का वेतन जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने अगले आदेश तक बंद कर दिया है। शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 545 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा दिये गए आदेश में मो0 कलीम उद्दीन को अपने शैक्षणिक

प्रशिक्षणिक सभी प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी को जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। क्षेत्रीय विकास अधिकारी मगध प्रमंडल के पत्रांक 56 के अनुसार शिक्षक मो0 कलीम के प्रमाण पत्रों की जांच करने के लिए मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आदेश कई बार दिया गया परन्तु शिक्षक के द्वारा वांछित कागजातों को प्रस्तुत नही किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आखिरकार शिक्षक का वेतन अगले आदेश तक बंद करने का पत्र जारी किया है।बता दें कि आर टी आई के माध्यम से अरविंद मिश्रा द्वारा शिक्षक के प्रमाण पत्रों की मांग की गई थी। दिए गए सूचना में जो प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए थे वह जाली प्रतीत होता है। अरविंद मिश्रा ने मामले को लेकर प्रमंडल अधिकारी से जांच कराने का आग्रह किया था। दिए गए आवेदन के आलोक में कई गयी कार्रवाई के बाद शिक्षक कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही कर पाया जिससे प्रमाण पत्रों के जाली होने को बल मिलता है। जिले में सैकड़ो शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र पर अभी अभी नौकरी कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्रवाई के बाद फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।इंतजार इस बात का है कि अधिकारियों का हाथ फर्जी शिक्षकों के सर पर कब तक रहता है। ●

सम्राट अशोक की मनायी गई जयंती

● मिथिलेश कुमार

नवादा जिला कुशवाहा सेवा समिति के प्रधान कार्यालय में आयोजित विश्व विजेता सम्राट अशोक महान की जयंती संगठन के अध्यक्ष महेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर सम्राट अशोक महान के चित्र पर पुष्प समर्पित कर उन्हें नमन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सम्राट अशोक महान अखंड भारत के चक्रवती सम्राट अशोक अखाण्ड भारत के निर्माता। भारत वर्ष के राष्ट्रनायक, वसुधैव कुटुम्बकम् के जनक, महान मानवतावादी एवं जनमानस के दिलों पर राज करने वाले विश्व विजेता थे। अशोक ने भारत को विश्वव्यापी प्रतिष्ठा दिलायी, जिसकी छाप आज तक सम्पूर्ण विश्व में, दिखाई पड़ती है। सम्राट अशोक ने कुछ बुद्ध के विचारों को पूरी दुनिया में फैलाया। भारत उस जमाने का सबसे विकसित भारत था । हर क्षेत्र में भारत ने तरक्की की थीं। यही नहीं मानवता के प्रति उन्होंने जो अपना रुख अपनाया उसकी वजह से उन्होंने दुनिया के दिलों को जीत लिया। इसलिए हृदय सम्राट कहलाये उनके इसी नीति का आशय फिल्म पूरब पश्चिम के एक गीत में दर्शाया गया है! 'जीते हों किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है' में कर सकता हूँ कि हिंसा के बल पर राज करने वाले, इतिहास के पन्नों में 10 राजे महराजे मिल जायेंगे। लेकिन अहिंसा केबल पर राज करने वाला इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक ही मिलेगा। वह सम्राट अशोक महान ही मिलेगें । अशोक ने भारत को समूह के रूप में वैभवशाली एवं शक्तिशाली भारत बनाया अर्थात भारत को सोने की चिडिया बनाया हृदय की गहराईयों से आज इनके चरणों में नमन किया। वक्ताओं ने सम्राट अशोक जयंती को धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया। मौके पर रामचन्द्र सोनी, अर्जुन कुशवाहा, डॉ० भोला प्रसाद कुशवाहा, पूर्व मुखिया सुंदर प्रसाद, अरुनजय मेहता, बसन्त कुमार, संजय कुमार, प्रमोद कुमार, जॉनसन, डॉ० मनोज कुमार, ललिता कुमारी, शिक्षिका बबिता कुमारी, सुरुचि कुमारी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। ●

गीत, संगीत एवं नृत्य में मगध की शान हैं कुमकुम

● कृष्णा कुमार चंचल/मनीष कमलिया

वर्तमान में जीते हुए अतीत को स्मरण करना उलझन से भरा होता है। लेकिन, बहुत बार अतीत को याद करना सुखद अनुभूतियों से भरा होता है। बात 1980 की है जब बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी नेता एवं पूर्व मंत्री कपिल देव प्रसाद सिंह बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हुए। इसी बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में शेखपुरा विधानसभा भी पड़ता था। कपिल देव बाबू का हस्तलिखित पत्र मुझे मिला जिसमें उन्होंने शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर चुनाव प्रभारी के रूप में काम करने का आग्रह था। इस संदर्भ में 1980 के आस पास मेरा एक लेख दैनिक अखबारों में 'मैं जब चुनाव प्रभारी बना' शीर्षक से लेख प्रकाशित हुआ था। इस कारण यह बात विस्तार से लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है। शेखपुरा शहर में राजो बाबू के भय के कारण कोई कार्यालय के लिये भवन नहीं मिला। प्याज के गोलेदार ने मुझ से आग्रह किया कि हुसैनाबाद में आप मेरे गोदाम को कार्यालय के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कपिल देव बाबू ने एक गाड़ी और 3000 रूपया प्रदान किया, मैं हुसैनाबाद आ गया।

बालपन से हुसैनाबाद के नवाब के संदर्भ में एक किस्सा सुनता आ रहा था कि हुसैनाबाद के नवाब मंजूर हसन शाम में अपने अधिनस्थ काम करने वाले जिसको 'अमला' बोला जाता था से पूछा कि "शाम होते ही कौन हल्ला करता है।" अमलाओं ने कहा कि "हुजूर, ठंड के कारण सियार हुआ हुआ करता है" तब नवाब ने कहा "इन सबों के लिए गर्म कपड़े भेज दो", अमलों ने कहा भेज देता हूं लेकिन फिर शाम होते ही सियार हुआ हुआ करने लगा तब नवाब ने पूछा "आखिर अब क्यों हुआ हुआ करता है?" तब अमलों ने जवाब दिया कि "ये सब दुआ दुआ करता है, आपको बधाई दे रहा है।" जब हुसैनाबाद आया तब एक विशाल, भव्य और कलात्मक मस्जिद देखा और एक गहरे तालाब के चारों तरफ भवनों के टूटे-फूटे रूप को भी देखा। कुछ भवन सुंदर और सुरक्षित भी थे, उसमें पुआल बिछा दिया गया और आने-जाने वाले कार्यकर्ता उसी में सोने लगे थे। आसपास में पुराने ढंग के कई मकान थे। उस मकान में रहने वालों ने भी कहा कि हम सब भी नवाब जी के परिवार के ही हैं। मंजूर हसन की पत्नी खुर्शीद बानो की पुत्री जैबुनिशां जो कुमकुम नाम से प्रसिद्ध हुई बालीवुड अभिनेत्री इसी गांव से थी। कुमकुम 15 वर्ष की आयु में हुसैनाबाद छोड़कर अपने पिता और मां के साथ कोलकत्ता चली गई। लेकिन कोलकत्ते में मंजर हसन ने दुसरी शादी कर ली, विवाद होने पर खुर्शीद बानों अपनी पुत्री के साथ लखनऊ आ गई। उधर उसके पिता मंजूर हसन अपनी नई पत्नी के साथ पाकिस्तान चले गए।

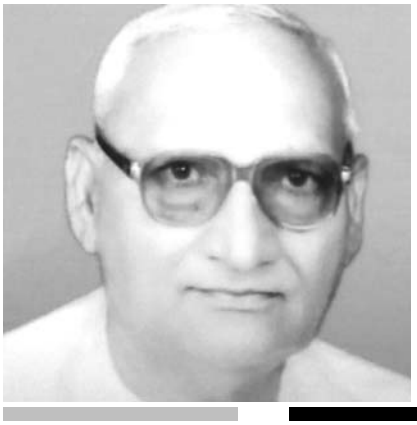

खुर्शीद बानों अपनी पुत्री कुमकुम में नृत्य के प्रति झुकाव देखकर बनारस के रहने वाले शंभू महाराज के पास कथक नृत्य सीखने के लिए भेजी। कुमकुम कुछ दिनों में ही गीत संगीत में निपुण हो गई और मां के आदेश पाकर शमसेद आलम जो लखनऊ के रहने वाले थे और बंबई में बस गए थे के पास भेज दी। कुछ दिनों तक कई फिल्मों में छोटे आकार की भूमिका मिली, लेकिन गुरु दत्त की फिल्म 'आर-पार' में शीर्षक के अनुसार के गीत गाकर कुमकुम की पहचान बढ़ी और फिर देश के कई मान्य बड़े कलाकारों के संग काम करने का मौका मिला। खासकर मदर इंडिया में इनके गीत और नृत्य को बहुत सराहा गया। आज भी पुराने फिल्मी गाने सुनने वालों के लिए ग्रामीण परिवेश में कुमकुम के गीत "...घुंघट नहीं खोलूंगी सैंया तोरे आगे.." कालजयी गीत के रूप में सुना जाता है। भोजपुरी फिल्म गंगा मैयया तोरे पियरी चढैवो में मगही शब्दों की भरमार है। यह फिल्म आकर्षक और कर्णप्रिय बनाने में कुमकुम का बड़ा योगदान है। 1975 में कुमकुम की शादी लखनऊ निवासी सज्जाद अकबर खान के साथ हो गई और वह अपने पति के साथ अरब देश चली गई लेकिन भारत के प्रति कुमकुम के मन में प्यार था। 1995 में लौटकर भारत आई और अपने परिवार के साथ मुंबई में रहने लगी। 28 जुलाई 2020 को देह त्याग किया लेकिन कुमकुम के नृत्य, गीत और संगीत का जादू आज भी कायम है।

मगध के प्रबुद्ध जन, कला और साहित्य से जुड़े हुए लोग आज भी स्मरण करते हैं मगध की उस बेटी को जिसने कला के क्षेत्र में मगध का गर्व बढ़ाया है। नमस्कार है! ●

अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों का परिचालन बदस्तूर जारी

● धर्मेन्द्र सिंह

किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत पौआखाली मिरभिट्टा से होकर बहने वाली बूढ़ी कनकई नदी मिरभिट्टा से अहले सुबह से ही अवैध खनन कर कई ट्रैक्टरों के माध्यम से ले जाया जाता है। सरकारी विद्यालय के महज कुछ ही दूरी से अवैध खनन कर बालू माफिया अपना जेब गर्म कर रहे हैं। गौरतलब हो कि बरसात के मौसम में जब उक्त नदी उफान पर रहती है तब आस पास के गांव इससे प्रभावित रहता है। गौर करे कि सुचना के आधार पर लगातार खनन विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में शामिल वाहनों को जप्त कर फाइन भी किया जाता है। इसके बावजूद अवैध खनन पर विराम नहीं लग रहा है। वही ओवरलोड वाहनों का परिचालन भी धड़ल्ले से जारी है। ठाकुरगंज-बहादुरगंज रूट होकर सुबह से ही ओवरलोड डम्पर का परिचालन शुरू हो जाता है। ओवरलोड वाहनों के परिचालन से क्षेत्र की सड़कें खराब होने लगी हैं इसके बावजूद भी ओवरलोड वाहनों का परिचालन थमने का नाम नहीं ले रहा है। गौर करे कि ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध पूर्व में कार्रवाई करते हुए ओवरलोड वाहनों पर फाइन किया गया इसके बावजूद भी लगातार ओवरलोड वाहनों का परिचालन बदस्तूर जारी है। यह कहना उचित होगा कि डायमंड कोड का असर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। डायमंड कोड के सहारे ओवरलोड वाहन किसी भी रूट में जाती है और उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है तभी तो खुलेआम ओवरलोड वाहनों का परिचालन बदस्तूर जारी है। वक्त रहते अगर ओवरलोड वाहनों और अवैध खनन को नहीं रोका गया तो सरकारी राजस्व को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

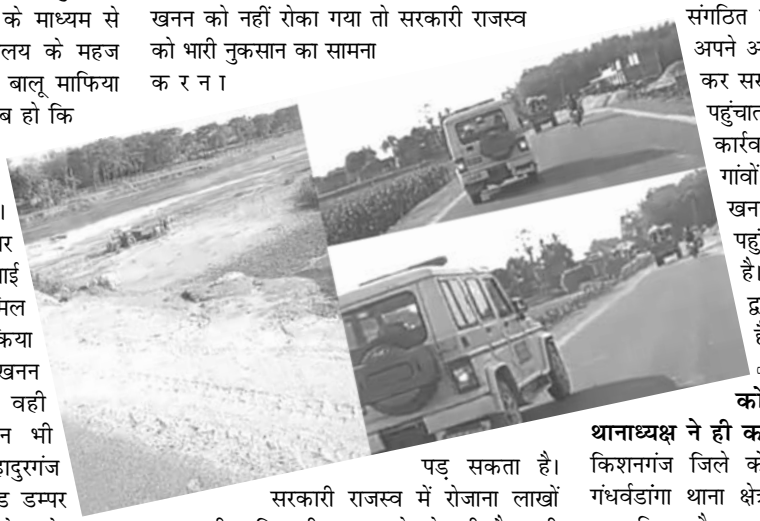

सरकारी राजस्व में रोजाना लाखों रुपए की क्षति इसी कारण से हो रही है। वही खान निरीक्षक उमाशंकर सिंह ने दो दिन पूर्व अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करते हुए एक पोकलेन मशीन व एक मिट्टी लोड ट्रैक्टर को जब्त किया था। कार्रवाई तलीभिट्टा कनकई नदी में की गई। खान निरीक्षक उमाशंकर सिंह ने बताया कि कोचाधामन थाना क्षेत्र के काशीबाड़ी के समीप से एक बालू लोड ट्रैक्टर व पौआखाली थाना क्षेत्र के तेलिभिट्टा कनकई नदी में अवैध रूप से खनन कर रहे एक पोकलेन मशीन को जब्त किया गया था। जब्त दोनों गाड़ियों को पौआखाली थाना के सुपुर्द किया गया। फिर भी खनन माफिया बाज नही आ रहे। गौर करे कि जिले में अवैध खनन करने वालों का कई संगठित गिरोह काम कर रहा है जो अपने अपने क्षेत्र में चोरी छिपे खनन कर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाता है। सूचना मिलने पर विभाग कार्रवाई करती है लेकिन सुदूर गांवों में नदी के किनारे अवैध खनन की सूचना विभाग तक पहुंचने में भी कई बार देर होती है। स्थानीय स्तर पर दबंगों के द्वारा अमूमन खनन किया जाता है।

☞ **जप्ती के बाद ट्रैक्टर को बांड बनाकर छोड़ा, थानाध्यक्ष ने ही कर दी खनिज की जांच :-** किशनगंज जिले के दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत गंधर्वडांगा थाना क्षेत्र के डोरिया पुल के नीचे आए दिन अवैध खनन के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। जिसकी सूचना खनन विभाग को पूर्व में दी गई है। रविवार दो अप्रैल को गंधर्वडांगा थाना पुलिस ने डोरिया पुल के नीचे से अवैध खनन करते हुए ट्रैक्टर को जप्त किया। जिसके बाद जप्त किए गए ट्रैक्टर को पुलिस द्वारा थाना लाया गया। फिर बांड बनाकर छोड़ दिया गया। जब मामले की तहकीकात की गई तब पता चला कि

डोरिया पुल के नीचे से नदी बहती है जिससे बालू का अवैध खनन किया जाता है वहीं आसपास के ग्रामीणों ने ट्रैक्टर जप्ती की वीडियो बनाकर भेजी। जिसमें देखा जा रहा है कि नदी से ट्रैक्टर की जप्ती की गई है। और आगे-आगे जप्त किए गए ट्रैक्टर चल रहे हैं और पीछे से पुलिस वाहन। इस संबंध में गंधर्वडांगा थानाध्यक्ष राम लखन पूछने पर उन्होंने कहा कि असलियत बात यह है कि उसका जमीन नदी में बढ़ गया है और ट्रैक्टर में बालू नहीं मिट्टी था जिसको लेकर बांड बनाया गया फिर ट्रैक्टर को छोड़ दिया गया। अब यह सवाल उठता है कि खनिज की जांच कौन करता है।

☞ **जिला परिवहन टास्क फोर्स की बैठक संपन्न :-** किशनगंज जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स और परिवहन टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में गुरुवार को आयोजित की गयी। बैठक में डीएम द्वारा 2023-24 में राजस्व संग्रह के लिए एजेंडावार समीक्षा की गई। जिलांतर्गत सभी बालूघाट बंदोबस्त, बालू घाट पर घर्मकांटा उपलब्धता, बालू परिवहन, अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, ईट भट्ठा संचालन, जांच, अवैध संचालकों पर कार्रवाई , रॉयल्टी संग्रहण, माइनिंग ईनफोर्समेंट हेतु वन के अधिकारियों से समन्वय आदि के बिन्दु पर गहन समीक्षा हुई। प्रभारी खनिज विकास पदाधिकारी और खान निरीक्षक को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लगातार क्षेत्र भ्रमण कर अवैध खनन के विरुद्ध छापामारी करें तथा विभागीय पत्र के आलोक में कार्य करना सुनिश्चित करें। ओवरलोडिंग के विरुद्ध डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि वाहनों की जब्ती, शमन की कार्रवाई अवश्य करें। बालू घाट बंदोबस्ती हेतु नीलामी की कार्रवाई, खनन राजस्व संग्रहण, अवैध इट-भट्ठा पर नियमानुसार कार्रवाई की समीक्षा की गई। डीएम ने निर्देश दिया कि खनन कार्य विभागीय प्रावधान के अनुसार ही बंद और चालू रहे, इसे सुनिश्चित करवाएं। जिला खनन कोष (डीएमएफ) से नियमानुसार व्यय करना, घाट का खनन प्लान तैयार करना सुनिश्चित करें। डीएम ने निर्देश दिया कि वैद्य तरीके से एवं स-समय रॉयल्टी भुगतान कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह का कठिनाई का सामना ना करना पड़े तथा सभी कार्य विभाग को एतद निर्देश दिए गए है। जिला परिवहन टास्क फोर्स के कार्यो की समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी अभिनय भास्कर ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में निधरित लक्ष्य के विरुद्ध 89% रहा। इस वित्तीय वर्ष में अधिकाधिक राजस्व संग्रहण हेतु कार्य किया जाएगा। नियम विरुद्ध वाहन परिचालन करने वाले वाहन से शमन राशि भी वसूल की जाती है। जिला परिवहन विभाग के कार्यो और उपलब्धि की समीक्षा किया गया, जो संतोषप्रद रहा। जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सघन छापामारी, चेकिंग का निर्देश दिया गया। इस बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी अभिनय भास्कर, जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के पदाधिकारी यथा खान निरीक्षक एवं इससे संबंधित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।●

केवल सच पत्रिका में छपी खबर का हुआ असर

बालू की अवैध खनन पर खूब गरजे डॉ दिलीप कुमार जायसवाल

किशनगंज मेडिकल कॉलेज के निर्देशक सह विधान पार्षद डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने सदन में अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग सदन में की है। विधान पार्षद डॉ जायसवाल ने कहा है कि अवैध खनन हो रहा है जनता को भी बालू का इतना किल्लत और दिक्कत हो रहा है कि आज अगर कोई गरीब आदमी या मध्यम वर्ग आदमी घर बनाना चाहता है तो उसको बालू नहीं सोना खरीदना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन का दो साल से क्यों बंदोबस्ती रुका हुआ है। 102 लोग पर प्राथमिकी किया है और करीब 300 लोगों को इन्होंने पकड़ा है। यह तो समाहर्ता और सरकार इस बात को कबूल कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं आखिर कानून का राज कहां पर है। अवैध खनन आरा से छपरा जो नया पुल बना है 4 घंटा लगेगा जाने में, हजारों ट्रक अवैध खनन वाला बालू रोड पर पड़ा हुआ है और इतनी बड़ी वसूली हो रही है। उस क्षेत्र के पदाधिकारियों के यहां छापेमारी व जांच किया जाए तो करोड़ों करोड़ का मामला बन रहा है। मंत्री से उन्होंने कहा कि सीधा इस पर कार्यवाही करें अगर आपको 102 को प्राथमिकी दर्ज करना पड़ रहा है। इसका मतलब सोच सकते हैं कि कितने लोग अवैध खनन में लिप्त होंगे, दो साल से क्यों बंदोबस्ती रुका हुआ है। अवैध खनन वाले माफिया को आगे बढ़ाने के लिए। सभापति से मांग करते हुए कहा कि आप के माध्यम से मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यह जो माफिया का खेल चल रहा है बालू के अवैध खनन में आप इस पर रोक लगाए नहीं तो सरकार की बदनामी हो रही है। जनता को भी बालू का इतना किल्लत और दिक्कत हो रहा है कि आज अगर कोई गरीब आदमी घर बनाना चाहता है तो उसको बालू नहीं सोना खरीदना पड़ता है। इसलिए उसपर ध्यान दिया जाए।

जाति आधारित गणना से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम

डाटा डुप्लीकेसी ठीक करने का डीएम ने दिया निर्देश

● धर्मेन्द्र सिंह

बिहार जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण का कार्य 15 अप्रैल से 15 मई 2023 तक निर्धारित है। बिहार जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण का कार्य अच्छे ढंग से संपन्न हो, इसे लेकर मास्टर ट्रेनर, फील्ड मास्टर ट्रेनर एवं प्रखंड के वरीय पदाधिकारी को अपने-अपने नामित प्रखंडों में भेजकर प्रखंडों, नगर निकायों के प्रगणकों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री ने ठाकुरगंज चार्ज का भ्रमण कर उच्च विद्यालय ठाकुरगंज में आयोजित प्रशिक्षण का जायजा लिया है। प्रशिक्षण के दौरान छोटी मोटी जो भी समस्याएं अवगत कराई गई, उसे ऑन द स्पॉट निराकरण कराया गया ताकि द्वितीय फेज के दौरान घर-घर गणना करने जाने के दौरान कोई त्रुटि ना रहे। गौरतलब हो कि 03 अप्रैल को जिलाधिकारी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जातीय गणना के द्वितीय चरण से संबंधित तैयारी की जानकारी बारी-बारी से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर निकाय के पदाधिकारियों तथा प्रखंड के नामित जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी से जानकारी ली गई थी। ठाकुरगंज के प्रशिक्षण सत्र का मुआयना के उपरांत डीएम ने कहा कि इस चरण में प्रत्येक परिवार, व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक आंकड़े प्रपत्र और मोबाइल ऐप दोनों के माध्यम से एकत्रित किये जायेंगे। गणना प्रपत्र में परिवार से आंकड़े लेकर उस परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर प्राप्त करने के उपरांत सभी आंकड़े मोबाईल एप में प्रविष्ट किये जायेंगे। मोबाईल ऐप से यह आंकड़ा स्टेट डाटा सेंटर के सर्वर पर एकत्रित होगा, जो बिहार जाति आधारित गणना पोर्टल पर देखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्राप्त आंकड़ों का प्रसंस्करण और प्रतिवेदन/ग्राफ, विवरणी आदि का निर्माण भी इसी पोर्टल से होगा। गणना प्रपत्र और मोबाईल ऐप पर प्रत्येक परिवार के लिए एक ही क्रमांक होंगे। गणना के बाद सभी प्रपत्र को स्कैन कर मोबाईल के आंकड़े से टैग कर सॉफ्ट कॉपी में रख लिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण (जो 15 अप्रैल से 15 मई तक की जानी है) का प्रशिक्षण सभी चार्ज अंतर्गत बैचवार दिया जा रहा है,जो 10 अप्रैल तक संपन्न कर लिया जाएगा। सभी प्रखंड और नगर निकाय में चार्ज के पदाधिकारियों, मास्टर ट्रेनर की उपस्थिति में सभी चार्ज पदाधिकारी, फील्ड ट्रेनर तथा आई०टी० सहायक द्वारा भाग लिया गया हैं। प्रशिक्षण में बिहार जाति आधारित गणना प्रपत्र की जानकारी दी गई। इस प्रपत्र में चार भाग है। लोकेशन कोड विवरणी गणना संकलन, कोड एवं विकल्प तथा परिवार के किसी सदस्य द्वारा घोषणा की जानकारी दी गई। प्रपत्र के भाग दो में कुल 17 प्रकार के प्रश्न है इसकी जानकारी प्रशिक्षण के समय दी गई। द्वितीय चरण में मोबाईल ऐप का भी उपयोग किया जाना है इससे संबंधित जानकारी भी आई०टी० प्रबंधक द्वारा दी गई। ठाकुरगंज में आयोजित प्रशिक्षण सत्र का अवलोकन उपरांत डीएम ने कहा कि सभी चार्ज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्रशिक्षण के बाद सभी प्रगणक को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हर हाल में दिलवाए। सभी प्रगणक को मोबाइल फ्रेंडली बनाने हेतु हैंड्स ऑन ट्रेनिंग काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एवं सामान्य जानकारी की वीडियो उपलब्ध कराया गया है, जो सभी सुपरवाइजर तथा प्रगणक तक हर हाल में शेयर करें ताकि वीडियो तथा प्रेजेंटेशन देखकर, पढ़कर भी प्रशिक्षित हो सकते हैं। उपलब्ध कराए गए वीडियो को देखकर स्टेपवार समझने में काफी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार का एक से अधिक जगह पर डाटा एंट्री या गणना हो गया है, उस स्थिति में ऐप के माध्यम से डुप्लीकेसी को डिलीट करवाया जाएगा। इसके लिए ऐप में यह फंक्शन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अनुदेश पुस्तिका, विभिन्न प्रकार के दिए गए पांच प्रपत्र तथा अन्य प्रशिक्षण मटेरियल को हर हाल में अच्छे तरीके से पढ़ ले ताकि फील्ड में जाने के दौरान काफी सहूलियत मिलेगी। त्रुटि रहित गणना सुनिश्चित करें। इसमें लापरवाही अक्षम्य है। प्रथम फेज की गणना में डाटा में जो त्रुटि है उसे तुरंत सुधार लें और डाटा डुप्लीकेसी को रोकें। सभी प्रखंड में जातीय गणना का प्रशिक्षण जारी है। ●